अक्टूबर 2020 ■ ₹ 30

सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका

समसामयिकी क्रॉनिकल

- निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 रिपोर्ट
- वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025
- 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' मंच
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल
- राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020
- डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020
- एनसीसी विस्तार योजना

इन्हें भी जानें

पत्र-पत्रिका संपादकीय

संस्थान-संगठन

समसामयिक प्रश्न

लोक सभा-राज्य सभा प्रश्नोत्तर सार

24 वर्षों से

आपकी सफलता का मार्गदर्शक

सर्वोत्तम ज्ञान का संदर्भ-कोष

भारत सरकार की पहल व विकास से जुड़ी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, रिपोर्ट, समिति, सूचकांक, अधिनियम, संशोधन एवं संगठन

मुख्य आकर्षण

- सामाजिक विकास
- विनिर्माण क्षेत्र
- शिक्षा
- कृषि
- ऊर्जा
- सुरक्षा
- सेवा क्षेत्र
- परिवहन
- पर्यावरण
- भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन
- समकालीन अर्थव्यवस्था
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत सार्वभौमिक विश्व का बाजीगर

- 350 लाख करोड़ की भारतीय अर्थव्यवस्था की पहल
- भारत के कूटनीतिक आयाम
- सामाजिक एकीकरण व समरसता
- भारत के निर्माण में मजबूत संस्थानों की भूमिका
- ए.आई.: मानव रहित विश्व
- भारत में वैज्ञानिक विकास
- सामाजिक न्याय के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण
- पर्यावरण सक्रियता

Cover Story

कोविड-19: व्यवधान, प्रावधान व प्रभाव

- एक जैविक आपदा के रूप में
- वायरस का पर्यावरण पर प्रभाव
- भारत में ग्रामीण जीवन व आजीविका पर प्रभाव
- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व समाधान
- महिलाओं पर प्रभाव
- नागरिक समाज की भूमिका
- स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा अध्यादेश
- भारत में चिकित्सा और संरचना
- मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
- आत्मनिर्भर भारत अभियान

CHRONICLE BOOKS

write us:

Also Available on
www.chronicleindia.in
amazon
flipkart.com

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Mob.: 9953007630, E-mail: circulation@chronicleindia.in

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा

2020 संस्करण

हल प्रश्न पत्र

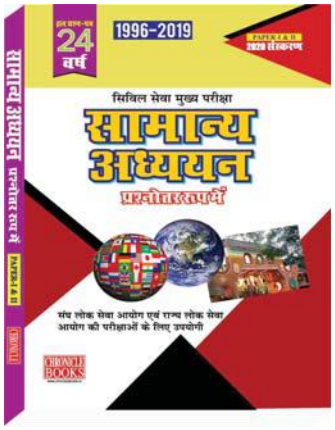

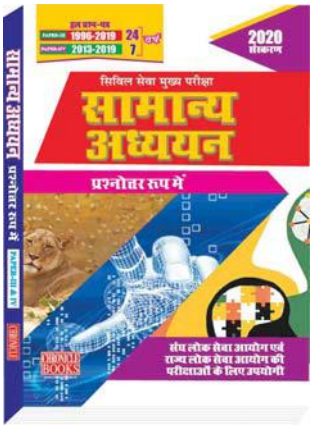

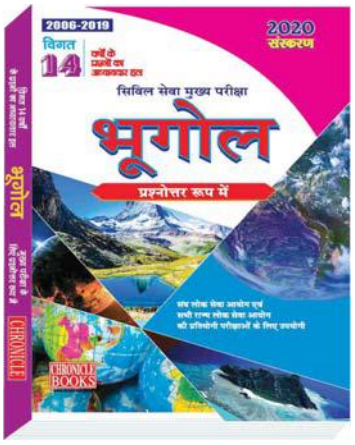

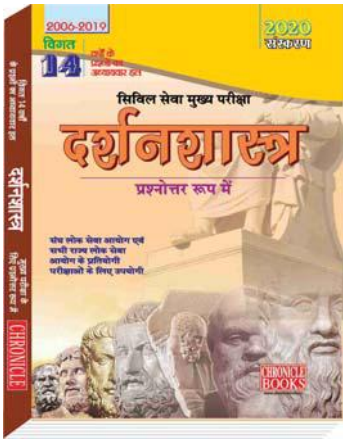

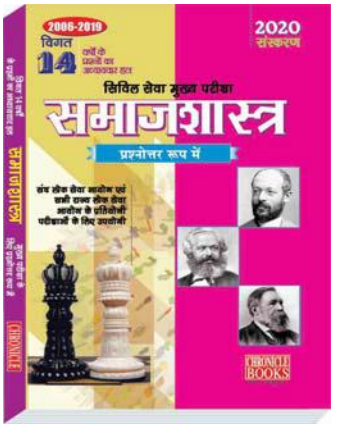

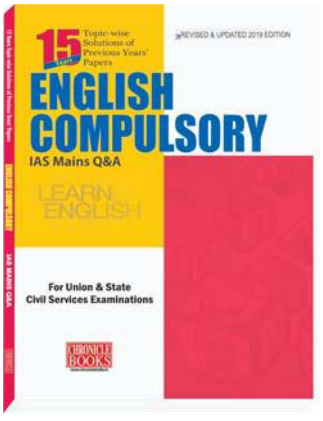

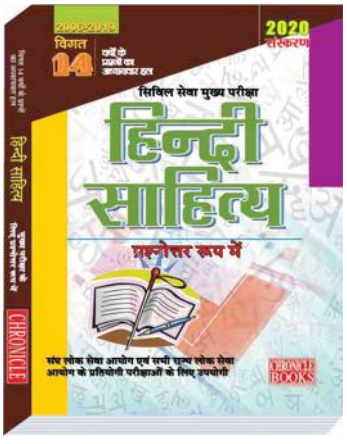

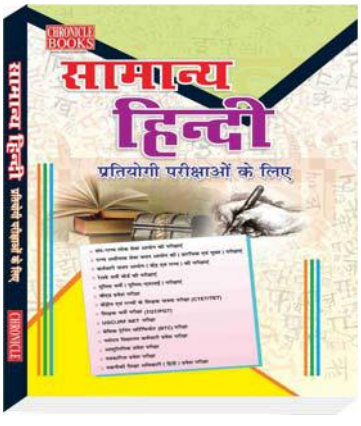

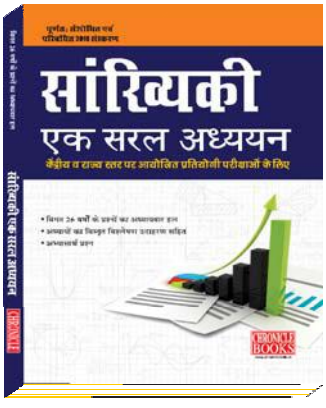

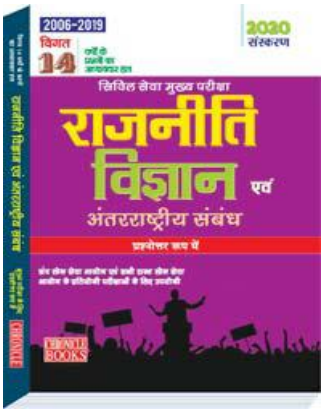

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon

flipkart.com

Contact us

CHRONICLE BOOKS

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514610/12, www.chronicleindia.in
E-mail: circulation@chronicleindia.in

टू द पॉइंट

NCERT Plus

6 भागों में

2020 संस्करण

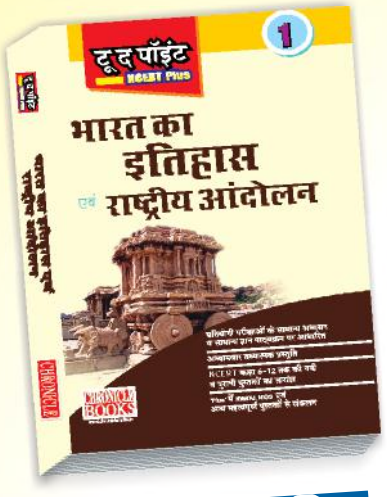

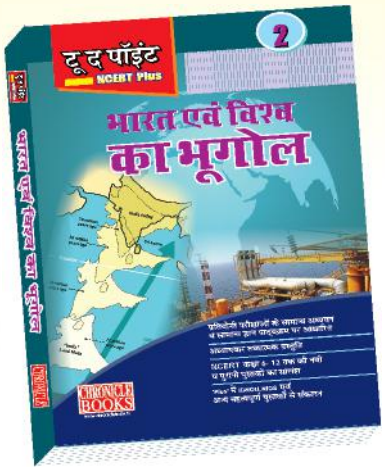

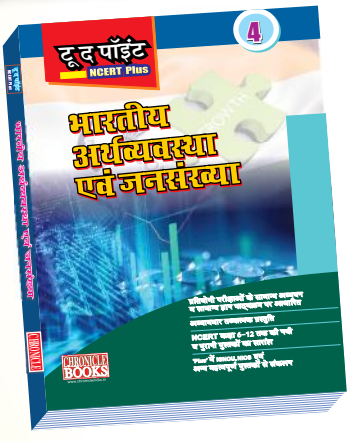

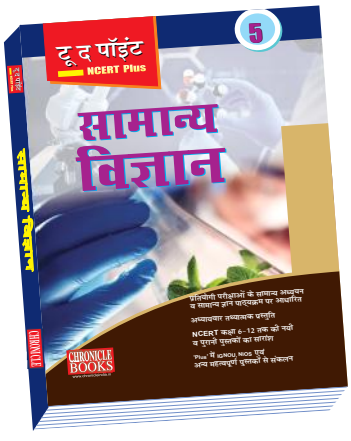

इस पुस्तक को टू द पॉइंट रूप में सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान (GK/GS) की प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर व NCERT की सामग्रियों को समाहित कर तैयार किया गया है। इसमें NCERT कक्षा 6-12 की नई व पुरानी पुस्तकों तथा IGNOU, NIOS, राज्य बोर्ड एवं अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तकों से सामग्री संकलित की गई है।

NCERT, IGNOU, NIOS व State Board द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान की आधारभूत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह पुस्तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ., कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा, बीएड, राज्य कर्मचारी चयन आयोग व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति व राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, ओलंपियाड के अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं व प्रवेश परीक्षाओं जैसे- CLAT, विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon

flipkart.com

CHRONICLE BOOKS

Corporate Office

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514610/12,Mob.: 9953007630
E-mail: circulation@chronicleindia.in, info@chronicleindia.in

आपकी सफलता का मार्गदर्शक

आईएएस तथा पीसीएस परीक्षाओं, यू.जी.सी. की जे.आर.एफ./नेट परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी

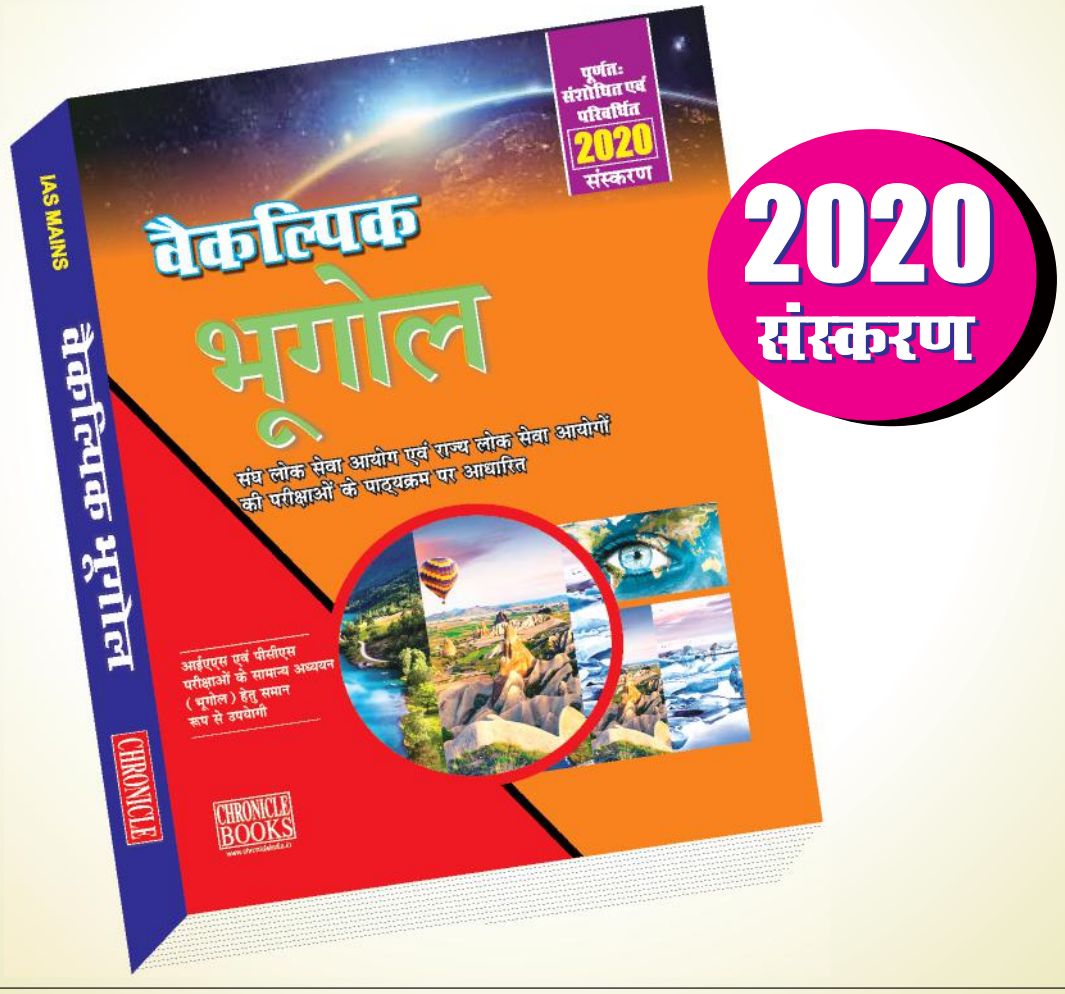

2020 संस्करण

Also Available on

www.chronicleindia.in

amazon

flipkart.com

Contact us

CHRONICLE BOOKS

A-27D, Sector-16, Noida, U.P.-201301
Ph.: 0120-2514611/12, www.chronicleindia.in
E-mail: circulation@chronicleindia.in

सभी परीक्षाओं को समर्पित प्रतियोगी पत्रिका

समसामयिकी क्रॉनिकल

अक्टूबर 2020 | वर्ष : 7 | अंक : 8

इस अंक में...

लोक सभा राज्य सभा प्रश्नोत्तर-सार 56

इन्हें भी जानें 57

07 आर्थिकी

- निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 रिपोर्ट
- राष्ट्रीय जीआईएस-सक्षम भूमि बैंक प्रणाली
- खुदरा भुगतान इकाई स्थापना हेतु रूपरेखा जारी
- 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' योजना
- भारत की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट
- वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025
- 'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' मंच
- 'गन्ना और चीनी उद्योग' पर नीति आयोग कार्य बल रिपोर्ट

13 राष्ट्रीय

- 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण के प्रमुख अंश
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन
- अयोध्या राम मंदिर नागर वास्तुकला
- एससी-एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण मामला
- अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020
- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी
- एनसीसी विस्तार योजना

19 अंतरराष्ट्रीय

- अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित
- डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020
- ब्रिक्स नवाचार संचालन केंद्र
- तुर्की द्वारा काले सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज
- अरमको द्वारा चीन में तेलशोधक परिसर बनाने का समझौता स्थगित
- 43% से अधिक स्कूलों में नहीं साफ-सफाई की बुनियादी सुविधाएं
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल

23 विज्ञान-पर्यावरण

- राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020
- एस्ट्रोसैट दूरबीन द्वारा एक सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान-एशिया के लिए परिवहन पहल
- अटलांटिक महासागर में माइक्रोप्लास्टिक्स प्रदूषण
- डीआरडीओ प्रयोगशालाओं से संबंधित समिति
- भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर कड़ी शर्तें

29 BFSI

31 बिजनेस

32 राज्य

35 खेल

38 सार-संक्षेप

51 पत्र-पत्रिका संपादकीय

53 समसामयिक प्रश्न

55 संस्थान-संगठन

संपादक
एन.एन. ओझा

विज्ञापन
अध्यक्ष
संजीव नन्दक्योलियार
advt@chronicleindia.in
Ph. 9953007627

प्रसार
सहायक महाप्रबंधक
पंकज पांडेय
circulation@chronicleindia.in
Mob.: 9953007630
subscription@chronicleindia.in
Mob.: 0-9953007629

व्यावसायिक कार्यालय
क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27डी, सेक्टर-16
नोएडा-201301
फोन: 0120-2514611-12

सर्वाधिकार सुरक्षित (c) क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि. न्यायिक-क्षेत्र दिल्ली।
क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा. लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा**। द्वारा एच-31, प्रथम तल, ग्रीन पार्क एक्स. नयी दिल्ली - 110016, से प्रकाशित एवं रत्ना ऑफसेट, सी-101, ओखला फेस 2, नई दिल्ली, से मुद्रित। **संपादक. एन.एन.ओझा**

आर्थिकी

निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 रिपोर्ट

नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझीदारी में 26 अगस्त, 2020 को निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की।

उद्देश्यः भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करने के लिए चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः सूचकांक की संरचना में 4 स्तंभ- नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन तथा 11 उप स्तंभ-निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत संरचना, व्यवसाय वातावरण, अवसंरचना, परिवहन संपर्क, वित्त की सुविधा, निर्यात अवसंरचना, व्यापार सहायता, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण और विकास अनुकूलन शामिल हैं।

- अधिकांश भारतीय राज्यों ने निर्यात विविधीकरण, परिवहन संपर्क एवं अवसंरचना के उप स्तंभों में 50 प्रतिशत से अधिक के औसत स्कोर के साथ औसतन अच्छा प्रदर्शन किया है।
- छः तटीय राज्य शीर्ष दस रैंकिंग में शामिल हैं, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मजबूत सक्षमकारी और सुगमकारी कारकों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु क्रमशः शीर्ष तीन स्थानों पर काबिज हैं।
- भूमि से घिरे हुए राज्यों में, राजस्थान का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है।

जीके फैक्ट

✧ हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है, जिसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। केंद्र-शासित प्रदेशो में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसके बाद गोवा और चंडीगढ़ हैं।

राष्ट्रीय जीआईएस-सक्षम भूमि बैंक प्रणाली

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 27 अगस्त, 2020 को 'राष्ट्रीय जीआईएस-सक्षम भूमि बैंक प्रणाली' (national GIS-enabled land bank system) शुरू की।

उद्देश्यः निवेशकों को औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में रियलटाइम जानकारी प्राप्त करने में मदद करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः अभी छः राज्यों के लिए परियोजना लॉन्च की गई। यह अभी केवल प्रारम्भिक अवस्था (प्रोटोटाइप) में ही है और इसे भूमि की पहचान एवं खरीद का एक प्रभावी, पारदर्शी तंत्र बनाने के लिए राज्यों से मिले इनपुट के साथ और आगे विकसित किया जाएगा।

- यह प्रणाली औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) को राज्यों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के साथ एकीकृत करके विकसित की जा रही है।
- प्रणाली में लगभग 475,000 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 3,300 से अधिक औद्योगिक पार्कों का मानचित्रण किया गया है।
- इस प्रणाली में उपलब्ध और खाली भूखंडों, इलाके के सैटेलाइट व्यू और वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर 'हीट मैप' (ग्राफ में डेटा को रंगो के रूप में प्रदर्शित करना) की जानकारी शामिल है।

खुदरा भुगतान इकाई स्थापना हेतु रूपरेखा जारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 18 अगस्त, 2020 को खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अखिल भारतीय छत्र इकाई (umbrella entity) की स्थापना के लिए रूपरेखा जारी की।

उद्देश्यः भुगतान प्रणाली में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के दबदबे को कम करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः स्थापित की जाने वाली इकाई, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भारत में स्थापित कंपनी होगी। बाद में यह फैसला लिया जा सकता है, कि कंपनी लाभकारी होगी या धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी।

- यह इकाई, एटीएम, व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल PoS, आधार-आधारित भुगतान और विप्रेषण सेवाओं (Remittance services) में नए भुगतान प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी।
- उसे भागीदारी करने वाले बैंकों तथा गैर-बैंकों के लिए क्लियरिंग एवं निपटान प्रणाली संचालित करनी होंगी।
- नई इकाई की न्यूतनम चुकता पूंजी (Paid-up capital) 500 करोड़ रुपये होगी और इस पूंजी में किसी भी प्रवर्तक (Promoter)/प्रवर्तक समूह की 40% से अधिक हिस्सेदारी नहीं होगी।

- नई इकाई की स्थापना के लिए आवेदन करते समय प्रवर्तक के पास कम से कम 50 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी तथा उसे भुगतान प्रणाली का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

जीके फैक्ट

✧ अखिल भारतीय छत्र इकाई का गठन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत अधिकृत किया गया है।

'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' (One Sun, One World, One Grid) योजना के बारे में उल्लेख किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह विचार पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की पहली असेंबली के दौरान प्रस्तावित किया था।

- यह 'सूर्य कभी अस्त नहीं होता' की दृष्टि पर आधारित है अर्थात सूर्य किसी भी भौगोलिक स्थान पर, वैश्विक स्तर पर, किसी भी समय पर स्थिर है।
- यह महत्वाकांक्षी योजना 140 देशों को एक सार्वजनिक ग्रिड (Common grid) के माध्यम से जोड़ेगा जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- केंद्र में भारत के साथ, सौर स्पेक्ट्रम को आसानी से दो व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। सुदूर पूर्व, जिसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया आदि देश शामिल हैं, और सुदूर पश्चिम, जो मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र को कवर करेगा।
- योजना को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। चरण-1 सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को साझा करने के लिए पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रिड के साथ भारतीय ग्रिड को जोड़ेगा।
- चरण-2 नवीकरणीय स्रोतों के अफ्रीकी पूल के साथ पहले चरण के राष्ट्रों को जोड़ेगा। और चरण-3 वैश्विक देशों के परस्पर कनेक्शन का अंतिम चरण होगा।

भारत की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 अगस्त, 2020 को जारी अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून तिमाही) में भारत की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: देश की अर्थव्यवस्था में करीब चार दशक बाद पहली बार संकुचन (-23.9%) देखा गया। इसकी तुलना में पिछली तिमाही में जीडीपी में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। जबकि 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई।

- कृषि एकमात्र क्षेत्र था, जिसने 3.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की। अन्य सभी क्षेत्रों में संकुचन देखा गया।
- निर्माण में 50.3% की गिरावट; व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 47% की गिरावट; विनिर्माण 39.3% की गिरावट , जबकि खनन और उत्खनन में 23.3% की गिरावट दर्ज की गई।
- निजी खपत में 26.7% की गिरावट दर्ज की गई गई, जबकि निवेश, जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross fixed capital formation) से परिलक्षित होता है, में 47% की गिरावट दर्ज की गई। जबकि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में 16.4% की वृद्धि दर्ज की गई।

जीके फैक्ट

✧ अर्थव्यवस्था का अंतिम संकुचन 1979-80 में हुआ था, जब जीडीपी में 5.2% की गिरावट दर्ज की गई।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020 – 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 20 अगस्त, 2020 को 'वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2020-2025' (NSFE) जारी की गई।

उद्देश्य: आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाना।

प्रमुख कार्यनीतिक उद्देश्य: वित्तीय शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाना;

- सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना; वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने हेतु वित्तीय बाजारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना;
- क्रेडिट अनुशासन विकसित करना और सावधानी और सुरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना; तथा प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय शिक्षा के प्रसार हेतु '5C' (Content, Capacity, Community, Communication and Collaboration) दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश की गई है।

- स्कूलों, कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में पाठ्यक्रम सहित प्रासंगिक 'सामग्री' (Content) का विकास;
- वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में शामिल मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच 'क्षमता' (Capacity) विकास;
- समुचित 'संचार' (Communication) कार्यनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के लिए 'सामुदायिक' (Community) नेतृत्व वाले मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का लाभ उठाना;
- विभिन्न हितधारकों के बीच 'सहयोग' (Collaboration) को बढ़ाना।

जीके फैक्ट

✧ 2013 में वित्तीय शिक्षा के लिए पहली राष्ट्रीय कार्यनीति 2013-2018 लॉन्च की गई थी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 27 परियोजनाओं को मंजूरी

अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना वाली योजना के अंतर्गत 27 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: इन परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश (7), बिहार (1), गुजरात (2), हरियाणा (4), कर्नाटक (3), केरल (1), मध्य प्रदेश (1), पंजाब (1), राजस्थान (2), तमिलनाडु (4) और उत्तर प्रदेश (1) राज्यों में मंजूरी दी गई है।

- 208 करोड़ की अनुदान-सहायता वाली इन परियोजनाओं से भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत, मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों में भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए 35% की दर से तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, और द्वीपों के लिए 50% की दर से अनुदान-सहायता प्रदान करता है।
- पूरे देश में 85 कोल्ड चेन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

जीके फैक्ट

✧ केंद्रीय क्षेत्र की पीएमकेएसवाई योजना को सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 2016-20 की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

'गन्ना और चीनी उद्योग' पर नीति आयोग कार्य बल रिपोर्ट

नीति अयोग सदस्य (कृषि) रमेश चंद की अध्यक्षता में 'गन्ना और चीनी उद्योग' पर कार्य बल की रिपोर्ट 20 अगस्त, 2020 को प्रकाशित की गई।

महत्वपूर्ण सिफारिशें: कार्य बल ने गन्ना मूल्य को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की।

- चीनी मिलों को उत्पादन की लागत को कवर करने में मदद करने हेतु न्यूनतम चीनी की कीमत में एकमुश्त 33 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी की सिफारिश।
- किसानों को उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करके गन्ने की खेती के तहत कुछ क्षेत्रों में कम पानी वाली फसलों को अपनाने की सिफारिश। किसानों को उनके गन्ना उत्पादन के उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजस्व साझाकरण फॉर्मूला (Revenue Sharing Formula) के साथ ही एक 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' भी शुरू किया जाना चाहिए।
- कम पानी वाली सघन फसलों के लिए प्रोत्साहन लगभग 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होना चाहिए तथा छः महीने में गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की समीक्षा होनी चाहिए।
- तीन साल की अवधि के लिए चीनी पर 50 रुपये प्रति क्विंटल का उपकर लगाने का प्रस्ताव भी किया गया है।

मुक्त व्यापार में आयातित माल के 'मूल स्थान के नियम' को लागू करने की व्यवस्था

केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क की तरजीही दर (preferential rate of customs duties) की अनुमति देने के लिए 'मूल स्थान के नियमों' (Rule of origin) के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए मानदंडों की व्यवस्था की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने तथा एफटीए में भागीदार देश के जरिये किसी तीसरे देश के उत्पादों की डंपिंग को रोकने के लिए यह मानक तैयार किए गए हैं।

- राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के लिए उत्पत्ति नियमों के प्रशासन) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। ये नियम 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे। ये नियम भारत में आयातित उन उत्पादों पर लागू होंगे, जिन पर आयातक व्यापार समझौते के तहत शुल्क में छूट या रियायत का दावा करते हैं।
- व्यापार समझौते के तहत तरजीही शुल्क दर के दावे के लिए आयातक या उसके एजेंट को बिल जमा कराते समय यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित उत्पाद तरजीही शुल्क दर के लिए पात्र है। और उसे संबंधित उत्पाद के 'मूल स्थान का प्रमाणन' भी देना होगा।

जीके फैक्ट

✧ भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और आसियान के सदस्यों सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस तरह के समझौतों में दो व्यापारिक भागीदार देश आपसी व्यापार वाले उत्पादों पर आयात/सीमा शुल्क को घटा देते हैं या पूरी तरह हटा देते हैं।

'पारदर्शी कराधान – ईमानदार का सम्मान' मंच

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अगस्त, 2020 को 'पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान' ('Transparent Taxation-Honoring the Honest) नाम से एक मंच (Platform) का शुभारंभ किया।

उद्देश्यः कर प्रणाली को सुगम, सरल और फेसलेस बनाना तथा करदाताओं का विश्वास बढ़ाना और उन्हें निडर बनाना।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस मंच में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर जैसे प्रमुख सुधारों को समाहित किया गया है।

- फेसलेस असेसमेंट और करदाता चार्टर 13 अगस्त से लागू हो गया, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर से उपलब्ध होगी।

फेसलेस असेसमेंटः इसका उद्देश्य करदाता और आयकर विभाग के बीच मानवीय इंटरफेस को समाप्त करना है।

फेसलेस अपीलः देश भर में किसी भी अधिकारी को यादृच्छिक (randomly) रूप से अपीलें आवंटित की जाएंगी; अपील तय करने वाले अधिकारी की पहचान अज्ञात रहेगी तथा निर्णय टीम आधारित होंगे।

- आयकर दाता को किसी भी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। हालांकि गंभीर अपराध, बड़ी टैक्स चोरी, अंतरराष्ट्रीय कराधान, बेनामी संपत्ति तथा ब्लैक मनी के मामले में इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
- **करदाता चार्टरः** आयकर विभाग एक 'करदाता चार्टर' को अपनाएगा जो कर अधिकारियों और करदाताओं दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। इसके तहत करदाता को अब उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का आश्वासन दिया गया है।

17वें आसियान–भारत आर्थिक मंत्रियों की परामर्श बैठक

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्री त्रान तुआन अन्ह ने 29 अगस्त, 2020 को वर्चुअल रूप में आयोजित 17वें आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श बैठक की सह-अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्यः बैठक में सभी 10 आसियान देशों - ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया।

- बैठक में महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सामूहिक कार्यों हेतु प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।
- डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुपालन के तहत क्षेत्र में विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं और दवाओं के प्रवाह के लिए आर्थिक और वित्तीय स्थिरता तथा आपूर्ति श्रृंखला कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।
- भारत ने मूल-स्थान संबंधी प्रावधान के नियमों को मजबूत करने, गैर-प्रशुल्क बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम करने और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आसियान भारत व्यापार परिषद (एआईबीसी) रिपोर्टः एआईबीसी रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि पारस्परिक लाभ के लिए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN India Trade in Goods Agreement) की समीक्षा की जाए। ताकि मुक्त व्यापार समझौते को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल, सरल और व्यवसायों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

कृषि मेघ

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 अगस्त, 2020 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का डेटा रिकवरी सेंटर 'कृषि मेघ' लॉन्च किया है।

उद्देश्यः सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती आंकड़ों की सुरक्षा करना।

महत्वपूर्ण तथ्यः इसे हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (NAARM) में स्थापित किया गया है। वर्तमान में, ICAR का मुख्य डेटा सेंटर राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (IASRI) में है।

- भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी) के तहत कृषि मेघ की स्थापना की गई है।

कृषि मेघ की प्रमुख विशेषताएंः वर्तमान डाटा सेंटर को क्लाउड कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूत बनाएगा।

- भारत में कृषि क्षेत्र में जोखिम में कमी, गुणवत्ता बढ़ाने, ई-प्रशासन की उपलब्धता और पहुंच प्रदान करेगा।
- छवि विश्लेषण के माध्यम से बीमारी की पहचान, फलों की परिपक्वता और उनके पकने का पता लगाने, पशुओं आदि में बीमारी की पहचान आदि से जुड़े एप्लीकेशंस के विकास और उपयोग के लिए नवीनतम एआई/ डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर/ टूल किट्स मौजूद हैं।

जीके फैक्ट

✧ कृषि विद्यालयों के विद्यार्थियों को ज्यादा औचित्यपूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को डिजाइन किया गया है।

कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग पर समिति की रिपोर्ट

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 11 अगस्त, 2020 को संयुक्त सचिव ज्ञानेश्वर कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित 'कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग पर समिति की रिपोर्ट' जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्यः कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग (Business Responsibility Reporting -BRR) एक सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अपने सभी हितधारकों को उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने का प्रकाशन है।

समिति की सिफारिशेंः गैर-वित्तीय मापदंडों पर रिपोर्टिंग के उद्देश्य और दायरे को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए 'कंपनी जवाबदेही एवं निरंतरता रिपोर्ट' (Business Responsibility and Sustainability Report- BRSR) नामक एक नई रिपोर्टिंग रूपरेखा की सिफारिश।

खुलासा करने (Disclosure) के लिए दो प्रारूपों की सिफारिश: एक 'व्यापक प्रारूप' और दूसरा 'सहज संस्करण'।

- रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर अमल क्रमिक और चरणबद्ध तरीके से किया जाना। BRSR को एमसीए 21 पोर्टल के साथ एकीकृत करना। एमसीए 21 का उपयोग कंपनी कानून के तहत मंत्रालय को अपेक्षित फाइलिंग प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।
- बीआरएसआर फाइलिंग के माध्यम से प्राप्त होने वाली जानकारियों का उपयोग कंपनियों के लिए एक 'कंपनी जवाबदेही-निरंतरता सूचकांक' (Business Responsibility-Sustainability Index) विकसित करने में किया जाना चाहिए।

जीके फैक्ट

✧ इस समिति का गठन 2018 में किया गया था।

आरबीआई द्वारा के वी कामथ की अध्यक्षता में समिति गठित

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 6 अगस्त, 2020 को आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ के वी कामथ की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित दबावग्रस्त कर्ज संपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंड सिफारिशें करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य: आरबीआई ने 7 जून, 2019 को जारी दबावग्रस्त आस्ति के समाधान संबंधी विवेकपूर्ण ढांचे के तहत विशेष विंडो के रूप में 'कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचा' की घोषणा की है।

- समाधान ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ आरबीआई द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी शामिल है।
- वित्तीय मापदण्डों को क्षेत्र विशेष के लिए बेंचमार्क के आधार पर समाधान योजना में शामिल किया जाएगा।
- विशेषज्ञ समिति 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि के दबावग्रस्त खातों के लिए इस रूपरेखा के तहत समाधान योजना की प्रक्रिया का अनुमोदन भी करेगी।
- समिति के अन्य सदस्यों में दिवाकर गुप्ता, टी. एन. मनोहरन शामिल हैं। इसके अलावा अश्विन पारेख समिति के रणनीति सलाहकार तथा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) समिति में सदस्य सचिव होंगे।

भारत की पहली 'किसान रेल'

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केन्द्रीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में 7 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या 'किसान रेल' का शुभारम्भ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह रेल सप्ताह में एक दिन चलेगी और महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री का परिवहन करेगी।

- 'किसान रेल' फलों और सब्जियों को ले जाएगी और इसमें कई स्टेशनों पर स्टॉपेज हैं, जिससे पार्सल चढ़ाया और उतारा जा सकेगा।
- इस ट्रेन में कंटेनर फ्रिज की तरह डिब्बे होंगे। मतलब यह एक चलता-फिरता कोल्ड स्टोरेज होगा, इसमें किसान खराब होने वाले सब्जी, फल, मछ्ली, मांस, दूध आदि रख सकेंगे।
- पार्सल वैन (डिब्बे) रेलवे ने 17 टन की क्षमता के साथ नए डिजाइन के रूप में निर्मित करवाया है। इसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनाया गया है।

जीके फैक्ट

✧ खराब होने वाली उपज की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में 'किसान रेल' शुरू करने की घोषणा की थी।

'प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही-2020' रिपोर्ट

अगस्त 2020 में प्रोपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक (Knight Frank) द्वारा 'प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही-2020' रिपोर्ट जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: रिपोर्ट में दुनिया में आलीशान आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में प्रमुख शहरों की सूची दी गई है।

- इस सूची में फिलिपींस की राजधानी मनीला पहले स्थान पर है। मनीला में जून, 2020 तक सालाना आधार पर आलीशान आवासों की कीमत में 14.4% की वृद्धि हुई। उसके बाद जापान के टोक्यो (8.60%) तथा स्वीडन के स्टॉकहोम (4.40%) हैं।
- थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। वहां सालाना आधार पर आलीशान आवासों की कीमतों में 5.8% की गिरावट दर्ज की गई।
- दुनिया में आलीशान आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में भारतीय शहर बेंगलुरू 26वें और दिल्ली 27वें तथा मुंबई 32वें स्थान पर रहे।
- अप्रैल-जून की तिमाही में पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में बेंगलुरू में आलीशान आवासीय संपत्तियों का पूंजीगत मूल्य 0.6% और दिल्ली में 0.3% बढ़ा, जबकि मुंबई में इसमें 0.6% की गिरावट दर्ज की गई।

जीके फैक्ट

✧ दुनिया के 45 शहरों में आलीशान आवासीय संपत्तियों की कीमत में औसतन 0.9% की वृद्धि हुई है। यह पिछले 11 वर्ष में सबसे कम सालाना वृद्धि है।

भारत–संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि

भारत ने 4 अगस्त, 2020 को विकासशील राष्ट्रों को सभी सतत विकास लक्ष्यों के लिए उनकी विकास संबंधी प्राथमिकताओं हेतु सहायता करने के लिए 'भारत--संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि' में 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस 15.46 मिलियन डॉलर की राशि में 6 मिलियन डॉलर की समग्र निधि भी शामिल है, जिसमें सभी विकासशील देश साझेदारी के लिए पात्र होंगे और अन्य 9.46 मिलियन डॉलर सभी सामान्य राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित होंगे।

- 2017 में स्थापित, भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि' के भीतर एक समर्पित सुविधा है।
- यह भारत सरकार द्वारा समर्थित तथा 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (United Nations Office for South-South Cooperation- UNOSSC) द्वारा प्रबंधित है, और इसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से लागू किया गया है।
- 2017 में इसकी स्थापना के बाद से, 55 परियोजनाओं और प्रस्तावों को अब तक स्वीकृत किया गया है, जिसमें 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बहु-वर्षीय संकल्प के लिए 41.8 मिलियन डॉलर का कुल योगदान शामिल है।

खादी अगरबत्ती आत्म–निर्भर मिशन

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 2 अगस्त, 2020 को अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम 'खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन' को मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्य: देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: सार्वजनिक निजी भागेदारी मोड पर केवीआईसी द्वारा तैयार इस योजना के तहत, केवीआईसी सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा, जो व्यापार भागीदारों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

- केवीआईसी मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और कारीगरों से हर महीने आसान किस्तों में शेष 75% की वसूली करेगा। व्यापार भागीदार कारीगरों को अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा।

जीके फैक्ट

✧ देश में अगरबत्ती की वर्तमान खपत लगभग 1490 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। हालांकि, भारत में अगरबत्ती का उत्पादन प्रतिदिन केवल 760 मीट्रिक टन ही है।

भारत में कृषि वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी

मार्च-जून 2020 की अवधि में देश से 25552.7 करोड़ रूपए की कृषि वस्तुओं का निर्यात हुआ, जो कि 2019 की इसी अवधि में हुए 20734.8 करोड़ रूपए के निर्यात की तुलना में 23.24% अधिक है।

महत्वपूर्ण तथ्य: फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फलों में सबसे ज्यादा निर्यात अंगूर का होता है।

- 2017-18 में भारत का कृषि निर्यात देश के कृषि जीडीपी का जहां 9.4% था, वहीं 2018-19 में यह 9.9% हो गया, जबकि भारत के कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात 5.7% से घटकर 4.9% रह गया, जो निर्यात योग्य अधिशेष को दर्शाता है।
- कृषि उत्पादन के मामले में शीर्ष पर होने के बावजूद कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में देश बड़े कृषि उत्पाद निर्यातक देशों की सूची में स्थान नहीं पा सका है।
- भारत, दुनिया में गेहूं उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन निर्यात के मामले में यह 34वें स्थान पर है।
- सब्जियों के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद निर्यात के मामले में यह 14वें स्थान पर है। फलों के मामले में, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इस क्षेत्र में भी यह निर्यात के मामले में 23वें स्थान पर है।

जीके फैक्ट

✧ विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ो के अनुसार, 2017 में विश्व कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमश: 2.27% और 1.90% था।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के लागू होने के छः साल पूरे

28 अगस्त, 2020 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन-'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (पीएमजेडीवाई) ने सफलतापूर्वक लागू होने के छह साल पूरे किए।

उद्देश्य: किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।

योजना के सिद्धांत: बैंकिंग पहुंच से दूर रहने वाले लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना; असुरक्षित को सुरक्षित करना; तथा वित्त पोषण की सुविधा।

उपलब्धियां: पीएमजेडीवाई के तहत अब तक 40.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग से जोड़ा गया, जिसमें कुल रकम 1.31 लाख करोड़ रुपये है। जबकि प्रति खाता औसत जमा 3,239 रुपए हैं।

- 63.6% ग्रामीण पीएमजेडीवाई खाते तथा 55.2% महिला पीएमजेडीवाई खाते हैं। लगभग 8 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारक सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्राप्त करते हैं। ■■

राष्ट्रीय

74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण के प्रमुख अंश

वोकल फॉर लोकलः स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' (Vocal For Local) के संकल्प से भारत को मजबूती प्रदान करना।

मेक फॉर वर्ल्डः दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र के रूप में देख रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया के साथ-साथ 'मेक फॉर वर्ल्ड' (Make for World) को लेकर आगे बढ़ना।

पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्कः गत 5 वर्ष में डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (OFN) पहुंचाया गया 1000 दिन के अंदर-अंदर देश के छः लाख से अधिक गांवों में OFN का कार्य पूरा करने की योजना।

साइबर सुरक्षाः सरकार द्वारा जल्द ही 'नई साइबर सुरक्षा नीति' का पूरा खाका देश के सामने लाया जाएगा।

महिला स्वास्थ्यः गरीब महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जन-औषधि केंद्र के माध्यम से एक रूपये में 'सैनिटरी पैड' पहुंचाने का काम किया गया है। लड़कियों में कुपोषण, शादी की सही उम्र के संबंध में जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशनः स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission) का 15 अगस्त से आरंभ किया जा रहा है। प्रत्येक भारतीय को 'हेल्थ आईडी' (Health ID) दी जाएगी, जो उसके स्वास्थ्य खाते (स्वास्थ्य संबंधित जानकारी) की तरह काम करेगी।

नवीकरणीय ऊर्जाः भारत one sun, one world, one grid के विजन के साथ पूरी दुनिया को खासतौर से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के शीर्ष पांच देशों में अपनी जगह बना चुका है।

प्रदूषण के लिए प्रौद्योगिकीः 100 शहरों में, प्रदूषण कम करने के लिए, एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रदूषण कम करने की दिशा में मिशन मोड में काम किया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरताः रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए हाल ही में 100 से ज्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गई है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर विस्तार योजनाः 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों से कुल एक लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जायेगा, जिसमें एक-तिहाई कैडेट महिला कैडेट होंगी।

देश के द्वीपीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटीः अंडमान-निकोबार में पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का लोकार्पण किया गया। आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने की योजना है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग

आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 20 अगस्त, 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्यः मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम रैंकिंग हासिल हुई। इंदौर ने लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

- छत्तीसगढ़ को सौ से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान और झारखंड को सौ से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल हुआ।
- देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के लिए नई दिल्ली तथा देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में जालंधर छावनी बोर्ड को शीर्ष रैंकिंग हासिल हुई।

एक लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणीः 1- इंदौर (मध्य प्रदेश), 2- सूरत (गुजरात), 3- नवी मुंबई (महाराष्ट्र), 4-अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़), 5- मैसूर (कर्नाटक)।

एक लाख से कम आबादी वाली श्रेणीः 1- कराड (महाराष्ट्र), 2- सासवड (महाराष्ट्र), 3- लोनावाला (महाराष्ट्र), 4- नवांशहर (पंजाब), 5- पनहाला (महाराष्ट्र)

दस लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणीः 1- इंदौर (मध्य प्रदेश), 2- सूरत (गुजरात), 3-नवी मुंबई (महाराष्ट्र), 4- विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), 5- अहमदाबाद (गुजरात)।

एक लाख से दस लाख तक की आबादी वाली श्रेणीः 1- अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़), 2- मैसूर (कर्नाटक), 3-नई दिल्ली एनडीएमसी (दिल्ली), 4- चंद्रपुर (महाराष्ट्र), 5- खरगौन (मध्य प्रदेश)।

गंगा नदी के तट पर बसे शहर (एक लाख से अधिक आबादी श्रेणी): 1- वाराणसी, (उत्तर प्रदेश) 2- कानपुर (उत्तर प्रदेश), 3- मुंगेर (बिहार)।

गंगा नदी के तट पर बसे शहर (पचास हजार - एक लाख आबादी श्रेणी): 1- कन्नौज (उत्तर प्रदेश), 2- बिजनौर (उत्तर प्रदेश), 3- शुक्लागंज/गंगाघाट (उत्तर प्रदेश)।

गंगा नदी के तट पर बसे शहर (पचास हजार से कम आबादी श्रेणी): 1- चुनार (उत्तर प्रदेश), बिठुर(उत्तर प्रदेश), गौचर (उत्तराखंड)।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' (NDHM) की शुरुआत की।

उद्देश्य: सभी नागरिकों को समावेशी, सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा के लिए समय पर कुशल पहुँच प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम तैयार करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: पूरी तरह से प्रौद्योगिकी आधारित इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड (Health ID card) जारी किया जाएगा, जिसमें उनकी पिछली चिकित्सा स्थिति और उपचार, परीक्षण आदि के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होगी।

- इसे 6 केंद्र-शासित प्रदेशों चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में प्रायोगिक तौर पर लॉन्च किया गया है।
- प्रायोगिक लॉन्च के शुरुआती परिणामों का अध्ययन करने के बाद मिशन को देश के सभी हिस्सों में लागू किया जाएगा।
- 'आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को मिशन के डिजाइन और कार्यान्वयन का जिम्मा सौंपा गया है।

जीके फैक्ट

✧ मिशन का राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट स्वास्थ्य मंत्रालय के पैनल द्वारा नीति आयोग के 2018 में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक (national health stack) के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए तैयार किया गया था।

उड़ान 4.0 के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त, 2020 को क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) योजना (आरसीएस)- उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान- यूडीएएन) के चौथे दौर उड़ान 4.0 के तहत 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इन नए मार्गों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है।

- उत्तर पूर्वी राज्यों में गुवाहाटी से तेजू, रूपसी, तेजपुर, पासीघाट, मीसा और शिलांग के हवाई मार्गों के साथ कनेक्टिविटी को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है।
- उड़ान 4.0 के लिए मंजूर किए गए इन मार्गों से लोग हिसार से चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला के लिए उड़ान भर सकेंगे।
- वाराणसी से चित्रकूट और श्रावस्ती के लिए हवाई मार्गों को भी मंजूरी दी गई है। लक्षद्वीप के अगात्ती, कवारत्ती और मिनिकॉय द्वीपों को भी उड़ान 4.0 के नए मार्गों से जोड़ा गया है।
- उड़ान योजना के तहत अब तक 766 हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। उड़ान के चौथे दौर को दिसंबर 2019 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया था।

जीके फैक्ट

✧ क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) की शुरुआत 2016 में की गई थी।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 40) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 21 अगस्त, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष (पदेन) और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष (पदेन) होंगे।

परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच प्रतिनिधि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

- राष्ट्रीय परिषद का सदस्य, पदेन सदस्य के अलावा, अपने नामांकन की तारीख से तीन साल के लिए पद पर काम कर सकेगा।
- **परिषद के प्रमुख कार्य:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं पर केंद्र सरकार को सलाह देना;
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता से संबन्धित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना;
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े सभी सरकारी और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना;
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना।

अयोध्या राम मंदिर नागर वास्तुकला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 5 अगस्त को अयोध्या में 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' में भूमि पूजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला 'नागर शैली' में किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य: उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला की शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है।

- दक्षिण भारत के विपरीत नागर शैली में आमतौर पर विस्तृत दीवारें या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं।
- इन मंदिरों में गर्भगृह के सामने मंडपों का निर्माण किया जाता है।
- जबकि शुरुआती मंदिरों में सिर्फ एक मीनार या शिखर था, लेकिन बाद के मंदिरों में कई शिखर थे। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है।

हिंदू मंदिर के मूल रूप में निम्न शामिल हैं:

- 'गर्भगृह' जो एक प्रवेश द्वार के साथ एक छोटा कक्ष था समय के साथ एक बड़े कक्ष में विकसित हुआ। गर्भगृह में देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है।
- मंदिर का प्रवेश द्वार जो एक स्तंभयुक्त कक्ष है, बड़ी संख्या में उपासकों के लिए स्थान है, इसे एक 'मंडप' के रूप में जाना जाता है।
- 'शिखर' आकार में पर्वत जैसा होता है, जो उत्तर भारत में एक घुमावदार 'शिखर' का आकार ले सकता है और इसे दक्षिण भारत में 'विमान' कहा जाता है, जो पिरामिड के आकार का होता है।
- 'वाहन' मंदिर के मुख्य देवता का वाहन होता है जो गर्भगृह की सीध में रखा जाता है।

जीके फैक्ट

✧ 'राम मंदिर' मंदिर वास्तुकारों के 'सोमपुरा परिवार' द्वारा बनाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व चंद्रकांत सोमपुरा कर रहे हैं।

27 फीसदी छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं हेतु सुविधाएं नहीं: एनसीईआरटी

अगस्त 2020 में एनसीईआरटी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 27% छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा लेने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप की सुविधा नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सर्वेक्षण में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों सहित 34,000 से अधिक प्रतिभागियों को कवर किया गया।

सर्वेक्षण की मुख्य बातें: 80% से अधिक छात्र ले रहे मोबाइल से ऑनलाइन कक्षा; 28% छात्र-छात्राएं और अभिभावक बिजली की समस्या से परेशान; लगभग 36% छात्रों ने पाठ्यपुस्तकों और उपलब्ध अन्य पुस्तकों का उपयोग किया; लगभग आधे छात्रों के पास स्कूल की पाठ्य पुस्तकें नहीं; गणित और विज्ञान जैसे कांसेप्ट आधारित विषय की ऑनलाइन पढ़ाई कठिन; तथा कई छात्रों और अभिभावकों ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से शारीरिक शिक्षा कक्षाओं की आवश्यकता महसूस की।

अन्य तथ्य: सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के अधिगम संवर्धन दिशा-निर्देश (Learning Enhancement Guidelines) तैयार किए हैं।

- दिशा-निर्देश तीन प्रकार की स्थितियों के लिए सुझाए गए हैं। पहला, जिसमें छात्रों के पास कोई डिजिटल संसाधन नहीं हैं। दूसरा, जिसमें छात्रों के पास सीमित डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। तीसरा, जिसमें छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं।

जीके फैक्ट

✧ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है।

एससी-एसटी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण मामला

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने 27 अगस्त, 2020 को सबसे जरूरतमंद तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी 'कोटे में कोटा' को सही ठहराया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पीठ के अनुसार आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को एससी/एसटी श्रेणी में वर्गीकरण का अधिकार है। राज्य सरकार आरक्षित श्रेणी में उप-वर्गीकरण कर सकती है।

- 2005 में 'ई वी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश' मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही पांच जजों की एक पीठ ने इससे विपरीत फैसला देते हुए कहा था कि एससी/एसटी में उप-वर्गीकरण का राज्यों को अधिकार नहीं है।
- समान क्षमता वाली दो पीठ के विपरीत फैसलों को देखते हुए प्रधान न्यायाधीश से मामले को सात जजों या उससे बड़ी पीठ के समक्ष विचार के लिए आग्रह किया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद दायर की गई अपील के बाद आया है, जिसमें पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवा में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4 (5) को रद्द कर दिया गया था।
- इसके तहत प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का 50%, यदि उपलब्ध हो, तो पहली वरीयता के रूप में 'बाल्मीकि और मजहबी सिखों' को देने का प्रावधान था।

जीके फैक्ट

✧ ई वी चिन्नैया मामले में कहा गया था कि अनुच्छेद 341 (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में सभी जातियां सजातीय समूह के एक वर्ग का गठन करती हैं, और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है।

अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 18 अगस्त, 2020 को अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA) 2020 की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: रैंकिंग में संस्थानों की भागीदारी में पिछले वर्ष की तुलना में 30-35 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

- इस वर्ष, रैंकिंग में दो विस्तृत श्रेणियों और छह उप-श्रेणियों में संस्थानों का वर्गीकरण किया गया था।
- आईआईटी मद्रास ने 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों' की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया।
- इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई को 'सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों' के अंतर्गत शीर्ष स्थान हासिल हुआ।
- 'सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों' के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे; 'निजी या स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों' के अंतर्गत कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर और 'निजी या स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों' के तहत एस. आर. इंजीनियरिंग कॉलेज, वारंगल को शीर्ष स्थान दिया गया।
- रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन 7 मापदंडों के आधार पर किया गया है। इनमें बजट और धन सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं, जागरूकता, उद्यमिता, व्यावसायीकरण, सीखने के तरीके तथा गवर्नेंस शामिल हैं।

जीके फैक्ट

✧ ARIIA भारत में छात्रों और संकायों के बीच 'नवाचार और उद्यमिता विकास' से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD), सरकार की एक पहल है।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अगस्त, 2020 को सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी शुरू में समूह-ख और समूह-ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है।

- इस एजेंसी में रेल तथा वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंक कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- एनआरए द्वारा गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, इंटरमीडिएट और मैट्रिक तीनों स्तर के लिए अलग-अलग सीईटी का संचालन किया जाएगा।
- सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर (II, III इत्यादि) परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा।
- उम्मीदवार का सीईटी स्कोर, परिणाम घोषित करने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य रहेगा। शुरू में वर्ष में दो बार सीईटी का आयोजन किया जाएगा।
- देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है।

एनसीसी विस्तार योजना

स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमावर्ती और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 16 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) विस्तार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

महत्वपूर्ण तथ्य: 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों से कुल एक लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जायेगा, जिसमें एक तिहाई कैडेट महिला कैडेट होंगी। योजना का कार्यान्वयन राज्यों की साझेदारी में किया जायेगा।

- सीमावर्ती एवं तटीय जिलों में से 1,000 से अधिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की पहचान की गई है, जहां एनसीसी को लागू किया जायेगा।
- कैडेटों को एनसीसी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 83 एनसीसी यूनिट्स (सेना 53, नौसेना 20, वायु सेना 10) का उन्नयन किया जायेगा।
- सेना 'सीमावर्ती क्षेत्रों' में स्थित एनसीसी यूनिट्स, नौसेना 'तटीय क्षेत्रों' स्थित एनसीसी यूनिट्स तथा वायु सेना 'वायु सेना स्टेशनों के निकट' स्थित एनसीसी यूनिट्स को प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करायेगी।

जीके फैक्ट

✧ एनसीसी का गठन 1948 में किया गया था। रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ एनसीसी का नेतृत्व तीन-स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। यह हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है और विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। कैडेट विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अगस्त, 2020 को एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (Naval Innovation and Indigenisation Organisation - NIIO) का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: NIIO रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने हेतु अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए शिक्षा और उद्योग के साथ परस्पर संवाद के लिए समर्पित संरचना तैयार करता है।

- NIIO एक त्रि-स्तरीय संगठन है।
- 'नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद' {Naval Technology Acceleration Council (N-TAC)} नवोन्मेषण एवं स्वदेशीकरण दोनों पहलुओं को एक साथ लाएगी और शीर्ष स्तरीय निर्देश उपलब्ध कराएगी। N-TAC के तहत एक कार्य समूह (Working Group) परियोजनओं को कार्यान्वित करेगा।
- त्वरित समय सीमा में उभरती प्रौद्योगिकी के समावेशन के लिए एक 'प्रौद्योगिकी विकास त्वरण प्रकोष्ठ' (Technology Development Acceleration Cell - TDAC) का भी सृजन किया गया है।

जीके फैक्ट

✧ NIIO का गठन 'प्रारूप रक्षा अधिग्रहण नीति 2020' (Draft Defence Acquisition Policy 2020) के अनुरूप है, जो मौजूदा संसाधनों के भीतर सेना मुख्यालयों द्वारा एक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना किए जाने की परिकल्पना करती है।

पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकारः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त, 2020 को ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बेटियों को, बेटों की तरह, संयुक्त हिंदू पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने का एक समान जन्मसिद्ध अधिकार है।

महत्वपूर्ण तथ्यः जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने फैसले में कहा हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005, जिसने पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार दिया था, का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा।

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया था, जो संशोधन के पहले या बाद में पैदा हुई बेटी को बेटे के समान 'हमवारिस' (Coparcener) का दर्जा देता है। श्हमवारिसश एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैतृक संपत्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है।
- पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संशोधन से पहले अर्थात साल 2005 से पहले भी अगर पिता की मृत्यु हो गई है, तो भी पिता की संपत्ति पर बेटी को बेटे के बराबर का अधिकार मिलेगा।
- हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 में यह स्पष्ट नहीं किया गया था, कि क्या यह कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा? तथा क्या महिलाओं का पैतृक संपत्ति संबंधी अधिकार पिता के जीवित होने पर निर्भर करता है?

जीके फैक्ट

✧ साल 2015 में प्रकाश बनाम फूलवती मामले में दो जजों की एक बेंच ने फैसला दिया था कि अगर पिता की मौत हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के 9 सितंबर, 2005 को लागू होने से पहले हो गई है तो बेटी को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

कोझिकोड विमान हादसा और टेबलटॉप रनवे

7 अगस्त, 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान कोझिकोड में कारीपुर के कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 'टेबलटॉप रनवे' (Tabletop runway) पर उतरने के दौरान फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्यः दुबई से लौट रही वंदेभारत एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1344 में विमान के दो टुकड़े होने के कारण 21 लोगों की मौत हो गई।

टेबलटॉप रनवेः टेबल टॉप रनवे अमूमन पठार या पहाड़ के शीर्ष पर होता है। इसमें कई बार एक तरफ या कई बार दोनों तरफ गहरी ढाल होती है, जिसके नीचे घाटी होती है।

- ऐसे रनवे दिखने में जितने सुंदर होते हैं, यहां लैंडिंग उतनी ही जोखिम भरी होती है। लैंडिंग और टेक ऑफ (उड़ान भरने) दोनों के दौरान खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है।
- देश में टेबलटॉप रनवे हवाई अड्डे हैं- लेंगपुई (मिजोरम), शिमला और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश), पाक्योंग (सिक्किम), मंगलुरु (कर्नाटक), कोझिकोड और कन्नूर (दोनों केरल)।

जीके फैक्ट

✧ अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के तकनीकी दस्तावेज में किसी भी रूप में 'टेबलटॉप हवाई अड्डे' जैसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन भारत का विमानन निकाय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), इन हवाई अड्डों को इन रनवे के संचालन के दौरान सुरक्षा उपायों को उजागर करने के लिए टेबलटॉप से संदर्भित करता है।

रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 मसौदा जारी

रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में भारत को शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 3 अगस्त, 2020 को रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा जारी किया।

नीति के लक्ष्य और उद्देश्यः 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये (5 बिलियन डॉलर) के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपये (25 बिलियन डॉलर) का कारोबार हासिल करना।

- गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एयरोस्पेस और नौसेना जहाज निर्माण उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना। घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाना तथा आयात पर निर्भरता कम करना तथा रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
- एक ऐसा वातावरण तैयार करना, जो अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को प्रोत्साहित करे, भारतीय बौद्धिक सम्पदा स्वामित्व तैयार करे और एक मजबूत एवं आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे सके।

- **रणनीति फोकस क्षेत्र:** अधिप्राप्ति सुधार (Procurement Reforms); एमएसएमई/स्टार्टअप स्वदेशीकरण एवं सहायता; इष्टतम संसाधन आवंटन; निवेश संवर्धन, एफडीआई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस; नवाचार और अनुसंधान एवं विकास; रक्षा पीएसयू और आयुध निर्माणी बोर्ड; गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण अवसंरचना तथा निर्यात प्रोत्साहन।

भारत ने लगाया 101 रक्षा उत्पादों पर प्रतिबन्ध

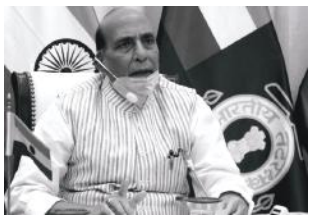

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त, 2020 को भारत द्वारा रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने (नकारात्मक आयात सूची) की घोषणा की। वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे-धीरे लागू करने की योजना है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 वस्तुओं की सूची तैयार की गई थी।

- आयात पर प्रतिबंध लगाई जाने वाली इन 101 वस्तुओं की सूची में न केवल हल्की वस्तुएं शामिल हैं, बल्कि आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें (Assault rifles), लड़ाकू जलपोत, सोनार प्रणाली, मालवाहक विमान, हल्के लड़ाकू विमान (एलसीएच), रडार जैसे कुछ उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां और हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने वाली कई अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं।
- चयनित 101 वस्तुओं में लगभग 260 योजनाएँ शामिल हैं, जिन्हें 2015 से 2020 के बीच 3.5 लाख करोड़ रुपये की लागत से सेना के तीनों अंगों द्वारा अनुबंधित किया गया था।
- इसके अलावा, अगले 5 से 7 वर्षों में घरेलू उद्योगों को 4 लाख करोड़ रुपये के अनुबंध प्रदान किए जायेंगे।

जीके फैक्ट

✧ रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए पूंजी खरीद को घरेलू और विदेशी पूंजी खरीद के रूप में विभाजित किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए घरेलू खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपये का एक अलग बजट बनाया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) ने कोविड महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाएं सुनिश्चित की है।

उद्देश्य: देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) एक नवीन तकनीकी समाधान है, इसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जा रहा है।

- eVIN का लक्ष्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, एक मजबूत आईटी अवसंरचना और प्रशिक्षित मानव संसाधन के माध्यम से देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार तथा बाजार में उपलब्धता और भंडारण तापमान पर रियलटाइम जानकारी देना है।
- कोविड महामारी के दौरान बच्चों तथा गर्भवती माताओं को टीके से बचाव योग्य बीमारियों से बचाने के लिए इस मजबूत प्रणाली का उपयोग किया गया है।
- eVIN 32 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है और जल्द ही शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम में पहुंच जाएगा।
- अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों पर हर वक्त टीके की उपलब्धता बढ़कर 99% हो गई है।

जीके फैक्ट

✧ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ वर्ष 2013 में किया था, जिसके उप-मिशन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को सम्मिलित किया गया था।

रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली

अगस्त 2020 में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है।

उद्देश्य: तैनात सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय रेलवे में मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन ने रेलवे परिसर, रेलवे ट्रैक सेक्शन, यार्ड, वर्कशॉप आदि जैसे रेलवे क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए दो निंजा यूएवी की खरीद की है।

- ये ड्रोन रियल टाइम निगरानी, वीडियो स्ट्रीमिंग में सक्षम हैं और इन्हें स्वचालित विफल सुरक्षित मोड (automatic fail safe mode) पर संचालित किया जा सकता है, जिससे यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- इसका उपयोग रेलवे परिसर में 'आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों' जैसे जुआ खेलने, कचरा फेंकने और फेरी लगाने वालों आदि पर निगरानी रखने तथा 'ट्रेन के सुरक्षित परिचालन' के लिए डेटा संग्रह के लिए भी किया जा सकता है।
- ड्रोन को आपदा स्थलों पर विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय के लिए राहत और बचाव कार्यों, रिकवरी और पुनर्निर्माण जैसी सेवाओं तथा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। ■■

अंतरराष्ट्रीय

अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीका क्षेत्र के कार्यालय द्वारा अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त देश घोषित करने के बाद 25 अगस्त, 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप पोलियो (वाइल्ड पोलियो वायरस) से मुक्त हो गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: अफ्रीका में आखिरी बार पोलियो का मामला 2016 में नाइजीरिया में आया था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जब किसी देश में चार साल तक पोलियो का कोई नया मामला नहीं सामने आता, तो उसे पोलियो मुक्त मान लिया जाता है।

- अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश बचे हैं, जहां अभी तक पोलियो वायरस मौजूद है।
- डब्ल्यूएचओ ने 27 मार्च, 2014 को दक्षिण-पूर्व एशिया को पोलियो मुक्त क्षेत्र घोषित किया था। इसी के तहत भारत भी पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। कभी भी एक देश को अकेले पोलियो मुक्त घोषित नहीं किया जाता है। डब्ल्यूएचओ क्षेत्र आधार पर पोलियो मुक्त होने की घोषणा करता है।
- यह दूसरी बार है, जब अफ्रीका में किसी वायरस को खत्म किया गया है। चार दशक पहले अफ्रीका में चेचक (smallpox) को पूरी तरह से खत्म किया गया था। पोलियो एक विषाणुजन्य रोग है, जो अधिकांशत: बच्चों को होता है। यद्यपि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। यह पानी या मल पदार्थ, अस्वच्छ भोजन के साथ, जल के संक्रमण से हो सकता है।

जीके फैक्ट

✧ डब्ल्यूएचओ ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल (जीपीईआई) शुरू की थी।

इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात आपसी संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और इजरायल ने 13 अगस्त, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।

महत्वपूर्ण तथ्य: सहमति के परिणामस्वरूप इजरायल अपने कब्जे वाले फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से को शामिल करने की अपनी योजना को निलंबित कर देगा।

- 49 वर्षों के बाद, इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात अपने राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से सामान्य करेंगे।
- वे दूतावासों और राजदूतों का आदान-प्रदान करेंगे और पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग शुरू करेंगे।
- यह कदम उन समझौतों की श्रृंखला में पहला होगा, जो इस क्षेत्र में 72 वर्षों की शत्रुता को समाप्त करेगा।

जीके फैक्ट

✧ जॉर्डन और मिस्र, केवल दो अन्य अरब राज्य हैं, जिनके इजरायल के साथ राजनयिक संबंध हैं। मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल

अगस्त 2020 में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन का मुका. बला करने के लिए 'आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल' (Supply Chain Resilience Initiative-SCRI) लॉन्च करने का निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल को सर्वप्रथम जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना है।

- इस पहल का मुख्य उद्देश्य हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, ताकि इस क्षेत्र को आर्थिक महाशक्ति में बदला जा सके। साथ ही, इसका उद्देश्य क्षेत्र के साझेदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध बनाना भी है।
- इस पहल के विचार को आसियान देशों के लिए भी खुला रखा गया है।
- इसकी शुरूआत करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क पर निर्माण कार्य-योजना तैयार करनी होगी। उदाहरण के लिए, भारत और जापान के बीच 'भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता' साझेदारी है, जो भारत में जापानी कंपनियों को स्थापित करने के लिए काम करती है।

जीके फैक्ट

✧ जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या 'क्वाड' (iQuad) के सदस्य हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्श के लिए एक समूह है।

अंतरराष्ट्रीय

डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020

अगस्त 2020 में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (Virtual Private Network- VPN) प्रदाता 'सर्फशार्क' (Surfshark) द्वारा 'डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020' (Digital Quality of Life Index 2020) जारी किया गया।

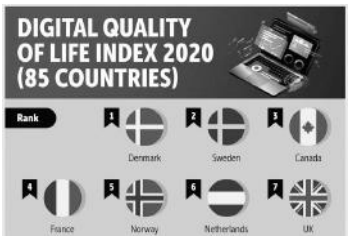

महत्वपूर्ण तथ्य: इस सूचकांक में इंटरनेट क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक गुणवत्ता, और इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा एवं ई-गवर्नमेंट मापदंडो के आधार पर 85 देशों को रैंकिंग दी गयी है।

- सबसे ज्यादा डिजिटल गुणवत्ता वाले शीर्ष 10 में से सात देश यूरोप से हैं, जिनमें डेनमार्क शीर्ष पर है। इसके बाद स्वीडन दूसरे, कनाडा तीसरे, फ्रांस चौथे तथा नॉर्वे पांचवें स्थान पर है।
- अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा; एशिया में जापान; अफ्रीकी देशों में दक्षिण अफ्रीका; तथा ओशिनिया देशों में न्यूजीलैंड सबसे अधिक डिजिटल गुणवत्ता वाले देश हैं। सूचकांक में सबसे नीचे होन्डुरस 85वें तथा अल्जीरिया 84वें स्थान पर है।

भारत की स्थिति: सूचकांक में भारत 57वें स्थान पर है।

- भारत इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना संकेतक में 79वें, इंटरनेट क्षमता संकेतक में 9वें, ई-गवर्नमेंट संकेतक में 15वें, इंटरनेट गुणवत्ता में 78वें, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा में 57वें स्थान पर है।

जीके फैक्ट

✧ सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में चीन 38वें, बांग्लादेश 78वें, नेपाल 79वें, श्रीलंका 80वें, पाकिस्तान 83वें स्थान पर है।

ब्रिक्स नवाचार संचालन केंद्र

24 अगस्त, 2020 को ब्रिक्स उद्योग मामलों के मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में चीन ने पांच देशों के बीच 5जी नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 'ब्रिक्स नवाचार संचालन केंद्र' बनाने की योजना बनाई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत, समूह में एकमात्र देश है, जो देश के 5जी नेटवर्क में चीन की भागीदारी नहीं चाहता है। जबकि रूस 5जी पर चीन के साथ काम करना चाहता है।

- दक्षिण अफ्रीका में, चीनी कंपनी हुआवे (Huawei) अपने तीन दूरसंचार प्रदाताओं को 5जी नेटवर्क के कार्यान्वयन में सेवाएं प्रदान कर रहा है। जबकि ब्राजील ने इसके परीक्षणों में भाग लेने की अनुमति दी है, किंतु अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।
- भारत द्वारा गलवान घाटी में चीन से झड़प के बाद से चीन से निवेश पर कड़ा रुख करने और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के हाल के कदमों के मद्देनजर 5जी में चीनी भागीदारी की अनुमति देने की संभावना न के बराबर है।

जीके फैक्ट

✧ ज्ञात हो कि ब्रिटेन की सरकार ने मई में चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवे को लेकर सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतों के मद्देनजर भारत समेत 10 लोकतांत्रिक देशों का 5जी क्लब बनाने के लिये अमेरिका से संपर्क किया था।

तुर्की द्वारा काले सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज

21 अगस्त, 2020 को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने काले सागर के तट में बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की। खोजी गई प्राकृतिक गैस की मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है।

महत्वपूर्ण तथ्य: तुर्की 2023 से खोजे गए प्राकृतिक गैस का उपयोग शुरू करेगा। हालांकि यह खोज तुर्की के लिए महत्वपूर्ण है, परन्तु यह भंडार पूर्वी भूमध्य सागर में की गई खोजों की तुलना में छोटा है।

- तुर्की अपने ऊर्जा संसाधनों के लिए ईरान, इराक और रूस, पर अत्यधिक निर्भर है। 2019 में, इन देशों से तुर्की का ऊर्जा आयात 41 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार, तेल की खोज से इसके आयात को कम करने में मदद मिलेगी।
- नाटो सहयोगी ग्रीस और तुर्की के बीच चल रहे तनाव के बीच यह खोज सामने आई है।
- वर्तमान में, इन दोनों देशों के बीच बड़ा संघर्ष गैस को लेकर है। हाल ही में, तुर्की साइप्रस के उन क्षेत्रों में ड्रिलिंग पोत 'फतिह' से ड्रिलिंग कर रहा है, जिन पर तुर्की का कब्जा है। तुर्की के कब्जे को अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

अरमको द्वारा चीन में तेलशोधक परिसर बनाने का समझौता स्थगित

सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरमको ने अगस्त 2020 में चीन के उत्तरी प्रांत लियाओनिंग में 10 अरब डॉलर की लागत से तेलशोधक और पेट्रो-रसायन परिसर बनाने का समझौता स्थगित कर दिया है। यह फैसला बाजार के अनिश्चित माहौल को देखते हुए लिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: तेल की कीमतों में गिरावट और कोरोना संकट के चलते तेल की मांग में कमी के कारण दुनिया भर की तेल कंपनियां अपनी परियोजनाओं की समीक्षा कर रही हैं।

- कच्चे तेल की कीमतों में कमी और बढ़ते कर्ज को देखते हुए अरामको कंपनी अपने पूंजीगत व्यय को काफी कम करने की योजना बना रही है, ताकि इसका लाभांश 75 अरब डॉलर बना रहे।
- इस लाभांश का अधिकतर हिस्सा सऊदी सरकार को जाता है, जिसकी सार्वजनिक वित्त की स्थिति फिलहाल कमजोर बनी हुई है।

जीके फैक्ट

✧ सऊदी सरकार और चीन के बीच इस संयुक्त उद्यम पर फरवरी 2019 में युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीजिंग दौरे पर हस्ताक्षर किए गए थे।

43 % से अधिक स्कूलों में नहीं साफ–सफाई की बुनियादी सुविधाएं

संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली एजेंसी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 13 अगस्त, 2020 को प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 43% स्कूलों में साफ- सफाई की बुनियादी सुविधाएं नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य: दुनिया भर में लगभग 81.8 करोड़ बच्चों को अपने स्कूलों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कोरोना वायरस वायरस (COVID-19) होने का खतरा है।

- 81.8 करोड़ बच्चों में से, 35.5 करोड़ बच्चे ऐसे थे, जिनके पास स्कूलों में पानी की सुविधा थी, लेकिन साबुन नहीं था, जबकि 46.2 करोड़ के पास ना तो पानी और ना ही अन्य सुविधा थी।
- एक तिहाई से अधिक या 29.5 करोड़ बच्चे जिनके पास इन मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, वे उप-सहारा अफ्रीका से थे।
- सबसे कम विकसित देशों में 10 में से 7 स्कूलों में हाथ धोने की बुनियादी सुविधाओं का अभाव था।
- 60 देशों में कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य और मानवीय संकट का सबसे अधिक जोखिम है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत के अधिकांश स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। भारत में मात्र 29% स्कूलों में 'विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सुलभ' के रूप में शौचालय बनाए गए थे।

जीके फैक्ट

✧ 2018 में, भारत में दो-तिहाई स्कूलों में बुनियादी पानी की सेवा थी, और आधे से अधिक में स्वच्छता और साफ-सफाई की सुविधाएं थी।

इजरायल ने किया उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण

इजरायल ने 12 अगस्त, 2020 को लंबी दूरी के बैलिस्टिक हमलों के खिलाफ देश की उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली 'एरो -2' (Arrow-2) का सफल परीक्षण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह परीक्षण मध्य इजरायल में संयुक्त रूप से अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ आयोजित किया गया था।

- एरो-2 उस बहुस्तरीय प्रणाली का हिस्सा है, जिसे इजरायल ने गाजा और लेबनान से दागे गए लघु और मध्यम-रेंज के रॉकेट और साथ ही ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाव के लिए विकसित किया है।
- इसमें लौह गुंबद, डेविड'स स्लिंग David's Sling (इजरायल रक्षा बल सैन्य प्रणाली) तथा एरो-3 प्रणाली शामिल है - जो वायुमंडल के बाहर के खतरों से बचाव करने में सक्षम है।
- एरो-2 में एक इंटरसेप्टर वारहेड है, जो अपने लक्ष्य के 40 से 50 मीटर के भीतर विस्फोट करता है।
- इंटरसेप्टर की लंबाई 7 मीटर, व्यास 0.8 मीटर और वजन 1,300 किग्रा. है।
- इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से अलास्का में 2019 में सफलतापूर्वक एरो-3 का परीक्षण किया था, जो जनवरी 2017 में परिचालन में आ गया था।
- एरो-2, एरो-3 से भी लंबे समय से इस्तेमाल हो रही है और इसे हाल के वर्षों में सीरिया की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया है।

श्रीलंका आम चुनावों में सत्ताधारी पार्टी की जीत

श्रीलंका में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व वाली सत्ताधारी पार्टी ने 5 अगस्त, 2020 को हुए आम चुनावों में शानदार जीत दर्ज की।

महत्वपूर्ण तथ्य: महिंदा राजपक्षे को 9 अगस्त को एक ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में चौथी बार देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वे दो बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।

- राजपक्षे की श्रीलंका पोडुजना पेरमुना (एसएलपीपी) ने दो-तिहाई बहुमत के साथ 225 सदस्यीय संसद में 145 सीटें जीती हैं।
- पूर्व मंत्री सजित प्रेमदासा के नेतृत्व में सामगी जन बलवेगया (एसजेबी) 54 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की अगुवाई वाले देश के सबसे पुराने दल यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) को केवल एक सीट हासिल हुई।
- एसएलपीपपी को लगभग 59.9% वोट मिले, जबकि एसजेबी को 24% वोट मिले।
- राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। महिंदा राजपक्षे पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव में गोटबया राजपक्षे की जीत के बाद प्रधानमंत्री बने थे।

जीके फैक्ट

✧ श्रीलंका एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो एक राष्ट्रपति प्रणाली और एक संसदीय प्रणाली के मिश्रण के साथ एक अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख, सरकार का प्रमुख और सशस्त्र बलों का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश की विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है।

शिक्षा पर कोविड–19 महामारी प्रभावः संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

4 अगस्त, 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक गिरावट के कारण अगले वर्ष लगभग 24 मिलियन बच्चों के स्कूल नहीं लौट पाने का खतरा है।

महत्वपूर्ण तथ्यः दुनिया भर में 1.6 अरब से अधिक शिक्षार्थी शिक्षा प्रणाली के व्यवधान से प्रभावित हुए हैं।

- 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान, उच्च विकसित देशों में सिर्फ 20% की तुलना में प्राथमिक स्तर पर गरीब देशों के स्कूल से 86% बच्चे प्रभावी रूप से बाहर हो गए हैं। इस महामारी का सबसे अधिक प्रभाव लड़कियों और महिलाओं पर देखने को मिल सकता है, स्कूल बंद होने से वे बाल विवाह और लिंग आधारित हिंसा के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं।
- 2020 की शुरुआत में, यह अनुमान लगाया गया था कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों ने अपने शिक्षा बजट और गुणवत्ता शिक्षा के सतत विकास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपलब्ध धन के बीच 148 बिलियन डॉलर के अंतर का सामना किया है।
- कोविड-19 के कारण शैक्षिक वित्तपोषण का अंतर भी एक तिहाई बढ़ने की संभावना है। इसलिए शिक्षा बजट को संरक्षित करने और बढ़ाने की जरूरत है।

बेरूत बंदरगाह पर भयावह विस्फोट

4 अगस्त, 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह पर भयावह विस्फोट में 150 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 6,000 से अधिक लोग घायल हुए।

महत्वपूर्ण तथ्यः बंदरगाह पर गोदाम में पड़े 2,700 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट से यह हादसा हुआ है।

- 'नाइट्रोजन समृद्ध यौगिक' अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक संरचना का मुख्य घटक है, जिसे 'अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल' (Ammonium Nitrate Fuel Oil-ANFO) के रूप में जाना जाता है।
- अपने शुद्ध रूप में, अमोनियम नाइट्रेट (NH_4NO_3) एक सफेद क्रिस्टलीय रसायन है, जो जल में घुलनशील है। यह खनन और निर्माण में प्रयुक्त वाणिज्यिक विस्फोटकों के निर्माण में मुख्य घटक है।
- शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में विस्फोटक नहीं है। इसे खतरनाक सामानों के संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण के तहत ऑक्सीकारक (ग्रेड 5.1) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर इसे ईंधन या कुछ अन्य संदूषक जैसे अवयवों के साथ मिलाया जाता है, तो यह बहुत विस्फोटक हो सकता है।
- अमोनियम नाइट्रेट भंडारण में बड़े पैमाने पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण गर्मी उत्पन्न होने से आग लगना विस्फोट का कारण हो सकता है।

जीके फैक्ट

✧ भारत में, विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 अमोनियम नाइट्रेट को 'यौगिक' के रूप में परिभाषित करता है।

माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार

10 अगस्त, 2020 को इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्यः इस विस्फोट के बाद आसमान में 5000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार और धुआँ छा गया।

- लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद ज्वालामुखी में वर्ष 2010 में उद्गार हुआ था। 2013 से यह लगातार पुनः सक्रिय है।
- वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार (विस्फोट) हो चुका है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- इंडोनेशिया के 'रिंग ऑफ फायर' या परिप्रशांत महासागरीय मेखला में अवस्थित होने के कारण यहां कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं और यह क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

जीके फैक्ट

✧ दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत ज्वालामुखी 'रिंग ऑफ फायर' में हैं और लगभग 90 प्रतिशत भूकंप इस 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में आते हैं।

'ईट आउट टू हेल्प आउट' योजना

कोविड-19 लॉकडाउन के बाद आतिथ्य व्यवसायों (Hospitality Businesses) को कारोबार शुरू करने में सहायता हेतु यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा अगस्त 2020 में एक आर्थिक सुधार उपाय के रूप में 'ईट आउट टू हेल्प आउट' (Eat Out to Help Out-EOHO) योजना शुरू की।

महत्वपूर्ण तथ्यः EOHO योजना के अंतर्गत, सरकार ने अगस्त महीने में प्रति सप्ताह सोमवार से बुधवार तक, रेस्तरां में भोजन (केवल खाद्य और गैर-मादक पेय) पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की।

- इस छूट की अधिकतम सीमा 10 ब्रिटिश पौंड प्रति व्यक्ति है। ग्राहकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए खर्च की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। इस योजना का उद्देश्य ग्राहकों को रेस्टोरेंट्स में भोजन करने को प्रोत्साहित करना था।
- EOHO योजना की कुल लागत 500 मिलियन ब्रिटिश पौंड है।

विज्ञान–पर्यावरण

राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020

18 अगस्त, 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु द्वारा 'राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020' जारी की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: रिपोर्ट का अनुमान है कि 2020 में देश में कैंसर के मामले 13.9 लाख होंगे। ये अनुमान 28 'जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों' (PBCR) की सूचना पर आधारित हैं।

- 2020 में, तंबाकू से संबंधित कैंसर का कुल कैंसर के बोझ में 3.7 लाख (27.1%) योगदान का अनुमान है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक है। पुरुषों में फेफड़े, मुंह, पेट और भोजन–नलिका के कैंसर सबसे आम कैंसर थे। महिलाओं के बीच स्तन और गर्भाशय के कैंसर सबसे आम कैंसर हैं।
- कुल कैंसर बोझ में महिलाओं में, स्तन कैंसर का 2.0 लाख (14.8%) और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का 0.75 लाख (5.4%) के योगदान का अनुमान है, जबकि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, जठरांत्र संबंधी मार्ग के कैंसर का 2.7 लाख (19.7%) के योगदान का अनुमान है।
- प्रति 1,00,000 पुरुष आबादी पर 269.4 के साथ कैंसर के सर्वाधिक मामले मिजोरम के आइजोल जिले में (भारत में सबसे अधिक) पाये गए। जबकि प्रति 1,00,000 महिलाओं की आबादी के लिए 219.8 कैंसर के सर्वाधिक मामले अरुणाचल प्रदेश के पापुंपारे जिले में पाए गए।

जीके फैक्ट

✧ वर्तमान अनुमानित मामलों से 12% की वृद्धि के साथ देश में कैंसर के मामलों में 2025 तक 15.6 लाख की वृद्धि होने की संभावना है।

एस्ट्रोसैट दूरबीन द्वारा एक सबसे पुरानी आकाशगंगा की खोज

24 अगस्त, 2020 को 'नेचर एस्ट्रोनोमी' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारत के मल्टी वेवलेंथ वेधशाला 'एस्ट्रोसैट' ने AUDFs01 नामक एक आकाशगंगा से निकलने वाले तीव्र–पराबैंगनी (Ultraviolet-UV) प्रकाश की खोज की है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाशवर्ष की दूरी पर स्थित है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह खोज भारत, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड के खगोलविदों द्वारा खगोल विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कनक साहा के नेतृत्व में की गई।

- इस आकाशगंगा को आकाश के 'हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड' (Hubble eXtreme Deep field– XDF) नामक क्षेत्र में खोजा गया, जो कि 'हबल अल्ट्रा डीप फील्ड' (Hubble Ultra Deep Field– HUDF) के केंद्र में स्थित है।
- HUDF फोर्नेक्स (Fornax) तारामंडल में एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसे वर्ष 2003 से 2004 तक हबल स्पेस टेलीस्कोप डेटा का उपयोग करके निर्धारित किया गया था। XDF नामक इस क्षेत्र में लगभग 5,500 आकाशगंगाएँ हैं।
- एस्ट्रोसैट द्वारा अक्टूबर 2016 में 28 घंटे के लिए एक्सडीएफ के एक हिस्से को देखा गया था। किंतु इसके विश्लेषण में वैज्ञानिकों को दो साल से ज्यादा का समय लग गया।
- पराबैंगनी विकिरण का वातावरण मे अवशोषण हो जाता है, अत: इसे केवल अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा देखा जा सकता था।

जीके फैक्ट

✧ एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला (multi-wavelength space telescope) है। इसे 2015 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान– एशिया के लिए परिवहन पहल

नीति आयोग द्वारा 27 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान– एशिया के लिए परिवहन पहल {Nationally Determined Contributions (NDC)–Transport Initiative for Asia (TIA): NDC– TIA} के भारत घटक की शुरूआत की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल (International Climate Initiative– IKI), प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा (Nature Conservation and Nuclear Safety) द्वारा समर्थित एक संयुक्त कार्यक्रम है।

- इस पहल का उद्देश्य भारत, वियतनाम और चीन में कार्बनमुक्त परिवहन हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
- इसे सात अन्य संगठनों के समूह द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से इस कार्यक्रम को नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

- NDC-TIA कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष है। यह कार्यक्रम सदस्य देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDCs) लक्ष्य को प्राप्त करने तथा परिवहन क्षेत्र में उनकी महत्वाकांक्षा को वर्ष 2025 तक पूरा करने में योगदान करेगा।
- NDC-TIA भारत घटक भारत में कार्बनमुक्त परिवहन के लिए एक बहु–हितधारक संवाद मंच स्थापित करने, परिवहन मॉडलिंग क्षमताओं को मजबूत करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने, परिवहन में जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तपोषण, इलेक्ट्रिक वाहन पर मांग और आपूर्ति संबन्धित नीतिगत सिफारिशें पेश करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक, 2018

अगस्त 2020 में भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थिति का एक आवधिक संकलन विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक (एसटीआई), 2018 जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: एसटीआई के अनुसार, भारत की निजी क्षेत्र की शोध कंपनियां सरकारी वित्त पोषित प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों की तुलना में मुख्य अनुसंधान और विकास गतिविधियों में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा नियोजित करती हैं।

- निजी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कंपनियों में कार्यरत 20,351 महिलाओं में से 15,011 या लगभग तीन–चौथाई 'आर एंड डी गतिविधियों' में शामिल थीं और शेष 'सहायक या प्रशासनिक गतिविधियों' में।
- जबकि 'प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों' में कार्यरत 23,008 महिलाओं में से, आधे से भी कम या 10,138 'आर एंड डी गतिविधियों' में संलग्न थीं।
- वर्ष 2018 तक भारत में 'आर एंड डी' के क्षेत्र में 3,41,818 वैज्ञानिक थे, जिनमें से लगभग 2,03,759 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी संस्थानों द्वारा नियुक्त किए गए।
- 2018 के संकेतक भारत के पुरुष वैज्ञानिकों की अत्यधिक प्रवृत्ति को दोहराते हैं। जहां निजी कंपनियों में प्रत्येक महिला के मुकाबले लगभग 6 पुरुष वैज्ञानिक हैं वहीं सरकारी एजेंसियों में प्रत्येक महिला के मुकाबले 4 पुरुष वैज्ञानिक हैं।

जीके फैक्ट

✧ एसटीआई को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के एक विभाग, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा तैयार किया गया है, और यह देश भर में कई वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।

पर्यावरण अनुकूल लिथियम–सल्फर (Li-S) बैटरी प्रौद्योगिकी

अगस्त 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे और शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण अनुकूल लिथियम–सल्फर (Li-S) बैटरी के उत्पादन के लिए एक नई प्रौद्योगिकी विकसित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह बैटरी इस समय इस्तेमाल की जा रहीं लीथियम–आयन बैटरियों की तुलना में तीन गुना अधिक ऊर्जा क्षमता वाली और किफायती होंगी।

- लिथियम–सल्फर बैटरी प्रौद्योगिकी 'हरित रसायन विज्ञान' सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें पेट्रोलियम उद्योग के सह–उत्पादों (सल्फर), कृषि–अपशिष्ट तत्व और कार्डेनॉल (काजू प्रसंस्करण का एक सह–उत्पाद) जैसे कोपॉलीमर्स और यूजीनॉल (लौंग का तेल) जैसे कैथोडिक सामग्री का उपयोग शामिल है।
- इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योगों की सहायता की क्षमता है, जिनमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं, जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं।

जीके फैक्ट

✧ यूजेनॉल पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, हैलोजन–मुक्त, लौ–मंदक है और दहनशील प्रवृत्ति को कम करता है, जिससे बैटरी उपयोग के लिए सुरक्षित हो जाती है।

अटलांटिक महासागर में माइक्रोप्लास्टिक्स प्रदूषण

18 अगस्त, 2020 को 'नेचर कम्युनिकेशंस' में प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार अटलांटिक महासागर में 11.6–21.1 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक्स है, जो पहले के अनुमान से लगभग 10 गुना अधिक है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अध्ययन में अटलांटिक महासागर के 10,000 किमी. के विस्तार में 12 स्थानों पर आमतौर पर पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले तीन प्लास्टिक प्रकारों–पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टायरीन से होने वाले प्रदूषण को मापा गया।

- ये तीनों प्रदूषक समुद्र की 200 मीटर की गहराई तक निलंबित मात्रा में थे।
- 1950–2015 से प्लास्टिक कचरा उत्पादन के रुझान के आधार पर यह अनुमान लगाया है, कि अटलांटिक महासागर में 65 वर्षों में वैश्विक प्लास्टिक कचरे का 0.3–0.8% प्रवेश हुआ है। साथ ही अटलांटिक महासागर में 17–47 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हो सकता है।
- माइक्रोप्लास्टिक्स लंबाई में 5 मिमी. से छोटे (तिल के बीज आकार के) प्लास्टिक के टुकड़े हैं। ये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका पता लगाना कठिन होता है।

जीके फैक्ट

✧ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के अनुसार, हर साल महासागरों में कम से कम 8 मिलियन टन प्ला. स्टिक प्रवेश करता है, जो सभी समुद्री कचरे का लगभग 80% है।

डीआरडीओ प्रयोगशालाओं से संबंधित समिति

भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास पर ध्यान देने के साथ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की सभी प्रयोगशालाओं के लिए कर्तव्यों के चार्टर की समीक्षा हेतु 24 अगस्त, 2020 को एक पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव करेंगे।

समिति की प्रमुख कार्य-शर्तें: डीआरडीओ के सभी प्रयोगशालाओं के कर्तव्यों के चार्टर का अध्ययन और समीक्षा करना; वर्तमान और भविष्य की रक्षा और युद्धक्षेत्र परिदृश्य पर प्रयोगशालाओं के कर्तव्यों के चार्टर को फिर से परिभाषित करना; और प्रयोगशालाओं के बीच प्रौद्योगिकियों के अतिव्याप्त (overlap) को कम करना।

अन्य तथ्य: डीआरडीओ के पास 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक वाहन, मिसाइल, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान और कृषि जैसे कई विषयों पर काम किया जाता है।

जीके फैक्ट

✧ डीआरडीओ की अंतिम प्रमुख समीक्षा 2008 में पी. रामाराव समिति द्वारा की गई थी, जिसने डीआरडीओ को सात प्रौद्योगिकी समूहों में विकेंद्रीकृत करने और केवल सामरिक महत्व की मुख्य प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया था।

सीएमईआरआई ने विकसित किया विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष

अगस्त 2020 में सीएसआईआर के केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआईआर) ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है, जिसे सीएमईआरआई आवासीय कॉलोनी, दुर्गापुर में स्थापित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट पीक (kWp) से अधिक है। इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000–14,000 इकाइयाँ उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है।

- सौर वृक्ष को इस तरह डिजाइन किया गया है, कि प्रत्येक सौर पैनल अधिकतम सूर्य का प्रकाश हासिल कर सके और नीचे की ओर कम से कम छाया क्षेत्र का निर्माण हो। प्रत्येक सौर वृक्ष में प्रति 330 वाट पीक (Wp) की क्षमता वाले कुल 35 सौर पैनल हैं।
- सौर पैनलों को आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सकता है, यह सुविधा रूफ–माउंटेड सौर सुविधाओं में उपलब्ध नहीं है। ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों की निगरानी रियलटाइम या दैनिक आधार पर की जा सकती है।
- इस सौर वृक्ष का उच्च क्षमता वाले पंप, ई–ट्रैक्टर और ई–पावर टिलर (जुताई करने वाला) जैसी कृषि गतिविधियों में व्यापक उपयोग किया जा सकता है।

जीके फैक्ट

✧ प्रत्येक सौर वृक्ष में जीवाश्म ईंधन की तुलना में ग्रीनहाउस गैसों के रूप में वायुमंडल में जारी होने वाले 10–12 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने की क्षमता है।

उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण

अगस्त 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (डब्लयूआईएचजी) के वैज्ञानिकों द्वारा उत्तराखंड में निचले हिमालयी क्षेत्र में मसूरी और उसके आसपास के 84 वर्ग किमी. क्षेत्र का अध्ययन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: 'जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस' में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र का 15% हिस्सा अत्यधिक भूस्खलन के प्रति अतिसंवेदनशील है। जबकि 29% हिस्सा हल्के भूस्खलन और 56% हिस्सा कम से बहुत कम भूस्खलन वाले अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है।

- भूस्खलन वाले अतिसंवेदनशील क्षेत्र का बड़ा हिस्सा भाटाघाट, जॉर्ज एवरेस्ट, केम्प्टी फॉल, खट्टापानी, लाइब्रेरी रोड, गलोगीधार और हाथीपांव जैसे बसावट वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जो 60 डिग्री से अधिक ढलान वाले अत्यधिक खंडित क्रोल चूना पत्थर (Krol limestone) से आच्छादित हैं।
- अध्ययन में भूस्खलन के विभिन्न संभावित कारकों में चट्टान संरचना (Lithology), लैंड यूज–लैंड कवर (एलयूएलसी), ढलान, वक्रता, ऊंचाई, सड़क–कटान आदि शामिल हैं।
- भूस्खलन के कारणों के एक विशेष वर्ग का पता लगाने के लिए भूस्खलन घटना अनुकूलता स्कोर (Landslide Occurrence Favourability Score-LOFS) के आंकड़े एकत्र किए गए और जीआईएस प्लेटफॉर्म में भूस्खलन अतिसंवेदनशील सूचकांक (Landslide Susceptible Index-LSI) तैयार करने के लिए भूस्खलन के प्रत्येक कारक के प्रभावों की अलग–अलग गणना की गई। LSI को प्राकृतिक मानकों के आधार पर पांच क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

तपेदिक और चिकनगुनिया रोधी फ्लेवोनॉइड अणुओं के लिए पहला संश्लेषित रास्ता खोजा गया

अगस्त 2020 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान अघारकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई), पुणे के वैज्ञानिकों ने तपेदिक और चिकनगुनिया के उपचार से संबंधित फ्लेवोनॉइड अणुओं के निर्माण के लिए पहला सिंथेटिक मार्ग खोजा है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वैज्ञानिक पत्रिका 'एसीएस ओमेगा' द्वारा प्रकाशित अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने रगोसाफ्लेवोनॉइड (rugosaflavonoids), पोडोकारफ्लेवोन (podocarflavone) और आइसोफ्लेवोन (isoflavone) जैसे फ्लेवोनॉइड्स के पहले पूरे संश्लेषण को विकसित किया है।

- रगोसाफ्लेवोनॉइड्स चिकनगुनिया और तपेदिक जैसे अत्यधिक संक्रामक रोगों को रोकने में अत्यधिक शक्तिशाली पाए जाते हैं।
- 'रगोसाफ्लेवोनॉइड ए' एक चीनी औषधीय पौधे 'रोजा रगोसा' (Rosa rugosa) से प्राप्त होता है। 'पोडोकारफ्लेवोन ए' को 'पोडोकार्पस मैक्रोफाइलस' (Podocarpus macrophyllus) पौधे से अलग किया जाता है।

जीके फैक्ट

✧ ज्यादातर आयुर्वेदिक उत्पाद फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर होते हैं। फ्लेवोनॉइड ज्यादातर टमाटर, प्याज, सलाद पत्ता, अंगूर, सेब, स्ट्रॉबेरी, आड़ू और अन्य सब्जियों में मौजूद होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर आहार दिल, जिगर, गुर्दा, मस्तिष्क से संबंधित और अन्य संक्रामक रोगों से बचाव करते हैं।

हिमालय क्षेत्र में भूतापीय जल–स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन

अगस्त 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी (WIHG) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में भू–तापीय जल स्रोत विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: ये भू–तापीय जल स्रोत हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैले हुए हैं। हिमालय क्षेत्र में विभिन्न तापमान और रासायनिक स्थितियों वाले लगभग 600 भू–तापीय जल–स्रोत हैं।

- वैज्ञानिक पत्रिका 'एनवायरनमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च' (Environmental Science and Pollution Research) में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार इन तापीय जल–स्रोतों में कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति, हिमालयी कोर में मौजूद कार्बोनेट चट्टानों के 'मेटामोर्फिक डीकार्बोनेशन' (Metamorphic Decarbonation) के साथ–साथ ग्रेफाइट के मैग्मा में परिवर्तित होने तथा ऑक्सीकरण से होती है। अधिकांश भू–तापीय जल में बड़े पैमाने पर वाष्पीकरण होता है, जिसके बाद सिलिकेट चट्टानों का अपक्षय होता है।
- डीकार्बोनेशन आम तौर पर तब होता है जब कार्बोनेट खनिजों से युक्त एक चट्टान, जैसे कि एक सिलिकेट चूना पत्थर, को उच्च तापमान और दबाव पर कायांतरित किया जाता है।

यमुना नदी में पाये गए डब्ल्यूएचओ द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण रोगजनक

अगस्त 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के एक अध्ययन के अनुसार यमुना नदी में कुछ मल्टीड्रग–प्रतिरोधी बैक्टीरिया पाये गए हैं। इनके प्रवेश का मुख्य स्रोत वाहित मल (sewage) था।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2017 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एंटीबायोटिक–प्रतिरोधी 'प्राथमिक रोगजनकों', बैक्टीरिया जो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं, की पहली सूची प्रकाशित की थी।

- सूची में सबसे ऊपर नई एंटीबायोटिक दवाओं की तत्काल आवश्यकता वाले रोगजनकों के सबसे महत्वपूर्ण समूह को शामिल किया गया था।
- नई दिल्ली में पांच स्थानों पर 20 प्रमुख सीवर नालियों और यमुना नदी के अध्ययन में सभी नमूनों में प्रचुर मात्रा में 'फेकल कॉलिफॉर्म' (Faecal Coliform) को अलग किया गया। फेकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया अपशिष्ट जल के माध्यम से नदियों में प्रवेश कर जाते हैं।
- अध्ययन में ऐसे बैक्टीरिया भी पाए गए, जो विस्तारित बीटा–लैक्टामेस (Beta-lactamases) का उत्पादन करते हैं। ये एंजाइम आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले एंटीबायोटिक दवा के प्रतिरोध के लिए बैक्टीरिया की मदद करते हैं।
- संभवत: आलीशान (पॉश) इलाकों में उन्नत एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक उपयोग और अत्यधिक मानवजनित गतिविधियों के कारण निकास प्रणालियों में प्रतिरोधी बैक्टीरिया बहुतायत में थे।
- ये प्रतिरोधी बैक्टीरिया नदी के जल के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं और इसके मनुष्यों और जानवरों में फैलने की भी अधिक संभावना है।

ओमेगा सेंटॉरी तारा समूह में हीलियम संवर्धित तारों की खोज

'द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल' में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार भारतीय तारा भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics) के वैज्ञानिकों ने ओमेगा सेंटॉरी (Omega Centauri) तारा समूह या ग्लोबुलर क्लस्टर (Globular Cluster) में हीलियम संवर्धित चमकीले तारों की खोज की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: ये तारे हमारी आकाश गंगा (Miky Way) में स्थित सबसे बड़े तारा समूह ओमेगा सेंटॉरी के धातु समृद्ध भाग में मिले हैं।

- ओमेगा सेंटौरी के इन ठंडे चमकीले तारों में हीलियम की मात्रा को मापने के लिए, दक्षिणी अफ्रीकी लार्ज टेलीस्कोप (SALT) से प्राप्त उच्च रिजॉल्यूशन स्पेक्ट्रा का उपयोग किया गया।

ग्लोबुलर क्लस्टर: ग्लोबुलर क्लस्टर लाखों तारों का एक ऐसा सघन समूह है, जो अंतरिक्ष में एक ही गैसीय बादल से निर्मित होता है। इसलिए, आम तौर पर, इससे बनने वाले तारों में मौलिक तत्वों की रासायनिक संरचना एक समान होती है।

- लेकिन ऐसे भी क्लस्टर हैं, जिनमें यह नियम आवश्यक रूप से लागू नहीं होता है– जैसे ओमेगा सेंटौरी के विभिन्न तारों में एक ही प्रकार की धातु सामग्री नहीं पाई गई है।

जीके फैक्ट

✧ अधिकांश तारों में, हाइड्रोजन सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है, लेकिन यदि हाइड्रोजन की प्रचुरता कम होती है, तो हीलियम की प्रचुरता बढ़ जाती है क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का योग एक स्थिरांक होता है, जबकि अन्य भारी तत्व भी अल्प मात्र में मौजूद होते हैं।

तेंदुओं के अवैध शिकार पर 'ट्रेफिक इंडिया' का अध्ययन

अगस्त 2020 में 'ट्रेफिक इंडिया' (TRAFFIC india) द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन के अनुसार भारत में 2015–2019 के बीच कुल 747 तेंदुए की मौत में से 596 अवैध वन्यजीव व्यापार और अवैध शिकार गतिविधियों से हुई।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस दौरान भारतीय तेंदुओं की आबादी में 75% से 90% की गिरावट दर्ज की गई।

- अध्ययन की अवधि के दौरान शिकारियों द्वारा मारे गए 140 तेंदुओं के शवों को वन क्षेत्रों से बरामद किया गया, जबकि 456 तेंदुओं के समतुल्य शरीर के अंगों को विभिन्न अभियानों के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किया गया।
- उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों से सबसे ज्यादा अवैध शिकार की घटनाएं दर्ज की गई।
- 2015 से 2019 की अवधि के दौरान, तेंदुए के शरीर के अंगों की बरामदगी के उत्तराखंड में 140 से अधिक मामले पाये गए तथा 19 का अवैध शिकार किया गया। वहीं महाराष्ट्र से 40 से अधिक मामले दर्ज किए गए तथा 16 का अवैध शिकार किया गया।
- अवैध वन्यजीव व्यापार में खाल (ैापद) सबसे अधिक मांग वाला उत्पाद रहा, जबकि पंजे, दांत और हड्डियों आदि का भी अवैध कारोबार किया गया।

जीके फैक्ट

✧ ट्रेफिक (TRAFFIC) दुनिया भर में एक प्रमुख वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। ट्रेफिक इंडिया के प्रमुख साकेत बडोला हैं।

शेडस्मार्ट और रेडिएंट कूलिंग प्रौद्योगिकी

अगस्त 2020 में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI) ने इमारतों में ऊर्जा-कुशल शीतलन को बढ़ावा देने हेतु 'शेडस्मार्ट' (Shadesmart) और 'रेडिएंट कूलिंग' (Radiant Cooling) प्रौद्योगिकी विकसित की है।

शेडस्मार्ट: दक्षता और आराम के लिए आवास मॉडल परियोजना के अंतर्गत आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में खिड़कियों के लिए बाहरी छाया का नवीन उपाय विकसित किया गया है। इस छाया प्रणाली को 'शेडस्मार्ट' नाम दिया गया है।

- इसे एयर कंडीशनिंग और रोशनी के लिए कम बिजली की खपत के साथ घरों में अंदरूनी आराम प्राप्त करने के एक अभिनव और लागत प्रभावी समाधान के रूप में विकसित किया गया है।
- शेडस्मार्ट सूर्य की स्थिति के आधार पर अपने विन्यास को बदलता है। इससे सूर्य की दिशा की तरफ वाली खिड़कियों पर छाया हो जाती है।
- **रेडिएंट कूलिंग:** इस तकनीक में शीतलता को आम संवहनी एयर कंडीशनिंग के बजाय रेडिएंट हीट (ऊष्मीय विकिरण) ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह तकनीक कुशल है और गर्मी में आरामदायक गुणवत्ता प्रदान करती है।
- रेडिएंट से ठंडी होने वाली इमारतों में ऊर्जा-बचत (60–70 फीसदी) की संभावना बहुत ज्यादा है। रेडिएंट कूलिंग में 100 फीसदी ताजी हवा की आपूर्ति होती है।
- 2014 में भारत के तेंदुओं की अंतिम औपचारिक गणना के अनुसार इनकी आबादी 12,000 से 14,000 के बीच है।

फ्लोराइड आयन का पता लगाने की उपकरण मुक्त प्रौद्योगिकी

अगस्त 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Nano Science and Technology- INST) के वैज्ञानिकों ने पीने के पानी में फ्लोराइड आयन का पता लगाने की उपकरण मुक्त प्रौद्योगिकी विकसित की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसे फ्लोरोसिस-आधारित विकारों से बचाने में घरेलू उपयोग के लिए विकसित किया गया है तथा इसके परिचालन के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होगी।

- इस तकनीक में 2,3-डिस्बस्टिट्यूटेड 1,1,4,4-टेट्रेसीनो-1,3-ब्यूटाडाइन्स (TCBD) पर आधारित एक पुश-पुल क्रोमोफोर (push-pull chromophore) शामिल है, जो फ्लोराइड आयन के संपर्क में आने पर रंग बदलता है। क्रोमोफोर एक अणु का हिस्सा होता है, जो इसके रंग के लिए जिम्मेदार होता है।
- फ्लोरोसिस (Fluorosis) एक गंभीर किस्म की बीमारी है, जो लंबे समय से पीने के पानी/खाद्य उत्पादों/ औद्योगिक प्रदूषण के माध्यम से फ्लोराइड के अधिक सेवन के कारण शरीर के कठोर और नरम ऊतकों में फ्लोराइड्स के जमाव से होती है।
- इसके परिणामस्वरूप, डेंटल फ्लोरोसिस (dental fluorosis), कंकाल फ्लोरोसिस (skeletal fluorosis) और गैर-कंकाल फ्लोरोसिस (non-skeletal fluorosis) बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं।
- विश्व स्वस्थ्य संगठन के अनुसार, पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जीके फैक्ट

✧ नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (INST), मोहाली (पंजाब) को नैनो मिशन के तहत स्थापित किया गया है। भारत में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे 2013 में शुरू किया गया।

भारत एयर फाइबर सेवा

केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स, संचार एवं आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने 2 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी 'भारत एयर फाइबर सेवाओं' (Bharat Air Fibre Services) की शुरुआत की।

लक्ष्य: बीएसएनएल लोकेशन से 20 किमी. के दायरे में वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना तथा दूरदराज वाले स्थानों के ग्राहकों को लाभान्वित करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत एयर फाइबर सेवाएं भारत संचार निगम लिमिटेड–बीएसएनएल द्वारा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहलों के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई हैं ।

- बीएसएनएल स्थानीय व्यावसायिक साझेदारों के जरिये 'भारत एयर फाइबर सेवाएं' प्रदान करेगी। ये सेवाएं शीघ्रता से असीमित नि:शुल्क वॉयस कालिंग के साथ 100 एमबीपीएस स्पीड तक सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगी।
- बीएसएनएल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स (टीआईपी) के रूप में नामांकन करने वाले स्थानीय निवासियों को 1 लाख रुपये की मासिक आय प्रदान करेगा और इस प्रकार वे भारत सरकार की 'आत्म निर्भर भारत' पहलों के तहत आत्म निर्भर भी बन सकेंगे।

अमेरिका द्वारा मिन्यूटमैन III मिसाइल का सफल परीक्षण

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 4 अगस्त, 2020 को कैलिफोर्निया स्थित वेंडेनबर्ग एयर फोर्स बेस से अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिन्यूटमैन III का सफल परीक्षण किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका के एयर फोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड एयरमेन और नेवी सेलर्स द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

- मिन्यूटमैन III तीन–चरणीय ठोस ईंधन चालित मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 18.2 मीटर, व्यास 1.85 मीटर और प्रक्षेपण भार 34467 किग्रा. है। मिसाइल की मारक क्षमता 13000 किमी. है।
- सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल परंपरागत एवं परमाणु युद्धशीर्ष ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी पनडुब्बियों पर इन परमाणु मिसाइलों को तैनात किया जाता है।

जीके फैक्ट

✧ इस मिसाइल को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में वर्ष 1970 में शामिल किया गया था।

भूजल के व्यावसायिक उपयोग पर कड़ी शर्तें

27 जुलाई, 2020 को नियमों के एक बड़े सुधार में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भूजल के व्यावसायिक उपयोग के लिए कड़ी शर्तें लगाने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: एनजीटी ने पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के बिना, विशेष रूप से वाणिज्यिक संस्थाओं पर 'भूजल की निकासी के लिए सामान्य अनुमति' पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- 'परमिट' जल की निर्दिष्ट मात्रा के लिए होना चाहिए, न कि निरंतरता में; और डिजिटल प्रवाह मीटर के साथ इसकी निगरानी की जानी चाहिए और हर साल तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किया जाना चाहिए।
- ऑडिट में विफल रहने वालों के खिलाफ मुकदमा सहित ब्लैकलिस्टिंग की सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
- नए नियमों के अनुसार, अधिकारियों को तीन महीने का समय दिया जाता है ताकि वे अति–दोहन, अर्ध–महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जल प्रबंधन योजना बना सकें।

जीके फैक्ट

✧ लगभग 8,00,000 कंपनियां ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं, जो भारत की सभी 3,881 भूजल मूल्यांकन इकाइयों के एक–तिहाई क्षेत्रों के तहत आते हैं।

इमली और कपास के अपशिष्ट से सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड का निर्माण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटेरियल–एआरसीआई (International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials-ARCI) ने इमली के बीजों और औद्योगिक कपास अपशिष्ट से किफायती इलेक्ट्रोड सामग्री तैयार की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: वैज्ञानिकों ने एक्टिवेशन प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को उच्च छिद्रित कार्बन फाइबर में परिवर्तित किया तथा छिद्रित कॉर्बन फाइबर का प्रयोग कर उच्च–क्षमता वाले सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड का निर्माण किया।

- इलेक्ट्रोड सामग्री का सेंटर फॉर फ्यूल सेल टेक्नालॉजी,एआरसीआई चेन्नई के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित त्वरित परीक्षण प्रारुप के द्वारा परीक्षण किया गया, जिससे विभिन्न छिद्रित इलेक्ट्रोड सामग्री का सुपरकैपेसिटर में अनुकूलता का मूल्यांकन किया गया।
- इससे कम लागत के इलेक्ट्रिक वाहन और हाईब्रिड वाहन बनाने की दिशा में सहायता मिलेगी। ये वाहन अपनी ब्रेकिंग प्रणाली और स्टार्ट–स्टॉप के लिए सुपरकैपेसिटर पर मुख्य रुप से निर्भर हैं।
- वैज्ञानिको की यह खोज 'जर्नल आफ मेटेरियल साइंस: मैटेरियल इन इलेक्ट्रोनिक्स' में प्रकाशित हुई है। ■■

BFSI बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा से संबन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड की शुरुआत की गई है।

नाबार्ड ने लॉन्च किया ऋण गारंटी उत्पाद

अगस्त 2020 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र में बिना किसी अड़चन के ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित ऋण गारंटी उत्पाद की शुरुआत की है। यह उत्पाद एनबीएफसी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्त एवं आंशिक गारंटी कार्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है।

इसमें लघु एवं मध्यम आकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को सामूहिक तौर पर दिये जाने वाले कर्ज पर आंशिक गारंटी उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए नाबार्ड ने विवृत्ति कैपिटल और उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक के साथ इस महीने की शुरुआत में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। शुरुआती चरण में इससे 2,500 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण होगा।

एचएसबीसी इंडिया का 'ग्रीन डिपॉजिट कार्यक्रम'

एचएसबीसी इंडिया ने अगस्त 2020 में कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए हरित पहलों हेतु एक 'ग्रीन डिपॉजिट कार्यक्रम' शुरू किया है। यह कार्यक्रम पर्यावरण-हितैषी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कंपनियों को सक्षम करने के लिए अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण, हरित भवन, सतत जल प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन और अन्य जैसे पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा। एक उत्पाद के रूप में 'ग्रीन डिपॉजिट' सामान्य बैंक जमा के समान स्तर की सुरक्षा के साथ स्थिर तथा पूर्व-सहमत रिटर्न प्रदान करता है।

एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया 'लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट'

एक्सिस बैंक ने अगस्त 2020 में युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया बचत खाता 'लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट' लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को प्रति माह 25,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने या बैंक के डेबिट कार्ड का उपयोग करके हर महीने इतनी ही राशि खर्च करने का विकल्प प्रदान करता है। यह, 20,000 रुपए का बीमा कवर भी प्रदान करता है, जिसमें कोविड-19 से संबंधित अस्पताल का खर्च भी शामिल है। उत्पाद 35 वर्ष से कम आयु के वेतनभोगी पेशेवरों के उद्देश्य से लाया गया है।

किसानों की साख आकलन हेतु उपग्रह डेटा का इस्तेमाल करेगा आईसीआईसीआई बैंक

अगस्त 2020 में आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक अब ऐसी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीजों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकीय और वित्तीय मापदंडों के संयोजन में इसका उपयोग करेगा। बैंक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के 500 से अधिक गांवों में पिछले कुछ महीनों से प्रायोगिक तौर पर उपग्रह डेटा का उपयोग कर रहा है।

'पेटीएम मनी' पर स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करने की घोषणा

पेटीएम ने 13 अगस्त, 2020 को अपने ऑनलाइन निवेश और धन प्रबंधन प्लेटफॉर्म 'पेटीएम मनी' पर बीटा मोड में स्टॉक ट्रेडिंग या शेयर बाजार की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। पेटीएम के उपभोक्ता पेटीएम मनी ऐप का प्रयोग करके शेयर बाजार में शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लिए केवाईसी सहित समस्त प्रक्रिया 100% डिजिटल है। इसके लिए, ऐप हर सूचीबद्ध कंपनी के लिए गहराई से वित्तीय और ऐतिहासिक मूल्य डेटा (price data) प्रदान करेगा, ताकि निवेशकों को स्वयं शेयर बाजार पर शोध करने में सक्षम बनाया जा सके।

टाटा कैपिटल की 'स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन' नामक सेवा

टाटा ग्रुप की वित्तीय सेवा शाखा, टाटा कैपिटल ने 19 अगस्त, 2020 को व्हाट्सएप पर 'स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन' (एसआईपीएल) नामक अपनी नई सेवा शुरू करने की घोषणा की। कंपनी अब अपने मौजूदा ग्राहकों को व्हाट्सएप पर टाटा कैपिटल के चैटबोट 'टीआईए' (TIA) का उपयोग करके तत्काल व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने और मंजूरी प्राप्त करने की अनुमति देगी।

अश्विनी भाटिया एसबीआई के प्रबंध निदेशक नियुक्त

अश्विनी भाटिया को 21 अगस्त, 2020 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। भाटिया की प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति उनकी सेवानिवृति तक के लिये की गई है। वे 31 मई, 2022 को सेवानिवृत होंगे। वे इससे पहले एसबीआई के उप-प्रबंध निदेशक है।

बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा और बीमा

भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड

21 अगस्त, 2020 को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने भारती एंटरप्राइजेज प्रवर्तित भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह पूर्णत: शेयरों की अदला-बदली का सौदा होगा। भारती एंटरप्राइजेज के पास फिलहाल भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी है। शेष 49% हिस्सेदारी फ्रांसीसी बीमा कंपनी एक्सा के पास है। इस सौदे के तहत भारती एक्सा के शेयरधारकों को कंपनी के प्रत्येक 115 शेयरों पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के दो शेयर मिलेंगे। इस विलय के साथ ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देश की तीसरी सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। इस सौदे के बाद कंपनी की वित्तीय-गणना के आधार पर बाजार हिस्सेदारी 8.7% होगी।

गैर-वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए साउथ इंडियन बैंक को आरबीआई की मंजूरी

साउथ इंडियन बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली गैर-वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। बैंक संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने और नियामकों से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सहायक कंपनी परिचालन शुरू कर देगी। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को 29 जनवरी, 1929 को एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में त्रिशूर, केरल में शुरू किया गया था। साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ वी.जी. मैथ्यू हैं।

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड समझौता

धारवाड़ मुख्यालय वाले कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (KVGB) और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 21 अगस्त, 2020 को कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की शाखाओं के माध्यम से सामान्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 सितंबर, 2005 को हुई थी। बैंक के चेयरमैन पी. गोपी कृष्ण हैं।

शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त

भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अगस्त, 2020 को देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। शशिधर जगदीशन की नियुक्ति अक्टूबर 2020 से तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। जगदीशन 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले आदित्य पुरी से पदभार संभालेंगे। जगदीशन, वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड और चेंज एजेंट हैं।

एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया 'शौर्य केजीसी कार्ड'

निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने 14 अगस्त, 2020 को सशस्त्र बलों के लिए एक 'शौर्य केजीसी कार्ड' (Shaurya KGC Card) लॉन्च किया। शौर्य केजीसी कार्ड सशस्त्र बल के कर्मियों को कृषि आवश्यकताओं जैसे फसल उत्पादन, फसल के बाद के रखरखाव और उपभोग की जरूरतों के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करेगा। ऋण सुविधा का लाभ इसकी शाखाओं या इसके ई-किसान धन ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड दिशानिर्देशों के आधार पर, शौर्य केजीसी कार्ड औसत कार्ड के लिए 2 लाख रुपए के मुकाबले 10 लाख रुपए का लाइफ कवर प्रदान करता है।

डीसीबी बैंक की वर्चुअल वीडियो बूथ सुविधा

डीसीबी बैंक ने 5 अगस्त, 2020 को नए ग्राहकों के संपर्क के लिए वर्चुअल वीडियो बूथ सुविधा शुरू करने की घोषणा की। यह किसी भी भारतीय को बिना डीसीबी बैंक शाखा में जाये या बैंक के प्रतिनिधि से मिले बगैर वीडियो-आधारित केवाईसी के माध्यम से डीसीबी बैंक सावधि जमा के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। डीसीबी बैंक की स्थापना 1930 के दशक में हुई थी। डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ मुरली एम. नटराजन हैं।

एस.एन.राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की प्रबंध निदेशक नियक्त

केंद्र ने एस.एन.राजेश्वरी को सामान्य बीमाकर्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले, राजेश्वरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक थीं। वे मई 2022 के अंत तक ओरिएंटल इंश्योरेंस के सीएमडी के पद पर रहेंगी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 12 सितंबर, 1947 को मुंबई में शुरू किया गया था।

दिनेश कुमार खारा होंगे एसबीआई के नए चेयरमैन

दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नए चेयरमैन होंगे। वर्तमान में वे एसबीआई में वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) ने एसबीआई के अगले चेयरमैन पद के लिए खारा के नाम की सिफारिश की है। खारा एसबीआई के मौजूदा चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे, जिनका तीन साल का कार्यकाल 7 अक्टूबर, 2020 को पूरा हो रहा है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का चैटबोट 'लिगो'

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने गूगल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म पर 'लिगो' (LiGo) नाम से एक ग्राहक सेवा चैटबॉट लॉन्च किया। इस सुविधा के माध्यम से कंपनी के पॉलिसी धारक सरल वॉयस कमांड्स देकर अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। ग्राहक स्मार्टफोन (Smartphone) पर इस सुविधा को सक्रिय कर गूगल असिस्टेंट से अपनी पॉलिसी का नंबर या फोन नंबर बोल कर अपनी पॉलिसियों के बारे में तुरंत जानकारी हासिल कर सकते हैं। ■■

B बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम PSUs

प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में करेंट अफेयर्स के अंतर्गत बिजनेस और सार्वजनिक उपक्रम से संबन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड की शुरुआत की गई है।

रिलायंस रिटेल ने खरीदा फ्यूचर समूह का खुदरा और थोक कारोबार

मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने 29 अगस्त, 2020 को फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक कारोबार तथा लॉजिस्टिक्स और भंडारण कारोबार के 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के साथ अधिग्रहण की घोषणा की। किशोर बियानी की अगुवाई वाले फ्यूचर समूह का फ्यूचर रिटेल 1,550 स्टोर का संचालन करता है और इसके प्रमुख ब्रांडों में बिग बाजार, एफबीबी, फूडहॉल, ईजीडे हैं।

'हुंडई मोबिलिटी मेम्बरशिप' कार्यक्रम

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने 13 अगस्त, 2020 को 'हुंडई मोबिलिटी मेम्बरशिप' कार्यक्रम लॉन्च किया। ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए यह एक 'वन-स्टॉप सॉल्यूशन' है। इस नई पहल के जरिए हुंडई ग्राहक को 'आजीवन ग्राहक' बनाने की रणनीति अपना रही है, जिससे ग्राहक ब्रांड के साथ हमेशा जुड़ा रहे। हुंडई इंडिया ने अपने इस कार्यक्रम के लिए 21 ब्रांडों के साथ भागीदारी की है।

सुनील दुग्गल वेदांता के सीईओ

खनन कंपनी वेदांता ने अगस्त 2020 में हिंदुस्तान जिंक के पूर्व सीईओ सुनील दुग्गल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में पदोन्नत किया है। मार्च 2020 में, दुग्गल को वेदांता के अंतरिम सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। दुग्गल पिछले 10 वर्षों से वेदांता से जुड़े हुए हैं और उनके पास 35 साल से अधिक का विविध नेतृत्व अनुभव है।

जोमैटो की 'माहवारी अवकाश' पहल

ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमैटो ने 8 अगस्त, 2020 को अपने संस्थान को बेहतर बनाने के कदम में सभी महिला कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 दिन का 'माहवारी अवकाश' (period leave) देने की घोषणा की। जोमैटो को 2008 में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल हैं।

बीईएमएल का आईआईटी कानपुर और नैसकॉम से समझौता

बेंगलुरु स्थित रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम भारत अर्थ मूवर्स लिमेटेड (बीईएमएल) ने 14 अगस्त, 2020 को ड्रोन (UAV) संबंधित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु आईआईटी कानपुर के साथ तथा कृत्रिम बुद्दिमता (AI) और 'इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए नैसकॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बीईएमएल, पायलट रहित लक्ष्य विमान (PTA) और सामरिक मानवरहित हवाई वाहन (UAV) के संयुक्त स्वदेशी विकास के लिए आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग करेगा। बीईएमएल की स्थापना 1964 में की गई थी। दीपक कुमार होता इसके चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक हैं।

फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स का 'एम्बार्क' प्लेटफॉर्म

डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स (एफएसएस) ने 13 अगस्त, 2020 को विश्वसनीय, लागत-कुशल भुगतान स्वीकृति उपकरणों के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) क्षेत्र को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए एक सेवा के रूप में 'एम्बार्क' (EmBark) प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। एक बहुआयामी भुगतान स्वीकृति प्लेटफॉर्म के रूप में, एम्बार्क बैंक, प्रोसेसर, व्यापारी अधिग्रहण संस्थान (वित्तीय संस्थान जो व्यापारी के बैंक खाते का रखरखाव करता है) और एमएसएमई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

गूगल का 'कोरमो जॉब्स' ऐप

19 अगस्त, 2020 को दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने रोजगार चाहने वालों को नौकरी ढूंढने और पदों के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए भारत में 'कोरमो जॉब्स' ऐप के लॉन्च की घोषणा की है। गूगल ने पिछले साल अपने पेमेंट ऐप 'गूगल पे' के साथ भारत में 'जॉब' फीचर शुरू किया था। इसी फीचर को फिर से ब्रांड करके 'कोरमो जॉब्स' नाम दिया गया है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने लॉन्च किया ऑनलाइन स्टोर

उपभोक्ताओं द्वारा कोविड महामारी के समय उपकरण खरीदने के लिए डिजिटल माध्यम की ओर रुख को देखते हुए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अगस्त 2020 में औपचारिक रूप से देश में अपना कंपनी-स्वामित्व वाला ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है। पहले चरण में, कंपनी दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता जैसे शीर्ष नौ मेट्रो शहरों में उत्पादों की एक चुनिंदा श्रेणी प्रस्तुत करेगी।

एन शिवरामन आईसीआरए लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नियुक्तफ

आईसीआरए लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 10 अगस्त, 2020 से एन शिवरामन को तीन साल के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आईसीआरए लिमिटेड की स्थापना 1991 में की गई थी।

राज्य समाचार

उत्तर प्रदेश

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020

राज्य सरकार ने 18 अगस्त, 2020 को नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 की घोषणा की।

उद्देश्य: राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के उत्पादन का नया वैश्विक केन्द्र बनाना।

- अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश आमंत्रित करने और 4 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य।
- निवेशकों को 15% की पूंजीगत सब्सिडी, 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 10% की अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी तथा अधिसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान।
- क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को भूमि की कीमत में दोगुनी सब्सिडी का प्रावधान।
- वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 की घोषणा की थी। ये तीनों क्षेत्र इस समय दुनिया में मोबाइल फोन उत्पादन के प्रमुख केन्द्रों में हैं।

गुजरात

गुजरात औद्योगिक नीति 2020

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 7 अगस्त, 2020 को गांधीनगर में गुजरात औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की।

- 8,000 करोड़ रुपए तक औसत वार्षिक परिव्यय वाली औद्योगिक नीति में बुनियादी और नये उभरते क्षेत्रों को ऐसे पन्द्रह भागों में विभाजित किया गया है जिन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- बुनियादी क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत मशीनरी और उपकरण, औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, मोटरवाहन और मोटरवाहन वाहनों के पुर्जे, चीनी मिट्टी, तकनीकी वस्त्र, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, औषधि और चिकित्सा उपकरण, रत्न और आभूषण तथा रसायन शामिल हैं।
- दूसरी ओर नये उभरते क्षेत्रों में अत्याधुनिक विनिर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं, इलेक्ट्रिक वाहन और उनके पुर्जे, सौर और पवन ऊर्जा समेत प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उपकरण तथा पारम्परिक प्लास्टिक के स्थान पर सड़ कर नष्ट होने वाले पर्यावरण अनुकूल पदार्थ का उत्पादन शामिल है।
- नई नीति राज्य में वित्तीय सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ऑडियो विजुअल सेवाओं, निर्माण इंजीनियरिंग तथा पर्यावरण सेवाओं आदि में संलग्न सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को 7 वर्ष तक की अवधि के लिए सालाना 35 लाख रुपए तक 7% ब्याज अनुदान की पेशकश करेगी।

पांच शहरों में 70 मंजिला या इससे भी अधिक ऊंची इमारत बनाने की मंजूरी

अगस्त 2020 में राज्य सरकार ने गुजरात के पांच शहरों- अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में 70 मंजिला या इससे भी अधिक ऊंची इमारतें बनाने की मंजूरी प्रदान की।

- राज्य सरकार ने इस तरह की इमारतों के निर्माण के लिए 2017 के मौजूदा नियमों में संशोधन का फैसला लिया है।
- नये नियमों के अनुसार पांच बड़े शहरों में 100 से 150 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों के लिए भूखंड का आकार 2,500 वर्ग मीटर से अधिक होना जरूरी होगा।
- 150 मीटर से अधिक ऊंचाई की इमारत बनाने के लिए 3,500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड की आवश्यकता होगी।
- फिलहाल राज्य में 22-23 मंजिलों से अधिक ऊंची इमारतें बनाने पर पाबंदी है।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना

मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 10 अगस्त, 2020 को राज्य के किसानों के लिए 'मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना' शुरू करने की घोषणा की।

- इस योजना के तहत सूखे, अत्यधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना 1 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर लागू की जाएगी। मुआवजा तभी प्रदान किया जाएगा, जब सूखा या अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल का नुकसान 33% से अधिक होगा। किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि पर मुआवजा पाने हेतु पात्र होंगे।
- 33 से 60% तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान पर एक किसान को 20000 रुपये प्रति हेक्टेयर और 60% से अधिक की फसल के नुकसान पर 25000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मणिपुर

दुनिया के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण मणिपुर में

भारतीय रेल मणिपुर में दुनिया के सबसे ऊंचे स्तम्भ वाले पुल (पियर ब्रिज) का निर्माण कर रही है। यह पुल नोनी के पास 'इजाई' नदी पर बनाया जा रहा है।

- पुल के सबसे बड़े स्तम्भ की ऊँचाई 141 मीटर होगी। फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज (pier bridge) यूरोप में मोंटेनीग्रो में 'माला-रिजेका वायाडक्ट' (Mala-Rijeka viaduct) को माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर है।
- पुल राजधानी इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर पश्चिम में, नोनी जिले के मारंगचिंग के पर्वतीय इलाके में बनाया जा रहा है। इस पुल की कुल लम्बाई 703 मीटर होगी।
- यह पुल 111 किमी. जिरिबाम-तुपुल-इम्फाल न्यू बीजी लाइन परियोजना का हिस्सा है। 280 करोड़ रुपए की लागत का यह पुल मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

राजस्थान

इंदिरा रसोई योजना

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए 20 अगस्त, 2020 को 'इंदिरा रसोई योजनाश का शुभारंभ किया।

- योजना के तहत, स्थानीय संस्थाओं द्वारा राज्य के 213 शहरों में 358 रसोईघर (किचन) शुरू किए गए हैं, जहां दोपहर और रात का खाना सिर्फ 8 रुपए में दिया जाएगा।
- प्रत्येक नगर निगम में 10 रसोईघर शुरू किए गए हैं, प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्रों में 3 और प्रत्येक नगर पालिका में एक-एक रसोई स्थापित की गई है।
- राज्य सरकार प्रति प्लेट 12 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी और हर साल योजना पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये रसोई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल जैसे प्रमुख स्थानों पर संचालित की जा रही हैं।

हरियाणा

हरियाणा ने लॉन्च किया 'परिवार पहचान पत्र'

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त, 2020 को पंचकूला में एक विशिष्ट पहचान पत्र 'परिवार पहचान पत्र' (पीपीपी) लॉन्च किया।

उद्देश्य: राज्य भर में प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शुरू की गई कई नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुचारू और स्वचालित रूप से डिलीवरी के लिए सक्षम बनाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसके तहत, प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी।

- परिवार पहचान पत्र में परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम, आयु, आय, मोबाइल नंबर के अलावा परिवार के मुखिया का नाम होगा।
- अगले तीन महीनों के भीतर सभी विभागों की कल्याणकारी योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा।
- वर्तमान में, चार योजनाओं- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांग जन पेंशन योजना और विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना को 'परिवार पहचान पत्र' के साथ एकीकृत किया गया है।
- सरकारी योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले परिवारों के लिए यह परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है।

पश्चिम बंगाल

'कर्म साथी प्रकल्प' योजना

12 अगस्त, 2020 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'कर्म साथी प्रकल्प' योजना का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

- इस योजना के तहत सरकार 1 लाख बेरोजगार युवाओं को बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी प्रदान करेगी।

आंध्र प्रदेश

वाईएसआर चेयुथा योजना

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 12 अगस्त, 2020 को महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु 'वाईएसआर चेयुथा' (YSR Cheyutha) योजना का शुभारंभ किया।

- योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की 45-60 वर्ष की लगभग 23 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
- योजना के तहत महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,750 रुपये के हिसाब से 4 वर्ष में 75000 रुपये की नगद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

दिल्ली

दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति

दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की।

उद्देश्य: शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, प्रदूषण के स्तर को कम करना और परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन करना।

- दिल्ली सरकार दोपहिया, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, माल वाहन पर प्रत्येक की खरीद पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी और कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। यह सब्सिडी केंद्र सरकार के 'फेम इंडिया' चरण 2 के तहत प्रोत्साहन राशि के अलावा होगी।

नीति के लक्ष्य: वर्ष 2024 तक शहर भर में नए पंजीकृत वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करना।

- इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की खरीद के लिए कम ब्याज दर, नए पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स को कम करना।
- हर 3 किमी. पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने के साथ-साथ अगले एक साल में दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाना ।

छत्तीसगढ़

'पढ़ाई तुहार परा' योजना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त, 2020 को एक विशेष योजना 'पढ़ाई तुहार परा' (Padhai Tuhar Para) शुरू करने की घोषणा की।

- योजना के तहत स्कूली छात्र कोरोनो वायरस प्रकोप के कारण सामुदायिक सहायता से अपने संबंधित स्थानीय इलाकों तथा गांवों में कक्षाएं कर सकेंगे।
- इसके अलावा, एक ब्लूटूथ-आधारित कार्यक्रम 'बुल्टू के बोल' (Bultu Ke Bol) को दूरस्थ क्षेत्रों में उन छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।

शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 अगस्त, 2020 को राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए 'शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना' लॉन्च की।

- 2013 में नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की स्मृति में चलाई जा रही इस योजना का लाभ लगभग 12.5 लाख परिवारों को मिलेगा, जिसमें ज्यादातर आदिवासी और वनवासी हैं, जो इसके संग्रह में लगे हुए हैं।

योजना में प्रावधान: पंजीकृत तेंदू पत्ते के संग्रहकर्ताओं के परिवार के मुखिया (यदि परिवार के मुखिया की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं है) की सामान्य मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति या वारिस को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।

- जबकि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता, पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की सहायता और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की सहायता।
- पंजीकृत तेंदू पत्ते के संग्रहकर्ताओं के परिवार के मुखिया (यदि परिवार के मुखिया की आयु 50-59 वर्ष है) की सामान्य मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति या वारिस को 30,000 रुपये तथा दुर्घटना में मृत्यु/ पूर्ण दिव्यांगता पर 75,000 रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर 37,500 रुपए की वित्तीय सहायता।

जीके फैक्ट

✧ महेंद्र कर्मा को 'बस्तर टाइगर' के नाम से भी जाना जाता था।

मिजोरम

'थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट' परियोजना

केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 अगस्त, 2020 के स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में विश्व स्तरीय 'थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट' परियोजना का उद्घाटन किया।

- स्वदेश दर्शन के तहत इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'न्यू इको टूरिज्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट' के तहत 92.25 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के साथ मंजूरी दी है। इसमें से 64.48 रूपए की राशि थेनजोल और गोल्फ कोर्स के विभिन्न घटकों के लिए आवंटित की गई है।
- थेनजोल में गोल्फ कोर्स को कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी 'ग्राहम कुक एंड एसोसिएट्स' द्वारा डिजाइन किया गया है। यह कुल 105 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जिसमें 75 एकड़ खेल क्षेत्र है।
- यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस है। इन्हें 'साइबेरियाई पाइनवुड' से बनाया गया है।

झारखंड

मुख्यमंत्री श्रमिक योजना

14 अगस्त, 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरी क्षेत्र व 51 नगर निकायों के अकुशल श्रमिकों के लिए 'मुख्यमंत्री श्रमिक योजना' और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया।

- योजना के तहत शहरी जनसंख्या के लगभग उन 31 प्रतिशत लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें हैं।
- इस योजना से 5 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर रोजगार दिया जाएगा, और ऐसा न कर पाने की स्थिति में, लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

उत्तराखंड

पवन हंस की पहली उड़ान-आरसीएस सेवा

उत्तराखंड में देहरादून को गढवाल पर्वतीय क्षेत्र से जोडने वाली पहली सरकारी अंतरराज्यीय हेलिकॉप्टर सेवा 29 जुलाई, 2020 से शुरू हो गई। इससे पर्वतीय क्षेत्र में पयर्टन को बढावा मिलेगा।

- सरकारी पवन हंस लिमिटेड ने केन्द्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत देहरादून-नई टिहरी-श्रीनगर गढवाल-गौचर रूट पर उडान शुरू की।
- पवन हंस लिमिटेड इस रूट पर सप्ताह में तीन दिन हेलीकॉप्टर सेवा का परिचालन करेगी। आम लोगों के लिए किरायों को किफायती बनाए रखने के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत ऑपरेटर और यात्रियों दोनों को ही वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) उपलब्ध कराई गई है। ■■

खेल

चर्चित खेल व्यक्तित्व

महेंद्र सिंह धोनी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त, 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

- उन्होंने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ एकदिवसीय मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने 90 टेस्ट मैचों में 4,876 रन; 350 वनडे मैचों में 10773 रन; तथा 98 टी-20 मैच में 1617 रन बनाए। इसके अलावा बतौर विकेटकीपर 829 शिकार किए।
- धोनी ने 60 टेस्ट, 200 एकदिवसीय और 72 टी-20 मैचों सहित कुल 332 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी की, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। उनकी कप्तानी में, भारत ने 2007 आईसीसी टी-20 विश्व, 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।
- उन्हें 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2009 में पद्म श्री तथा 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

जेम्स एंडरसन

25 अगस्त, 2020 को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन ने इंग्लैंड के साउथऐंपटन में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के अंतिम दिन अजहर अली को आउट कर यह सफलता हासिल की। यह मैच ड्रॉ रहा। इंग्लैंड ने 1-0 से यह श्रृंखला जीत ली है।

- टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन से अधिक विकेट लेने वाले तीनों गेंदबाज - मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न और अनिल कुंबले स्पिनर रहे हैं।

चेतन चौहान

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल और नागरिक सुरक्षा मंत्री चेतन चौहान का कोरोना संक्रमण के चलते 16 अगस्त, 2020 को गुरूग्राम में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे।

- चेतन चौहान ने भारत के लिए 40 टेस्ट और 7 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। सुनील गावस्कर के साथ उनकी सलामी जोड़ी दुनियाभर में मशहूर रही। दोनों ने सलामी जोड़ी के तौर पर तीन हजार से ज्यादा रन बनाए। 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
- चौहान उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 1991 और 1998 में दो बार लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे।

सुरेश रैना

भारत के बायें हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने 15 अगस्त, 2020 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की।

- वे महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाले 2011 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप और 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता भारतीय टीम के सदस्य भी रहे। उन्होंने 226 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 5,615 रन तथा 78 टी-20 मैचों में 1,605 रन बनाए। साथ ही उन्होंने 18 टेस्ट मैच भी खेले।

डेविड जॉन

खेल मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 तक अनुबंध का नवीनीकरण करने के कुछ ही दिन बाद हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर (High Performance Director) डेविड जॉन ने 21 अगस्त, 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की तैयारियों को झटका लगा है।

गोपालस्वामी कस्तूरीरंजन

पूर्व क्रिकेटर गोपालस्वामी कस्तूरीरंजन का 19 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। वे पूर्व क्रिकेट- प्रशासक और बीसीसीआई के क्यूरेटर भी रहे। उन्होंने अपने अधिकांश मैच रणजी ट्रॉफी में 1948 से 1963 के बीच एक दायें हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में कर्नाटक की 'मैसूर' टीम की ओर से खेले।

रोहित शर्मा

स्पोर्ट्स आईवियर (sports eyewear) ब्रांड 'ओकले' ने 18 अगस्त, 2020 को क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में दो साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की।

- साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रिज्म तकनीक (Prizm Technology) से लैस ओकले आईवियर का प्रचार करेंगे।

प्रिंसपाल सिंह

जुलाई 2020 में अंतरराष्ट्रीय स्तर के बास्केट बॉल टूर्नामेंट नेशनल बास्केट बॉल एसोसिएशन (एनबीए) में पंजाब के गुरदासपुर के खिलाड़ी प्रिंसपाल सिंह का चयन हुआ है। भारतीय फारवर्ड प्रिंसपाल सिंह एनबीए जी लीग के अगले सीजन में खेलेंगे।

- 2017 में एनबीए अकादमी इंडिया में शामिल हुए थे। वह एनबीए जी लीग के साथ अनुबंध हस्ताक्षर करने वाले पहले एनबीए अकादमी स्नातक है।

- एनबीए अमेरिका की प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है, जिसमें 30 टीमें शामिल है। उनमें से अमेरिका की 29 और 1 कनाडा की टीम है। प्रिंसपाल सिंह ये गौरव हासिल करने वाले देश के चौथे खिलाड़ी है।

भास्कर मैती

19 अगस्त, 2020 को भारत के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर भास्कर मैती का निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे। उन्होंने 1978 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1975 से 1979 तक खेले।

क्रिकेट

2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा 'टी-20 पुरुष विश्व कप-2020'

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोविड महामारी के कारण स्थगित हुए 'टी-20 पुरुष विश्व कप 2020' को अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पूर्व के कार्यक्रम अनुसार भारत 'टी-20' पुरुष विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा।

- आई.सी.सी. ने न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप 2021 को फरवरी-मार्च 2022 तक स्थगित करने का भी फैसला लिया है।
- टी-20 विश्व कप 2021 का फॉर्मेट 2020 के फॉर्मेट की तरह ही होगा और इसके लिए क्वालीफाइ कर चुकी सभी टीमें भारत में 2021 विश्व कप में भाग लेंगी। टी-20 विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया नयी होगी।

आईसीसी हॉल ऑफ फेम

23 अगस्त, 2020 को जैक कैलिस, जहीर अब्बास और महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को 'आईसीसी हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया है।

- क्रिकेट में बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक कैलिस ने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से 1995 से लेकर 2014 तक 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वे दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टेस्ट (13,289 रन) और वन डे (11,579 रन) में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
- जहीर अब्बास, जिन्हें एशियाई ब्रैडमैन कहा जाता है, ने अंतरराष्ट्रीय करियर में 78 टेस्ट मैचों में 5062 रन तथा 62 वनडे मैचों में 2572 रन बनाए।
- पुणे में जन्मी पूर्व ऑस्ट्रेलिया महिला कप्तान लिसा स्टालेकर ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 8 टेस्ट, 125 वनडे और 54 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले।

जीके फैक्ट

✧ 'आईसीसी हॉल ऑफ फेम' को 2009 में लॉन्च किया गया था।

ड्रीम-11 ने जीता आईपीएल 2020 टाइटल प्रायोजन करार

18 अगस्त, 2020 को फैंटेसी गेमिंग प्लेटफार्म ड्रीम-11 ने 222 करोड़ रुपये की बोली के साथ आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिया है। यह सौदा साढ़े चार महीने के लिए वैध होगा, जो दिसंबर 2020 में समाप्त होगा।

- ड्रीम-11 स्पोर्ट्स ऐप है। क्रिकेट के अलावा यह फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और कबड्डी में भी उपलब्ध है। 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने ड्रीम-11 की शुरुआत की थी।
- ज्ञात हो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 6 अगस्त, 2020 को इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो (VIVO) के साथ टाइटल प्रायोजन करार को निर्लंबित कर दिया था।
- वीवो ने 2190 करोड़ रुपये की राशि के साथ 2018 से 2022 तक पांच साल के लिए आईपीएल टाइटल प्रायोजन करार जीता था।

टेनिस

प्राग चैलेंजर, 2020 टेनिस टूर्नामेंट

एटीपी चैलेंजर टूर का 'प्राग चैलेंजर, 2020 टेनिस टूर्नामेंट' प्राग, चेक गणराज्य में 15 से 22 अगस्त, 2020 तक खेला गया।

प्रतियोगिता परिणाम

- **पुरुष एकल:** विजेता-स्टेन वावरिंका (स्विट्जरलैंड) तथा उपविजेता-असलन कारतसेव (रूस)
- **पुरुष युगल:** विजेता- पियरे-ह्यूग्स हर्बर्ट और आर्थर रिंडरनेच (दोनों फ्रांस) तथा उपविजेता- ज्डेनेक कोलार और लुकास रोसोल (दोनों चेक गणराज्य)

फुटबॉल

यूएफा चैम्पियंस लीग 2019-20

23 अगस्त, 2020 को जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख (Bayern Munich) ने यूएफा चैम्पियंस लीग 2019-20 का खिताब छठी बार जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में बायर्न के किंग्सले कोमान के गोल की बदौलत बायर्न ने पेरिस सेंट जर्मेन (Paris Saint-Germain) को 1-0 से हराने में सफलता पाई।

- बायर्न चैम्पियंस लीग में एक भी मुकाबला नही गवां कर खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बन गई है।
- बायर्न ने हंसी फ्लिक की कोचिंग में इस सत्र में खिताबी हैट्रिक लगाने में सफलता पाई। चैम्पियंस लीग से पहले उन्होने बुंदेसलीगा और जर्मन कप का खिताब भी जीता था।

विविध

राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020

खेल मंत्रालय ने 21 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। विजेताओं को 29 अगस्त, 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल मोड में विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया।

- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार चार वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है; अर्जुन पुरस्कार लगातार चार वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
- द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए प्रशिक्षकों (कोच) को दिया जाता है; ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार: रोहित शर्मा (क्रिकेट), मरियप्पन थंगावेलु (पैरा एथलेटिक्स), मनिका बत्रा (टेबल टेनिस), विनेश फोगाट (कुश्ती), रानी रामपाल (हॉकी)।

द्रोणाचार्य पुरस्कार (लाइफटाइम श्रेणी): धर्मेन्द्र तिवारी (तीरंदाजी), पुरूषोत्तम राय (एथलेटिक्स), शिव सिंह (मुक्केबाजी), रोमेश पठानिया (हॉकी), कृष्ण कुमार हुडा (कबड्डी), विजय भालचंद्र मुनीश्वर (पैरा पावर लिफ्टिंग), नरेश कुमार (टेनिस), ओम प्रकाश दहिया (कुश्ती)।

द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित श्रेणी): ज्यूड फेलिक्स सेबेस्टियन (हॉकी), योगेश मालवीय (मलखंभ), जसपाल राणा (निशानेबाजी), कुलदीप कुमार हांडू (वुशु), गौरव खन्ना (पैरा बैडमिंटन)।

अर्जुन पुरस्कार: अतनु दास (तीरंदाजी), दुती चंद (एथलेटिक्स), सात्विक साइराज रंकीरेड्डी (बैडमिंटन), चिराग चंद्रशेखर शेट्टी (बैडमिंटन), विशेष भृगुवंशी (बास्केटबॉल), सूबेदार मनीष कौशिक (मुक्केबाजी), लवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाजी), इशांत शर्मा (क्रिकेट), दीप्ति शर्मा (क्रिकेट), सावंत अजय अनंत (घुड़सवारी), संदेश झींगन (फुटबॉल), अदिति अशोक (गोल्फ), आकाशदीप सिंह (हॉकी) दीपिका (हॉकी), दीपक (कबड्डी), काले सारिका सुधाकर (खो-खो), दत्तू बाबन भोकानाल (नौकायन), मनु भाकर (निशानेबाजी), सौरभ चौधरी (निशानेबाजी), मधुरिका सुहास पाटकर (टेबल टेनिस), दिविज शरण (टेनिस), शिव केशवन (विंटर स्पोर्ट्स), दिव्या ककरन (कुश्ती), राहुल अवारे (कुश्ती) सुयश नारायन जाधव (पैरा तैराकी), संदीप (पैरा-एथलेटिक्स), मनीष नरवाल (पैरा-निशानेबाजी)।

ध्यानचंद पुरस्कार: कुलदीप सिंह भुल्लर (एथलेटिक्स), जिन्सी फिलिप्स (एथलेटिक्स), प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे (बैडमिंटन), त्रुप्ती मुरगुंडे (बैडमिंटन), एन. ऊषा (मुक्केबाजी), लक्खा सिंह (मुक्केबाजी), सुखविंदर सिंह संधु (फुटबॉल), अजीत सिंह (हॉकी), मनप्रीत सिंह (कबड्डी), जे. रंजीत कुमार (पैरा-एथलेटिक्स), सत्यप्रकाश तिवारी (पैरा-बैडमिंटन), मंजीत सिंह (नौकायन), स्वर्गीय सचिन नाग (तैराकी), नंदन पी बाल (टेनिस), नेत्रपाल हुडा (कुश्ती)।

तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार 2019: अनिता देवी (भू-साहस), कर्नल सरफराज सिंह (भू-साहस), टका तामूत (भू-साहस), नरेन्द्र सिंह (भू-साहस), केवल हीरेन कक्का (भू-साहस), सतेन्द्र सिंह (जल साहस), गजानंद यादव (हवाई साहस), स्वर्गीय मगन बिस्सा (लाइफ टाइम अचीवमेंट)।

मौलाना अबुल कलाम आजाद (एमएकेए) ट्रॉफी: पंजाब यूनीवर्सिटी, चंडीगढ़।

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार: लक्ष्य इंस्टीट्यूट तथा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट (उभरती युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना), ओएनजीसी लिमिटेड (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिये खेल प्रोत्साहन), एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय), इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट (विकास के लिए खेल)।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा

29 अगस्त, 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कारों की सात श्रेणियों में से चार के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की।

- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये, अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये, द्रोणाचार्य (जीवनकाल) पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है।
- वहीं द्रोणाचार्य (नियमित) पुरस्कार तथा ध्यानचंद पुरस्कार के लिए प्रति विजेता नकद पुरस्कार 5 लाख रुपये के बजाय अब 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।

जीके फैक्ट

- खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि की समीक्षा पिछली बार 2008 में की गई थी।

भारत और रूस फिडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता

भारत और रूस को 30 अगस्त, 2020 को फिडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। पहली बार ओलंपियाड ऑनलाइन आयोजित किया गया था।

- मूल रूप से, रूस को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन भारत ने अपील दायर की और जांच के बाद, भारत और रूस दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया।
- यह पहली बार था जब भारत फिडे शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा। इससे पहले ओलंपियाड में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 में हुआ था जब वह कांस्य पदक जीता था।

सार–संक्षेप

चर्चित व्यक्ति

कमला हैरिस

संयुक्त राज्य अमेरिका में, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने 11 अगस्त, 2020 को भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उप–राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नामित किया है।

- एक प्रमुख पार्टी द्वारा उप–राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली वे भारतीय मूल की पहली महिला तथा पहली अश्वेत महिला हैं।
- कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। निर्वाचित होने पर, कमला हैरिस संयुक्त राज्य की उप–राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी।
- वे सैन फ्रांसिस्को के लिए जिला अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला थी। वे कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनने वाली पहली अफ्रीकी–अमेरिकी और भारतीय मूल की महिला भी थीं।

जी सतीश रेड्डी

केंद्र सरकार ने जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष के रूप में दो साल का कार्यकाल विस्तार दिया है।

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ के अध्यक्ष तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव के रूप में रेड्डी के कार्यकाल विस्तार को 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। उन्हें दो साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था।

हसन दियाब

राजधानी बेरूत में बड़े विस्फोट के बाद जनता में आक्रोश के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने पूरी कैबिनेट के साथ 10 अगस्त, 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

- बेरुत के बंदरगाह में 4 अगस्त को हुए अमोनियम नाइट्रेट विस्फोट के बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

एयर मार्शल वी. आर. चौधरी

एयर मार्शल वी. आर. चौधरी ने 1 अगस्त, 2020 को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग–इन–चीफ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल बी. सुरेश से कमान संभाली।

- एयर मार्शल चौधरी को लड़ाकू पायलट के रूप में 29 दिसंबर, 1982 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था।
- उनके पास 3800 से अधिक घंटे का उड़ान अनुभव है, जिसमें मिग–21, मिग–23 एमएफ, मिग–29 और एसयू–30 एमकेआई लड़ाकू विमान शामिल हैं।
- उन्हें जनवरी 2004 में वायु सेना पदक और जनवरी 2015 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

चर्चित स्थल

हुबली

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 9 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया।

- उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह के पहले तथा दक्षिण पश्चिम रेलवे में मैसूर के ऐतिहासिक रेल संग्रहालय के बाद यह रेल संग्रहालय दूसरा संग्रहालयहै।

निधन

ए.आर. लक्ष्मणन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन का 27 अगस्त, 2020 को तिरुचि में निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे।

- न्यायमूर्ति लक्ष्मणन ने 20 दिसंबर, 2002 से 21 मार्च, 2007 तक उच्चतम न्यायालय में सेवाएं दी।
- इससे पहले, वे मद्रास उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया।
- सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें भारत के अठारहवें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

पंडित जसराज

शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का अमेरिका के न्यूजर्सी में 17 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे।

- जसराज का 'मेवाती' घराने से ताल्लुक था, लेकिन उन्हें 'खयाल' की पारंपरिक गायकी के लिए जाना जाता था।
- जसराज ने अर्ध-शास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी काम किया, जैसे हवेली संगीत, जिसमें मंदिरों में अर्ध-शास्त्रीय प्रस्तुतियां शामिल हैं।
- उन्होंने ऑस्कर विजेता फिल्म 'लाइफ ऑफ पाई' में आवाज दी थी। उन्हें 1975 में पद्म श्री, 1990 में पद्म भूषण और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्माननित किया था। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
- सितंबर 2019 में 'अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ' ने 2006 में खोजे गए एक ग्रह '2006 VP32 (संख्या-300128)' का नाम 'पंडित जसराज' ग्रह रख दिया था। संख्या 300128 पंडित जसराज की जन्म तिथि (28-01-30) के ठीक उल्टी है।

अर्नोल्ड स्पीलबर्ग

जाने-माने फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग के पिता एवं नवोन्मोषी इंजीनियर अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का 25 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे 103 वर्ष के थे।

- अर्नोल्ड स्पीलबर्ग और चार्ल्स प्रॉप्स्टर ने 'जनरल इलेक्ट्रिक' के लिए काम करते हुए 1950 के दशक में जीई-225 मेनफ्रेम कंप्यूटर बनाया था।
- इस मशीन की मदद से ही डार्टमाउथ कॉलेज के कंप्यूटर विज्ञानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 'बेसिक' विकसित कर सके थे, जो 1970 तथा 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए बेहद आवश्यक थी।

राहत इंदौरी

मशहूर उर्दू कवि, शायर और गीतकार राहत इंदौरी का कोरोना संक्रमण के चलते 11 अगस्त, 2020 को इंदौर में निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे।

- 'सभी का खून है शमिल यहां की मिट्टी में; किस के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है' राहत इंदौरी की सबसे मशहूर पंक्तियों में से एक थी।
- बतौर कवि 50 साल के करिअर में, इंदौरी को 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' के 'एम बोले तोह'; 'करीब' फिल्म के 'चोरी चोरी जब नजरें मिली'; 'घातक' फिल्म के 'कोई जाए तो ले आए' और फिल्म 'इश्क' के 'नींद चुराई मेरी' जैसे गीतों के बोलों के लिए जाना जाता था।
- उनका असली नाम 'राहत कुरैशी' था। उन्होंने 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया और 1985 में भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जिसका शीर्षक 'उर्दू में मुशायरा' था।

रसेल किर्श

पिक्सल के आविष्कारक और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का 11 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे।

- उन्होंने अपने बेटे की एक 2×2 इंच की छोटी ब्लैक-वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं, जिनका उपयोग फोन और कंप्यूटर स्क्रीन पर फोटो तथा वीडियो प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

इब्राहिम अल्काजी

रंगमंच की दिग्गज हस्ती और विख्यात शिक्षक इब्राहिम अल्काजी का 4 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। अल्काजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सबसे लंबे समय तक निदेशक के पद पर रहे।

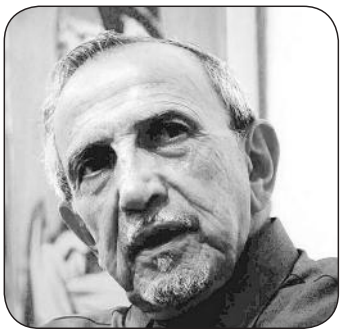

- उन्होंने गिरीश कर्नाड के 'तुगलक', मोहन राकेश के 'आषाढ़ के एक दिन' तथा धर्मवीर भारती के 'अंधायुग' जैसे लोकप्रिय नाटकों का मंचन किया। उन्होंने 'नसीरुद्दीन शाह' और 'ओम पुरी' जैसे अभिनेताओं को अभिनय की बारीकियां सिखाई।
- कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कालिदास पुरस्कार, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड सहित सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का बीमारी के कारण 5 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे।

- मराठावाड़ा क्षेत्र के लातूर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता निलंगेकर जून 1985 से मार्च 1986 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे।

अमर सिंह

राज्य सभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव अमर सिंह का लंबी बीमारी के बाद 1 अगस्त, 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे।

- सिंह ने कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और 1996 में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे।
- वे 1996 में पहली बार राज्य सभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2016 में एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में उच्च सदन के लिए फिर से चुना गया था।
- 2011 में, उन्होंने अपना राष्ट्रीय लोक मंच बनाया और 2012 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में 300 से अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था।

जॉन ह्यूम

उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनेता तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का 3 अगस्त, 2020 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे।

- ह्यूम उत्तरी आयरलैंड में 30 से अधिक वर्षों के लिए सबसे अधिक सम्मानित राजनेताओं में से एक थे।
- वे 1970 में सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी (SDLP) के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने 1979 से 2001 तक पार्टी का नेतृत्व किया।
- उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें डेविड ट्रिम्बल के साथ 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

नियुक्ति

राजीव कुमार

पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 21 अगस्त, 2020 को केंद्र द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। कुमार को अशोक लवासा के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने एशियाई विकास बैंक में बतौर उपाध्यक्ष शामिल होने के लिए इस्तीफा दे दिया है।

- कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

सत्यपाल मलिक

18 अगस्त, 2020 को गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का स्थानांतरण कर उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे तथागत रॉय का स्थान लेंगे।

- मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल भी थे।
- महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

राकेश अस्थाना

18 अगस्त, 2020 को राकेश अस्थाना ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर आईटीबीपी के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल का स्थान लिया, जो मार्च 2020 से बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे।

- 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक पद पर थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अतिरिक्त प्रभार के साथ काम कर रहे थे। वे एनसीबी के प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार जारी रखेंगे।
- वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वी.एस.के. कौमुदी को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) नियुक्त किया गया है।

प्रदीप कुमार जोशी

शिक्षाविद् प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने 7 अगस्त, 2020 को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली।

- उन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया। वे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा मई 2015 में यूपीएससी में बतौर सदस्य शामिल हुए।
- यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी। यूपीएससी भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के समूह ए और समूह बी के लिए नियुक्तियों और परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार है।

जीके फैक्ट

- अनुच्छेद 316 के अनुसार, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

मनोज सिन्हा

पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने 7 अगस्त, 2020 को जम्मू-कश्मीर के नए उप-राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

- उन्होंने पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) नियुक्त किया गया।
- तीन बार सांसद रह चुके, सिन्हा ने नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रेल राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि, वह 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्षेत्र से हार गए थे।

गिरीश चंद्र मुर्मू

केंद्र सरकार ने 6 अगस्त, 2020 को गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) नियुक्त किया है। उन्होंने इससे पहले जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था।

- वे कैग के पद पर राजीव महर्षि का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।
- केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल की नियुक्ति से पहले 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मू, ने वित्त मंत्रालय में व्यय सचिव के रूप में सेवाएं दी थी।

पुरस्कार/सम्मान

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020

26 अगस्त, 2020 को नीदरलैंड्स की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड (Marieke Lucas Rijneveld) को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित 'अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

- 1991 में जन्मी रिजनेवेल्ड यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका (Author) बन गई हैं।
- उन्हे यह पुरस्कार उनकी पुस्तक 'द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग' (The Discomfort of Evening) के लिए प्रदान किया गया। वे पुरस्कार में मिली 50,000 पाउंड की राशि को अनुवादक मिशेल हचिसन के साथ साझा करेंगी।
- पुस्तक एक 10 वर्षीय लड़की जस पर केन्द्रित है, जो अपने भाई मैथ्यूज के साथ आइस-स्केटिंग के लिए जाने की अनुमति न मिलने से क्रोधित है।
- यह पुरस्कार प्रति वर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक लघु कथा और उपन्यास को दिया जाता है, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो।
- वर्ष 2019 का यह पुरस्कार ओमान की लेखिका जोखा अल्हार्थी को उनके उपन्यास 'सेलेस्टियल बॉडीज' के लिए प्रदान किया गया था।

सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को 84 वीरता पुरस्कार

सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 14 अगस्त, 2020 को सशस्त्र बलों के कार्मिकों और अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों के लिए 84 पुरस्कारों और अन्य सम्मानों को मंजूरी प्रदान की।

- इन पुरस्कारों में 1 कीर्ति चक्र, 9 शौर्य चक्र, 5 बार टू सेना मेडल (वीरता), 60 सेना मेडल (वीरता), 4 नौसेना मेडल (वीरता), 5 वायु सेना मेडल (वीरता) शामिल हैं।
- जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलास को मरणोपरांत 'कीर्ति चक्र' प्रदान किया गया।
- इस बार चार रक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। 'जम्मू- कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों' के लिए थलसेना के ले. कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर विशाख नायर को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है।
- राष्ट्रपति ने विभिन्न सैनिक कार्रवाइयों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सेना के कार्मिकों के लिए 19 मेंशन-इन-डिस्पैच (Mention-in-Despatches) की भी मंजूरी दी है, जिसमें 'ऑपरेशन मेघदूत' और 'ऑपरेशन रक्षक' के लिए 8 मरणोपरांत शामिल हैं।
- सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाइयों पर नियंत्रण के लिए 1984 में ऑपरेशन 'मेघदूत' शुरू किया गया था। 'ऑपरेशन रक्षक' जम्मू-कश्मीर में 1990 से शुरू आतंकवाद विरोधी अभियान है।

जीके फैक्ट

- ये वीरता पुरस्कार वर्ष में दो बार घोषित किए जाते हैं - गणतंत्र दिवस के अवसर पर और फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है।

खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार

अगस्त 2020 में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा 'खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार' के लिए शीर्ष दस फाइनलिस्टों में चुना गया है।

- 'एफएसएसएआई' को 'ईट राइट इंडिया' (Eat Right India) पहल के लिए चुना गया है। यह पहल खाद्य अपशिष्ट को कम करने के सिस्टम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से स्वस्थ आहार की दिशा में एक राष्ट्रीय अभियान है।

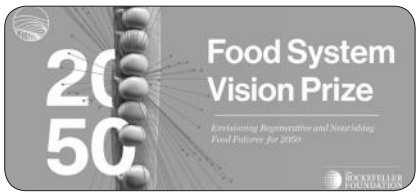

- हैदराबाद स्थित गैर-लाभकारी संगठन 'नंदी फाउंडेशन' को भी नए एकीकृत आर्थिक मॉडल 'अराकुनोमिक्स' हेतु पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो अराकू में आदिवासी किसानों के साथ काम पर आधारित है।

जीके फैक्ट

- खाद्य प्रणाली विजन पुरस्कार, 2050 तक 'पुनरुत्पादक और पौष्टिक खाद्य प्रणाली का विजन' विकसित करने के लिए दुनिया भर के संगठनों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। दस फाइनलिस्ट में से प्रत्येक को 200,000 डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा।

सार–संक्षेप

अभियान/सम्मेलन/आयोजन

'चुनौती' - नेक्सट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 28 अगस्त, 2020 को भारत के टियर-2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देने के लिए 'चुनौती'-नेक्सट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया।

उद्देश्य: चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपये तक की प्रारंभिक राशि (सीड फंड) तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।

- सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए 95.03 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

नौसेना के कमांडरों का वार्षिक सम्मेलन

नौसेना के कमांडरों का तीन दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 19 से 21 अगस्त, 2020 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

- इसमें नौसेनाध्यक्ष कमांडर्स-इन-चीफ के साथ वर्ष के दौरान की गयी संचालन प्रकियाओं, साजो-सामान और लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा की गई।

आसियान-इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का छठा-गोलमेज सम्मेलन

20-21 अगस्त, 2020 को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैंकॉक में आयोजित आसियान-इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (AINTT) में भाग लिया। यह भारत और AINTT के बीच छठा-गोलमेज सम्मेलन था।

विषय: 'आसियान-भारत: कोविड महामारी के बाद के युग में साझेदारी सुदृढ़ करना' (ASEAN-India: Strengthening Partnership in the Post COVID Era)।

- विदेश मंत्री ने सम्मेलन के दौरान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की चिंताओं को कम करने तथा आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण और लचीलापन करने तथा भारत और आसियान देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का एक मॉडल लागू किए जाने पर जोर दिया।

टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज 2019

कपड़ा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कपास बोर्ड और उद्योग और औद्योगिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की स्टार्ट अप इंडिया टीम के सक्रिय सहयोग से टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज 2019 का आयोजन किया गया।

उद्देश्य: प्लास्टिक थैलों को हटाने के लिए जूट बायोमास, जूट प्लांट आधारित बायो- पॉलीमर और कपास फाइबर के कचरे का उपयोग करके किफायती और कम वजन वाले कैरी बैग तैयार करने के लिए स्टार्ट-अप/ व्यवसायियों के नवीन विचारों को आगे लाना।

- इसके अंतर्गत (i) एक बार उपयोग में आने वाले प्लाास्टिक थैलों का विकल्प और (ii) घरेलू रूप से विकसित प्राकृतिक फाइबर जैसे जूट और कपास का उपयोग करके बहु-उपयोग वाले प्लास्टिक थैलों के विकल्प के लिए नवीन समाधान मांगे गए थे।

ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधी कार्यकारी समूह का चौथा सत्र

ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत को मिलाकर बने ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधी कार्यकारी समूह के चौथे सत्र का आयोजन 12 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, जिसकी अध्यक्षता रूस ने की।

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया।
- अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधी कन्वेन्शन (International Anti-drug conventions) के प्रति पांच सदस्य राष्ट्रों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाली विज्ञप्ति को अपनाया गया।
- ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों के बीच रियलटाइम जानकारी को साझा करने और समुद्री मार्गों के माध्यम से नशीली दवाओं की बढ़ती तस्करी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया गया।

स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 18 अगस्त, 2020 को 'स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज-आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान' लॉन्च किया। इस चैलेंज के अवधि 10 महीने की है।

उद्देश्य: देश में स्टार्ट-अप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत इकोसिस्टम को और गति प्रदान करना।

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के 'माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम' के तत्वावधान में स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति' और 'वेगा' को लॉन्च किया गया।
- 'स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज' के तहत इन माइक्रोप्रोसेसरों का उपयोग करते हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी उत्पादों को विकसित करने के लिए नवोन्मेषकों, स्टार्ट-अप और छात्रों को आमंत्रित किया गया है।

'वोकलफॉरहैंडमेड' सोशल मीडिया अभियान

7 अगस्त, 2020 को छठे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए हैशटैग #Vocal4Handmade

के जरियेदो सप्ताह के 'वोकलफॉरहैंडमेड' सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की गई।

- इसके तहत हथकरघा व देश के विभिन्न क्षेत्रों के उच्च स्तरीय हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु हथकरघा उत्पादों के निर्माताओं और बुनकरों/कारीगरों को ट्वीट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे आम लोगों के बीच अपने हथकरघा उत्पादों का प्रचार-प्रसार कर सकें।
- हैंडलूम मार्क योजना (एचएलएम) के लिए 'मोबाइल ऐप' और 'वेबसाइट' तथा ब्लॉक स्तर के समूहों, हथकरघा विपणन सहायता योजनाओं और पुरस्कारों के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तिगत बुनकरों के साथ-साथ अन्य संगठनों के लिए 'माई हैंडलूम' पोर्टल भी लॉन्च किया गया।

युद्धाभ्यास/सैन्य अभियान

अपतटीय गश्ती पोत 'सार्थक' लॉन्च

13 अगस्त, 2020 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए 'सार्थक' नाम का एक अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) लॉन्च किया गया।

- ओपीवी 'सार्थक' पांच ओपीवी की श्रृंखला में चौथा है। इसे मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- 105 मीटर यह पोत अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है।

समझौते/संधि

एपीडा द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समन्वय हेतु समझौता

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने 25 अगस्त, 2020 को 'एएफसी इंडिया लिमिटेड' और 'भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ' के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समन्वय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- एएफसी इंडिया लिमिटेड जैविक उत्पादन प्रणाली के साथ-साथ रासायनिक / अवशेष मुक्त उत्पादन प्रणाली के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की पहचान कर इसे प्रस्तुत करेगा।
- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ प्रदान करके सरकार द्वारा निर्धारित किसान आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेगा।
- 1968 में स्थापित एएफसी इंडिया लिमिटेड वाणिज्यिक बैंकों, नाबार्ड और एक्जिम बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत भारत के सहकारी गतिविधियों का सर्वोच्च संगठन है।

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना- III हेतु ऋण समझौता

भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए 24 अगस्त, 2020 को 500 मिलियन डॉलर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना- III के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- परियोजना की कुल अनुमानित लागत 997 मिलियन डॉलर है, जिसमें से 500 मिलियन डॉलर एआईआईबी, 310 मिलियन डॉलर महाराष्ट्र सरकार और 187 मिलियन डॉलर रेल मंत्रालय वहन करेगा।
- एआईआईबी से 500 मिलियन डॉलर ऋण में 5 साल की छूट अवधि और 30 साल की परिपक्वता अवधि है।
- मुंबई महानगर क्षेत्र में लगभग 86% लोग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर करते हैं।

अटल नवाचार मिशन और भारत-स्वीडन हेल्थकेयर इनोवेशन सेंटर साझेदारी

20 अगस्त, 2020 को देश में नवाचार की संस्कृति के विस्तार की एक साझा दृष्टि के अनुरूप, नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन (AIM) और 'भारत स्वीडन हेल्थकेयर इनोवेशन सेंटर' की ओर से 'बिजनेस स्वीडन' (Business Sweden) ने भारतीय उद्यमियों की उभरती क्षमता और देश भर में जीवंत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की।

- साझेदारी से अटल नवाचार मिशन के तहत चल रही विभिन्न कार्यक्रम और पहलों जैसे अटल न्यू इंडिया चौलेंज (ANIC), अटल इन्क्यूबेशन केंद्र (AIC), अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र

(ACIC), अटल टिंकरिंग लैब (ATL) और छोटे उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार (ARISE) को सहयोग मिलेगा।

भारत-स्वीडन हेल्थकेयर इनोवेशन सेंटर: यह एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर और बिजनेस स्वीडन के बीच एक साझेदारी है। इसका उद्देश्य खुले नवाचार का एक इकोसिस्टम तैयार करना है।

- इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), स्वीडन के स्वास्थ्य और सामाजिक मामलों के मंत्रालय और भारत में स्वीडन के दूतावास के रणनीतिक मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।

जहाजरानी मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के बीच समझौता

बंदरगाह और समुद्रीय क्षेत्र में कौशल विकास के लिए 20 अगस्त, 2020 को जहाजरानी मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्देश्य: बढ़ते हुए समुद्रीय उद्योग और तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल, पुन:कौशल और कौशल में वृद्धि करना।

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षेत्र में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने हेतु साझेदारी

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टार्ट-अप कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत कार्यरत राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी (एनएएल) के साथ अगस्त 2020 में साझेदारी की है।

- साझेदारी के तहत दोनों संस्थान मिलकर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के उभरते क्षेत्रों से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करेंगे तथा एयरोस्पेस क्षेत्र से संबंधित इनोवेशन/इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करेंगे।

जीके फैक्ट

- एनआरडीसी की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय विकास एवं अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों से निर्गत होने वाली प्रौद्योगिकियों/जानकारियों/आविष्कारों/पेटेंट/प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका व्यवसायीकरण करना है। एनआरडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ एच. पुरुषोत्तम हैं।

सीएसआईआर और एफएसएसएआई के बीच समझौता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के बीच 7 अगस्त, 2020 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्देश्य: खाद्य एवं पोषण के संबंध में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं सूचना का प्रसार करना।

एनएचएआई और आईआईटी दिल्ली

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 6 अगस्त, 2020 को राजमार्गों के लिए डाटा प्रेरित निर्णय प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)

तथा उन्नत डाटा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र के गठन के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- समझौते के तहत, आईआईटी दिल्ली एआई एवं मशीन लर्निंग पर आधरित उन्नत एनालिटिक्स (Advance analystics) के विकास पर एनएचएआई के साथ कार्य करेगी, सिमुलेशन माडल तैयार करेगी, डाटा स्टोरेज बढ़ाएगी तथा एनएचएआई की डाटा प्रेरित निर्णय प्रक्रिया क्षमताओं को और अधिक बढ़ाएगी।

जनशिकायतों के निपटारे हेतु रक्षा मंत्रालय ने किया त्रिपक्षीय समझौता

जनशिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए रक्षा मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के साथ 4 अगस्त, 2020 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE
सत्यमेव जयते

- समझौते के तहत आईआईटी कानपुर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित करेगी, जो वेब आधारित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर रक्षा मंत्रालय से जुड़ी जन शिकायतों का पूर्व विश्लेषण कर उनका प्रभावी तरीके से निपटारा कर सके।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) जन शिकायतों को निपटाने की भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- डीएआरपीजी शिकायत निपटान के लिए रक्षा मंत्रालय से संबधित डेटा आईआईटी कानपुर को उपलब्ध कराएगा, ताकि वह उनका व्यापक विश्लेषण कर सके।

कला/संस्कृति

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सात नए सर्किल की घोषणा

संस्कृति मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल की घोषणा की।

- जबलपुर (मध्य प्रदेश), त्रिची (तमिलनाडु), झांसी और मेरठ (उत्तर प्रदेश), हम्पी (कर्नाटक), रायगंज (पश्चिम बंगाल) और राजकोट (गुजरात) को नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है। हम्पी मिनी सर्किल को पूर्ण विकसित सर्किल में बदल दिया गया है।

- नए सर्किल पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को मजबूत करेंगे।

वेब पोर्टल/ऐप

आरोग्य सेतु 'ओपन एपीआई सेवा'

आरोग्य सेतु टीम ने लोगों, व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करने के लिए 22 अगस्त, 2020 को एक नई 'ओपन एपीआई सेवा' की शुरुआत की।

- इस सेवा का फायदा भारत में 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ पंजीकृत संगठन और व्यावसायिक संस्थाएं उठा सकती हैं।
- 'ओपन एपीआई सेवा' से कोई संगठन अपने कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ता की सेहत की स्थिति का पता उनकी डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना लगाने में सक्षम होगा।

मोबाइल ऐप 'माय आईएएफ'

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में 24 अगस्त, 2020 को वायु सेना मुख्यालय 'वायु भवन' में एक मोबाइल एप्लीकेशन 'माय आईएएफ' (MY IAF) का शुभारम्भ किया।

- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डीएसी) के सहयोग से विकसित किया गया यह मोबाइल एप्लीकेशन भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में शामिल होने के इच्छुक लोगों को करियर संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करेगा।

ज्वैलर्स के लिए पंजीकरण और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने 21 अगस्त, 2020 को ज्वैलर्स के लिए पंजीकरण और नवीकरण की ऑनलाइन प्रणाली और जांच-परख एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की मान्यता और नवीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की।

- इस ऑनलाइन प्रणाली को भारतीय मानक ब्यूरो के वेब पोर्टल www.manakonline.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- उपभोक्ता मामले विभाग जल्द ही देश में सभी उत्पादों के मानकीकरण के लिए 'एक राष्ट्र, एक मानक' योजना की शुरुआत करेगा।

मोबाइल ऐप 'हरित पथ'

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), ने देशभर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप 'हरित पथ' की शुरुआत की है। हरित पथ ऐप का उद्घाटन 21 अगस्त, 2020 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया।

- इस ऐप को राजमार्ग पर पौधारोपण, प्रतिष्ठान की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रत्येक पौधे के स्थान, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव और गतिविधियों तथा उपलब्धियों की निगरानी के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
- एनएचएआई ने हाल ही में राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान 'हरित भारत संकल्प' भी शुरू किया है।

जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल 'स्वास्थ्य'

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 17 अगस्त, 2020 को जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल 'स्वास्थ्य' का शुभारंभ किया गया।

- 'स्वास्थ्य' नामक ई-पोर्टल एक ही मंच पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है। पोर्टल भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवाचारी प्रक्रियाओं, शोध रिपोर्टों, मामला अध्ययनों, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करेगा।

'सृजन' पोर्टल

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अगस्त, 2020 को 'सृजन' नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया।

- यह एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जो वेंडर को स्वादेशी वस्तुओं के लिए मंच प्रदान करता है।
- आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशी पोर्टल 'सृजन डिफेंस डॉट जीओवी डॉट आईएन' विकसित किया है, जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्ध कराना है।

सार–संक्षेप

मानव-हाथी टकराव पर 'सुरक्ष्या' नामक एक पोर्टल

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 10 अगस्त, 2020 को मानव-हाथी टकराव पर 'सुरक्ष्या' (Surakhsya) नामक एक पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया।

- रियलटाइम जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव-हाथी टकरावों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल आंकड़ा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन, और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में मदद करेगा ताकि नीति निर्माताओं को नीति निर्माण और टकराव को कम करने की कार्य योजना बनाने में मदद मिल सके। अभी पोर्टल का बीटा संस्करण डेटा परीक्षण के लिए शुरू किया जा रहा है।

माईगॉव गोवा पोर्टल

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने 4 अगस्त, 2020 को सहभागी प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए नागरिक भागीदारी मंच 'माईगॉव गोवा पोर्टल' (MyGov Goa portal) लॉन्च किया।

- माईगॉव (mygov.in), भारत सरकार का नागरिक सहभागिता और लोगों के विचार जानने (क्राउडसोर्सिंग) का प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य शासन और नीति निर्धारण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है।
- 12 राज्य पहले ही अपने माईगॉव प्लेटफार्म लॉन्च कर चुके हैं। ये राज्य हैं - महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।

आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज

माईगॉव (MyGov) ने 7 अगस्त, 2020 को 'आत्ममनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज' (Aatmanirbhar Bharat Innovation Challenge) के विजेताओं की घोषणा की।

- मनोरंजन, समाचार, गेम्स, कार्यालय, स्वास्थ्य, ई-लर्निंग, व्यवसाय, सामाजिक तथा अन्य श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की गई।
- स्वदेशी विकसित वीडियो ऐप 'चिंगारी' जो प्रतिबंधित चीनी ऐप टिकटॉक का एक प्रतिस्पर्धी है, 'सामाजिक श्रेणी' में विजेता रहा।

- भारतीय फर्म जोहो ने अपने ऐप 'जोहो इनवॉयस, बुक्स एंड एक्सपेंस' (Zoho Invoice, Books - Expense) और 'जोहो वर्कप्लेस' के साथ दो श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है, जो क्रमशः व्यवसाय और कार्यालय श्रेणी में विजेता घोषित किए गए हैं।
- मनोरंजन श्रेणी- 'कैप्शनप्लस' (CaptionPlus); ई-लर्निंग श्रेणी- डिस्प्रज (Disprz); गेम्स श्रेणी- हिटविकेट सुपरस्टार्स 3डी क्रिकेट स्ट्रेटेजी गेम; स्वास्थ्य श्रेणी- 'स्टेपसेटगो' (StepSetGo) अन्य विजेता रहे।
- विजेताओं को प्रथम पुरस्कासर के लिए 20 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कायर के लिए 15 लाख रुपये और तृतीय पुरस्कार के लिए 10 लाख रुपये दिये जाएंगे।

जीके फैक्ट

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों द्वारा पहले से ही उपयोग किए जा रहे सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान करने और अपनी श्रेणी में विश्व स्तर के ऐप्स बनाने हेतु 4 जुलाई, 2020 को प्रौद्योगिकी समुदाय के लिए 'आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज' लॉन्च किया।

एनएचएआई द्वारा एक 'वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली' विकसित

अपने कंसल्टेंट्स, ठेकेदारों और रियायत पाने वालों के लिए एक पारदर्शी और व्यापक 'प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली' स्थापित करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अगस्त 2020 में एक 'वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली' विकसित की है।

- पोर्टल एनएचएआई वेबसाइट पर 'वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली' के तहत उपलब्ध है। इस पोर्टल के तहत, वेंडर को स्व-मूल्यांकन करने और उनके द्वारा कार्यान्वित परियोजना गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।
- पोर्टल में बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर-बीओटी (टोल), बीओटी (एन्यूटी), हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल, ईपीसी कार्यों और डीपीआर कंसल्टेंट्स के तहत कार्यान्वयन की स्थिति और पूरा होने की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं को रेटिंग देने का प्रावधान है।

विविध

ट्राइफूड परियोजना

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 20 अगस्त, 2020 को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्राइफेड की 'ट्राइफूड परियोजना' वर्चुअल तरीके से लांच की।

लक्ष्यः जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित गौण वन ऊपज (minor forest produce) के बेहतर उपयोग एवं मूल्य वर्धन के जरिये जनजातीयों की आय को बढ़ाना।

- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्राइफेड द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे परियोजना के तहत दो गौण वन ऊपज तृतीयक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

- महाराष्ट्र के रायगढ़ की इकाई का उपयोग महुआ, आंवला, कस्टर्ड सेब एवं जामुन के मूल्य वर्धन के लिए किया जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की मल्टी कमोडिटी प्रोसेसिंग सेंटर का उपयोग महुआ, आंवला, शहद, काजू, हल्दी, एवं अन्य फलों तथा सब्जियों के लिए किया जाएगा।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्वर्ण जयंती

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा 28 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली में स्वर्ण जयंती वर्षगांठ समारोह मनाया गया।

- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की संस्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिये 28 अगस्त, 1970 को नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के अधिदेश के साथ की गई थी।
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक वी.एस. के कौमुदी हैं।

ग्रेट अंडमानी जनजाति

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG), ग्रेट अंडमानी जनजाति के सदस्य कोविड -19 से संक्रमित पाये गए। यह इस क्षेत्र के लुप्तप्राय PVTGs के बीच कोविड -19 संक्रमण के पहले मामलों में से एक है।

- अंडमान और निकोबार द्वीपों में छह अधिसूचित जनजातियाँ हैं। निकोबारियों को छोड़कर, बाकी पांच जनजातियाँ - ग्रेट अंडमानी, जारवा, सेंटीनलीज, ओन्गे और शोम्पेन - को PVTG के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- ग्रेट अंडमानी, जिनकी आबादी 2012 के अध्ययन अनुसार सिर्फ 51 है, आपस में जेरू बोली बोलते हैं।

जीके फैक्ट

- 75 आदिवासी समूहों को गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। PVTGs 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीपों में रहते हैं।

विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0

अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) के युवा नवाचारकर्ताओं (अन्वेषकों) के लिए 11 अगस्त, 2020 को विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 (एसईपी 2.0) का शुभारम्भ किया।

नवाचार मिशन का उद्देश्य: देश में एक मिलियन नए अन्वेषक और संभावित रोजगार प्रदाता तैयार करना।

- एसईपी 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों से परामर्श सहयोग, प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण सहयोग; यूजर फीडबैक; बौद्धिक संपदा पंजीकरण और प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करने; तथा विनिर्माण सहयोग के साथ ही बाजार में उत्पाद के लॉन्च में भी सहयोग मिलेगा। एसईपी 1.0 की शुरुआत जनवरी 2019 में हुई थी।

स्वच्छ भारत मिशन अकादमी

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने 11 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) अकादमी शुरू की।

- सप्ताह भर चले व्यवहार परिवर्तन अभियान 'गन्दगी मुक्त भारत' के हिस्से के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है।
- यह एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) आधारित ओडीएफ प्लस पर मुफ्त मोबाइल ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है। ओडीएफ प्लस स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ कार्यक्रम का विस्तार है।

'फिट इंडिया यूथ क्लब' राष्ट्र व्यापी पहल

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रत्येक नागरिक के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त, 2020 को फिट इंडिया यूथ क्लबों की राष्ट्र व्यापी पहल आरंभ की।

उद्देश्य: फिट इंडिया आंदोलन के एक हिस्से के रूप में देश भर में फिटनेस के महत्व के बारे में आम जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की शक्ति का उपयोग करना।

- इसमें स्काउट्स एवं गाइड्स, एनसीसी एवं अन्य युवा संगठनों के साथ-साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के 75 लाख स्वयंसेवक एक जिला इकाई के तत्वाधान में देश के प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में पंजीकरण करेंगे और क्लब का प्रत्येक सदस्य समुदाय के लोगों को 30 से 60 मिनट तक फिटनेस गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा।

माइक्रोवेव उपकरण 'अतुल्य'

केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 12 अगस्त, 2020 को नागपुर में 'अतुल्य' नामक एक माइक्रोवेव उपकरण लॉन्च किया।

- स्वदेश में निर्मित तथा DRDO द्वारा प्रमाणित इस उपकरण का उपयोग किसी भी 5 मीटर क्षेत्र तक के परिसर, सतहों, घर और कार्यालय के फर्नीचर, बिस्तर आदि सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है।
- केवल 3 किग्रा. वजन का यह उपकरण 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदक हीटिंग (differential heating) की मदद से कोविड-19 वायरस को विघटित कर सकता है।

अंडमान- निकोबार पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली अंडमान- निकोबार पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया।

- यह पनडुब्बी केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप (हैवलॉक), लिटल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से भी जोड़ेगी।
- लगभग 1224 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2313 किमी. लंबी यह पनडुब्बी ओएफसी केबल परियोजना संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ् सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने इस परियोजना को कार्यान्वित किया है।
- इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर, 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी।
- फाइबर लिंक के चालू होने के साथ, एयरटेल अंडमान और निकोबार में 'अल्ट्रा-फास्ट 4 जी' सेवाओं को शुरू करने वाला पहला मोबाइल ऑपरेटर भी बन गया है।

'कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग' नामक पुस्तक के ई-संस्करण का विमोचन

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त, 2020 को अपने पद पर तीन साल पूरे कर लिए हैं।

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर नई दिल्ली में 'कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग' (Connecting, Communicating, Changing) नामक पुस्तक का के ई-संस्करण का विमोचन किया। पुस्तक में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू के तीन साल के कार्यकाल का वर्णन है।

राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में, स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवाद एवं अनुभव केंद्र 'राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र' का उद्घाटन किया।

- राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (आरएसके) डिजिटल और आउटडोर प्रतिष्ठानों का एक संतुलित मिश्रण है, जो कि 2014 में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के खुले में शौच करने से लेकर 2019 में खुले में शौच से मुक्त भारत के परिवर्तनों पर नजर डालता है।
- राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पहली बार महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल, 2017 को की गई थी।
- प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता के लिए चलने वाला एक सप्ताह का विशेष अभियान 'गंदगी मुक्त भारत' का भी शुभारंभ किया।

ट्राइफेड ने लॉन्च किया वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) ने 6 अगस्त, 2020 को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर अपना वर्चुअल कार्यालय लॉन्च किया।

उद्देश्य: जनजातीय लोगों को मुख्यधारा के विकास में शामिल करने की दिशा में मिशन मोड में काम करना।

- ट्राइफेड वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क में 81 ऑनलाइन वर्कस्टेशन और 100 अतिरिक्त कवरेज वाले राज्य् एवं एजेंसी वर्कस्टेशन हैं। ये वर्कस्टेनशन देश भर में ट्राइफेड की नोडल एजेंसियों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों की मदद करेंगे।

जीके फैक्ट

- बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत ट्राइफेड की स्था पना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी। यह सभी राज्यों के आदिवासी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही है। ट्राइफेड ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ 1988 में अपना कामकाज शुरू किया था।

'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना' से जुड़े चार राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश

1 अगस्त, 2020 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए 4 और राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को भी 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना' में शामिल कर लिया है। कुल 24 राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है।

- शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जीके फैक्ट

- वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है।

भारत द्वारा मालदीव सरकार को 18 मिलियन डॉलर का ऋण

अगस्त 2020 में भारत ने मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कम्पनी - (MiFCO) में मत्स्यपालन सुविधाओं के विस्तालर के लिए मालदीव सरकार को 18 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है।

- इस परियोजना में मछलियों को जमा करने और उनके भंडारण की सुविधाओं तथा टूना मछली पकाने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेरमाल किया जाएगा।
- ये ऋण, भारत सरकार द्वारा 800 मिलियन डॉलर ऋण की पेशकश का एक हिस्साम है, जिसे 20 साल में अदा करना है, तथा इसमें पांच वर्ष के लिए छूट भी दी जाएगी।

विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 राष्ट्रीय कार्यक्रम

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 1 अगस्त, 2020 को विद्यार्थी विज्ञान मंथन, 2020-21 का शुभारंभ किया।

- विज्ञान भारती (VIBHA) और विज्ञान प्रसार की यह पहल 6वीं से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- इसे छात्र समुदाय के बीच एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उज्ज्वल छात्रों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

पहली 'व्यापार माला एक्सप्रेस'

उत्तर रेलवे ने अगस्त 2020 में दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया के लिए पहली 'व्यापार माला एक्सप्रेस' चलाई है। माल ढोने वाली इस ट्रेन ने 2360 किमी. की दूरी सिर्फ 68 घंटे में तय की है।

- व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन पंजाब के फिरोजपुर के गोनियाना से एफसीआई से गेहूं और दिल्ली के किशनगंज से छोटे व्यापारियों के चावल और दाल लेकर त्रिपुरा पहुंची।
- यह छोटे व्यापारियों को कम समय में, लागत प्रभावी, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के माध्यम से रेल द्वारा अपने माल को स्थानांतरित करने में मदद करेगा।

मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ ने 30 जुलाई, 2020 को संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का शुभारंभ किया। इस भवन का निर्माण 28.12 मिलियन डॉलर के भारतीय अनुदान से किया गया है।

- यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुईस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना है।
- भारत सरकार ने 5 परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन डॉलर का 'विशेष आर्थिक पैकेज' दिया था, जिसके अंतर्गत यह पहली परियोजना है।

चर्चित पुस्तक

- 'नेताजी - इंडियाज इंडिपेंडेंस एण्ड ब्रिटिश आर्काइव्स' (NETAJI - India's Independence and British Archives) -**डॉ. कल्याण कुमार डे**
- 'ग्रीनलाइट्स' (Greenlights) - **मैथ्यू मैक्नाघे**
- 'ब्रेकिंग थ्रू-ए मैमोयर' (Breaking Through-A Memoir) - **इशर जज अहलूवालिया**
- 'वन अरेंज्ड मर्डर' (One Arranged Murder)-**चेतन भगत**
- 'परवीन बाबी: ए लाइफ' (Parveen Babi: A Life) - **करिश्मा उपाध्याय**
- 'मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी' (Making Sense of Indian Democracy) - **योगेन्द्र यादव**
- 'अमेजिंग अयोध्या' (Amazing Ayodhya) - **नीना राय**

चर्चित दिवस

दिनांक	दिवस/सप्ताह/माह	2020 का विषय/अभियान/नारा	महत्वपूर्ण तथ्य
3 अगस्त	विश्व संस्कृत दिवस	--	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संस्कृत भाषा के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसके प्रयोग को बढ़ावा देना और भारत की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाना है।
7 अगस्त	राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	--	7 अगस्त, 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2015 को इस आंदोलन की याद में प्रति वर्ष 7 अगस्त को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनता के बीच हथकरघा उद्योग और सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
9 अगस्त	विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस	'कोविड-19 एंड इंडिजेनस पीपल्स रेजिलिएन्स' (COVID-19 and indigenous peoples' resilience)	यह दिवस दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 9 अगस्त, 1982 को जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देने के लिए 9 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है।

10 अगस्त	विश्व जैव ईंधन दिवस	'जैव ईंधन की ओर आत्मजनिर्भर भारत'	यह दिवस पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर–जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस अवसर पर 'जैव ईंधन की ओर आत्म निर्भर भारत' के विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2015 से विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहा है।
12 अगस्त	विश्व हाथी दिवस	––	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हाथी संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसे एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा पर ध्यान देने के लिए 2012 में लॉन्च किया गया था। अवैध शिकार, पर्यावास क्षति, मानव–हाथी संघर्ष और कैद में दुर्व्यवहार अफ्रीकी और एशियाई हाथियों को होने वाले प्रमुख खतरे हैं।
12 अगस्त	अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस	'वैश्विक गतिविधियों के लिए युवाओं की प्रतिबद्धता' (Youth Engagement for Global Action)	संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में युवा मामलों से संबंधित मंत्रियों के विश्व सम्मेलन द्वारा 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस घोषित करने की सिफारिश स्वीकार की थी। यह दिवस युवाओं की आवाज, उनके कार्य और पहलों को पहचान दिलाने का अवसर उपलब्ध कराता है।
19 अगस्त	विश्व मानवतावादी दिवस	'रियललाइफ हीरोज' (#RealLifeHeroes)	मानवीय कार्यों के दौरान मारे गए और घायल हुए कर्मियों (humanitarian workers) के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।
21 अगस्त	आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतरराष्ट्रीय दिवस	––	आतंकवाद के पीड़ितों के सम्मान और समर्थन के लिए और उनके मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।
21 अगस्त	विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस	––	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा उनकी सहायता करना है। 1988 में इस दिवस की शुरूआत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी।
22 अगस्त	धर्म या विश्वास आधारित हिंसा पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय स्मरण दिवस	––	पहली बार यह दिवस 2019 में मनाया गया था।
26 अगस्त	महिला समानता दिवस	––	संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 अगस्त को महिला समानता दिवस की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिवस मुख्य रूप से अमेरिका में मनाया जाता है। इसी दिन 1920 में संयुक्तो राज्यं अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया था। पहली बार इसे 1972 में मनाया गया था।
29 अगस्त	राष्ट्रीय खेल दिवस	––	हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें 'हॉकी विजार्ड' के नाम से भी जाना जाता है।
29 अगस्त	परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस	––	इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परमाणु हथियार, परीक्षण विस्फोटों प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु- हथियार-मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में से एक के रूप में उनकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरुक करना है।

पत्र–पत्रिका संपादकीय

इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों के आधार पर संपादकीय तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की राह

श्रम संबंधित संसद की स्थायी समिति चाहती है, कि सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाए। यह, वास्तव में, उचित है। सामाजिक सुरक्षा को वास्तव में सार्वभौमिक बनाने के लिए, इसे श्रम मंत्रालय और श्रम कानून के दायरे से बाहर करना होगा। यह केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस कार्य के लिए समर्पित एक एजेंसी द्वारा इसे समन्वित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सामाजिक सुरक्षा को जमीनी स्तर से फिर से तैयार करना होगा।

जाहिर है, यह एक बार में नहीं किया जा सकता है। बदलाव के दौरान मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ वृद्धिशील दृष्टिकोण अपनाना होगा। आधार और आधार से जुड़े बैंक खातों और भुगतान प्रणालियों के साथ ही, जल्द ही आधार से जुड़े स्वास्थ्य रिकॉर्ड की व्यवस्था करनी होगी, जिससे एक आवेदक की वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, दिव्यांगता के दावे की सत्यता या बेरोजगारी की स्थिति का पता करना संभव है। स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं अलग से प्रदान की जा रही हैं और इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। निराश्रितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन पहले से ही लागू है, हालांकि यह राशि बहुत कम है।

अब यह जानना आवश्यक है, कि कैसे आबादी के बड़े हिस्से को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में शामिल किया जाए। एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को अपनी कमाई का लगभग एक चौथाई हिस्सा बचाने के लिए मजबूर किया जाता है, हालांकि उस बचत का एक हिस्सा, नियोक्ता के योगदान द्वारा होता है। कई श्रमिकों के पास अनौपचारिक क्षेत्र में स्थायी नियोक्ता नहीं हैं। यदि सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक होंगे, तो अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक की कमाई के एक चौथाई हिस्से को अलग कर सेवानिवृत्ति बचत और दिव्यांगता बीमा; बेरोजगारी और स्वास्थ्य के लिए अलग-अलग रूप से व्यवस्थित करना आसान होगा, जिससे श्रमिक और नियोक्ता उच्च सकल वेतन पर सहमत होने पर मजबूर होंगे। सभी भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने के लिए, पहला कदम भारत के 6.3 करोड़ उद्यमों में से अधिकांश के लिए वस्तु और सेवा कर का विस्तार करना है। **स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स**

मूल निवासियों के लिए नौकरियां: समाधान नहीं

भारत ने दशकों से 'धरती के लाल' के तर्क के कई संस्करण देखे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की यह घोषणा कि राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए केवल मूल-निवासी ही पात्र होंगे, इस मायने में अद्वितीय नहीं हैं। यह इस बात की ओर इशारा करता है, कि अधिकतर राजनीतिक दल और राज्य अधिवासवाद (nativism) को अपनाते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री की यह घोषणा राज्य के युवाओं के लिए एक चुनावी वादा जरूर है, लेकिन वास्तव में, यह निराशा की निशानी है। महाराष्ट्र सरकार, निजी क्षेत्र में रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के उपायों पर जोर दे रहा है। हाल के वर्षों में कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में निजी और सरकारी नौकरियों में रोजगार चाहने वालों के लिए इसी तरह के विभिन्न प्रकार की अधिवास पात्रता लागू करने के कदम या तो समाप्त कर दिए गए या उनके सीमित परिणाम मिले। लेकिन ये उपाय राष्ट्रीय एकीकरण में कृत्रिम बाधाओं को बढ़ाने वाले उपाय हैं, जिसमें बाजार एकीकरण शामिल है।

फिर भी, माना जा रहा है कि क्षेत्रीय विशिष्टताएं हैं। कुछ राज्यों को सरकारी नौकरियों में नियोजित होने के लिए स्थानीय भाषा में एक निश्चित प्रवीणता की आवश्यकता होती है, जो प्रशासनिक कारणों से है। भारत के जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध है। ये भारत की कानूनी और संवैधानिक योजना में इसके उल्लेखनीय विविधता का प्रबंधन करने के लिए प्रदान किए गए अपवाद हैं। देश की बढ़ती हुई युवा आबादी के लिए रोजगार सृजन की वास्तविक चुनौती से जनता का ध्यान हटाने के लिए स्थानीय जुनून को बढ़ाना एक अलग दायरे में आता है। प्रवासी आबादी कौशल और वरीयताओं में अंतराल द्वारा तैयार बाजार की मांग को पूरा करती है। यही कारण है कि कई जगहों पर रोजगार में स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य कोटा संबंधित सरकारी आदेश और यहां तक कि कानूनों को भी लागू नहीं किया गया। प्रवासियों के कारण स्थानीय लोगों का पिछड़ना बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और अक्सर लोगों को गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया है।

भारत में एक गंभीर बेरोजगारी संकट है और इस चुनौती से मेल खाने वाले प्रयासों की अत्यधिक आवश्यकता है। अधिवासवाद समाधान का हिस्सा नहीं है। वास्तव में, यह निवेश, विकास और रोजगार सृजन के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाकर संकट को बढ़ा सकता है। **स्रोत-द हिन्दू**

कमजोर अर्थव्यवस्था हेतु सरकारी कार्रवाई की जरूरत

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार अर्थव्यवस्था की मौजूदा कमजोर स्थिति के लिए मजबूत उपायों की जरूरत है। हालांकि रिपोर्ट यह स्वीकार करती है, कि राजकोषीय बाधाएं सकल स्थिर पूंजी निर्माण के लिए बजटीय योगदान को कम

कर देंगी, लेकिन साथ ही यह भी जोर देती है कि विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ही निजी निवेश को बढ़ाने और सतत आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने का एकमात्र तरीका है। यह बिजली क्षेत्र में गड़बड़ियों के तत्काल समाधान, ऋण बाजार को जीवंत बनाने के लिए सक्रिय कदम और कारोबार की सुगमता में सुधार का आह्वान करती है। कारोबार सुगमता में सुधार के लिए, आरबीआई अप्रत्यक्ष रूप से आधिकारिक दावे को खारिज कर देता है, कि इस मोर्चे पर चीजों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है।

वित्तीय बाधाओं को पहचानते हुए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए कुछ विकल्प हैं। पहला, सार्वजनिक उद्यम और राष्ट्रीय निवेश और इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जैसे फंड अपनी निवेश भूमिका को काफी हद तक बढ़ाएं। दूसरा, राज्य के स्वामित्व वाली मौजूदा संपत्ति का मुद्रीकरण और नई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में फंडिंग। आरबीआई की रिपोर्ट विशेष रूप से इस्पात, बिजली, कोयला, भूमि और रेलवे में संपत्ति के मुद्रीकरण और बंदरगाहों के निजीकरण का सुझाव देती है। जीएसटी के अनुभव की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने और इसकी संरचना एवं कार्यान्वयन में सुधार और कर चोरी का पता लगाने के लिए इसका सुझाव अमल करने योग्य है।

निर्यात को फिर से बढ़ाने पर जोर अपरिहार्य है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर इसकी सिफारिशें रणनीतिक क्षमता के एक घटक के रूप में और तकनीकी स्वायत्तता के स्तर तक गहरी क्षमता विकसित करने की आवश्यकता के रूप में क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट करने में विफल रहती है। कुल मिलाकर, आरबीआई की रिपोर्ट, यह स्वीकार करते हुए कि मौद्रिक नीति प्रभावकारिता की अपनी सीमा है, विकास को पुनर्जीवित करने में, बजटीय व्यय तक सीमित न होकर, सरकार को उचित कार्रवाई की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देती है। बड़े निवेश अब विकास को बढ़ाएंगे और ऋण-जीडीपी अनुपात को नीचे लाएंगे। अब कार्रवाई का समय आ गया है। **स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स**

महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार

महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने का सरकार का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। वर्तमान में महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष है, विवाह की न्यूनतम आयु व्यक्तिगत कानूनों का परिणाम है, जिसमें ज्यादातर महिलाओं के लिए समान अधिकार नहीं हैं। हिंदू महिलाओं के लिए, बाल विवाह को गैरकानूनी बनाना, धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादियों के खिलाफ एक कठिन लड़ाई रही। 1860 में भारतीय दंड संहिता में 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना, लड़कियों की सहमति की न्यूनतम आयु के लिए पहला कानूनी ढांचा पेश किया गया था। 1927 में आयु की सहमति के बिल में उम्र में केवल दो साल की वृद्धि (12 साल) का कई राष्ट्रवादियों ने विरोध किया, जिन्होंने इस कदम को स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ शाही हस्तक्षेप के रूप में देखा। 1929 में, इसे महिलाओं के लिए 12 से बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया। तब से, विवाह के लिए महिलाओं के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल के मौजूदा कानून को लाने में लगभग पांच दशक लग गए।

दो महत्वपूर्ण कारण हैं, जो कानून को फिर से अद्यतन करने के लिए आवश्यक हैं। पहला, महिला स्वास्थ्य में सुधार करना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की एक-तिहाई बालिका-वधू भारत में है। जल्दी विवाह से जल्दी गर्भधारण स्वाभाविक रूप से कुपोषण, मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर से जुड़े होते हैं। यद्यपि मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है, लेकिन विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने से इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। दूसरा है संविधान के तहत महिलाओं से किया गया समानता का वादा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कानून यह अनुमान लगाए कि विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग होनी चाहिए।

सुविचारित कारणों के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने में कानून में बदलाव पर्याप्त नहीं होगा। महिलाओं के लिए शैक्षिक और रोजगार के अवसरों सहित अन्य कल्याणकारी उपायों में सुधार के बिना, शादी की उम्र में वृद्धि केवल समस्या में देरी करेगी और इसका उपाय नहीं करेगी।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

अवमानना कानून पर पुनर्विचार की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में यह टिप्पणी की थी कि उसकी सकारात्मक आलोचना की जा सकती है। बावजूद इसके वकील प्रशांत भूषण को उनके ट्वीट के लिए अवमानना का दोषी ठहराते हुए, न केवल इसने अपने पहले वर्णित गुण को कम किया है, बल्कि राई का पहाड़ बना दिया है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन ने भी न्यायाधीशों की निंदा करने वाले अपराध को 2013 में आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है।

रॉबर्ट कार्सवेल (एक पूर्व उत्तरी आयरलैंड के मुख्य न्यायाधीश) ने कहा, 'न्यायाधीशों को आलोचना को झेलने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर होना पड़ता है, भले ही वह अपमानजनक हो'। आलोचना, लोकतंत्र में, जवाबदेही के रूप में कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, पहले के आदेशों में, न्यायाधीशों की आलोचना और न्यायिक आदेशों और निर्देशों का पालन करने में विफलता के बीच, 'न्यायिक आदेशों और निर्देशों का पालन करने में विफलता' को वास्तविक अवमानना के रूप में माना गया है, क्योंकि यह सार्वजनिक न्याय का उल्लंघन है।

न्यायालय द्वारा हर आलोचना का जवाब - यहां तक कि कड़ी आलोचना का जवाब, न्यायशास्त्रीय निन्दा (jurisprudential blasphemy) के रूप में देखा जाना अति-प्रतिक्रिया के संकेत के रूप में माना जा सकता है। इससे केवल सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा कम होगी, न कि बढ़ेगी। आलोचक अपने आप ही अवमानना के लिए दोषी नहीं होते। अदालत को अपने आलोचकों के साथ दो-तरफा संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए साथ ही कम से कम इसे बंद करने के लिए सक्रिय रूप से कानून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। **स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स** ■■

समसामयिक प्रश्न

इस खंड के अंतर्गत इस माह की समसामयिक घटनाओं पर आधारित संभावित प्रश्नों को संकलित किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को समसामयिक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

1. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम 'खादी अगरबत्ती आत्म-निर्भर मिशन' को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन किसके द्वारा प्रस्तावित है?
(a) नीति आयोग
(b) वित्त मंत्रालय
(c) जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकर
(d) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

2. अगस्त 2020 में किस राज्य द्वारा एक विशिष्ट पहचान पत्र 'परिवार पहचान पत्र' (पीपीपी) लॉन्च किया गया है?
(a) हरियाणा
(b) हिमाचल प्रदेश
(c) मध्य प्रदेश
(d) गुजरात

3. अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में विश्व स्तरीय 'थेनजोल गोल्फ रिसोर्ट' परियोजना का उद्घाटन किया गया है?
(a) त्रिपुरा
(b) अरुणाचल प्रदेश
(c) मेघालय
(d) मिजोरम

4. जुलाई 2020 में किसके द्वारा भूजल के व्यावसायिक उपयोग के लिए कड़ी शर्तें लगाने का फैसला किया गया है?
(a) सुप्रीम कोर्ट
(b) दिल्ली हाई कोर्ट
(c) जल शक्ति मंत्रालय
(d) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

5. तेंदुओं के अवैध शिकार पर 'ट्रेफिक इंडिया' (TRAFFIC india) द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन के अनुसार 2015- 2019 के बीच किन दो राज्यों से सबसे ज्यादा अवैध शिकार की घटनाएं दर्ज की गई?
(a) उत्तर प्रदेश और बिहार
(b) उत्तराखंड और महाराष्ट्र
(c) हिमाचल प्रदेश और गुजरात
(d) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

6. अगस्त 2020 में किसके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन, 2020-21 का शुभारंभ किया गया?
(a) नरेंद्र मोदी
(b) डॉ. हर्षवर्धन
(c) रमेश पोखरियाल 'निशंक'
(d) संजय धोत्रे

7. विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है?
(a) 2 अगस्त (b) 3 अगस्त
(c) 4 अगस्त (d) 5 अगस्त

8. कोविड-19 महामारी से प्रभावित दबावग्रस्त कर्ज संपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंड सिफारिशों हेतु किसकी अध्यक्षता में आरबीआई ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है?
(a) दीपक पारेख (b) रजनीश कुमार
(c) के वी कामथ (d) कौशिक बसु

9. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त 2020 में अंडमान-निकोबार पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) का उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह केबल पोर्ट ब्लेयर को किस शहर से जोड़ रही है?
(a) चेन्नई (b) बेंगलुरु
(c) पारादीप (d) विशाखापत्तनम

10. अगस्त 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार किस नदी में डब्ल्यूएचओ द्वारा सूचीबद्ध महत्वपूर्ण रोगजनक पाए गए हैं?
(a) गंगा (b) गोदावरी
(c) नर्मदा (d) यमुना

11. 'कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग' (Connecting, Communicating, Changing) **नामक पुस्तक किसके कार्यकाल से संबन्धित है?**
(a) वेंकैया नायडू (b) रामनाथ कोविंद
(c) नरेंद्र मोदी (d) उर्जित पटेल

12. अगस्त 2020 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का डेटा रिकवरी सेंटर 'कृषि मेघ' लॉन्च किया गया है। इसे कहाँ स्थापित किया गया है?
(a) हैदराबाद (b) नई दिल्ली
(c) मोहाली (d) जोधपुर

13. भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को 'खाद्य प्रणाली विजन 2050 पुरस्कार' के लिए शीर्ष दस फाइनलिस्टों में चुना गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा?
(a) विश्व बैंक
(b) खाद्य एवं कृषि संगठन
(c) रॉकफेलर फाउंडेशन
(d) सतत विकास समाधान नेटवर्क

14. अगस्त 2020 में भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस नाम का एक अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) लॉन्च किया गया?
(a) मिराज (b) विराट
(c) सुमेध (d) सार्थक

15. पुस्तक 'नेताजी-इंडियाज इंडिपेंडेंस एण्ड ब्रिटिश आर्काइव्स' के लेखक कौन हैं?
(a) रामचन्द्र गुहा
(b) डॉ. कल्याण कुमार डे
(c) जसवंत राठी
(d) रीना नायर

16. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'सुरक्ष्या' (Surakhsya) नामक एक पोर्टल का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया। यह किससे संबंधित है?
(a) मानव-हाथी टकराव
(b) जलवायु परिवर्तन
(c) वनाग्नि
(d) शेरों के संरक्षण

17. अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग (ARIIA) 2020 में किस संस्थान ने 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों' की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया?
(a) आईआईटी दिल्ली
(b) आईआईटी कानपुर
(c) आईआईटी मद्रास
(d) आईआईटी बॉम्बे

18. अगस्त 2020 में किसे बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया?
(a) कुमार राजेश चंद्र
(b) राकेश अस्थाना
(c) नवनीत सिकेरा
(d) ए पी माहेश्वरी

19. अगस्त 2020 में 'सृजन' नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किसने किया?
(a) नितिन गडकरी
(b) निर्मला सीतारमण
(c) राजनाथ सिंह
(d) संजय धोत्रे

20. अगस्त 2020 में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (Virtual Private Network- VPN) प्रदाता 'सर्फशार्क' (Surfshark) द्वारा जारी 'डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020' (Digital Quality of Life Index 2020) में कौन सा देश पहले स्थान पर है?
(a) संयुक्त राज्य अमेरिका
(b) फ्रांस
(c) भारत
(d) डेनमार्क

21. चीन का मुकाबला करने के लिए 'आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल' (Supply Chain Resilience Initiative-SCRI) लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल में कौन सा देश शामिल नहीं है?
(a) भारत (b) जापान
(c) ऑस्ट्रेलिया (d) यूनाइटेड किंगडम

22. आसियान-इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक का छठा-गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
(a) मनीला (b) बैंकॉक
(c) जकार्ता (d) हनोई

23. आरबीआई द्वारा कब तक के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (NSFE) जारी की गई?
(a) वर्ष 2020-2024
(b) वर्ष 2020-2025
(c) वर्ष 2020-2026
(d) वर्ष 2020-2030

24. अगस्त 2020 में प्रोपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक (Knight Frank) द्वारा जारी 'प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही-2020' रिपोर्ट के अनुसार आलीशान आवासों की कीमत में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पर है?
(a) स्वीडन (b) मुंबई
(c) मनीला (d) टोक्यो

25. किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए एक 'शौर्य केजीसी कार्ड' (Shaurya KGC Card) लॉन्च किया है?
(a) एचडीएफसी बैंक
(b) यस बैंक
(c) एचएसबीसी बैंक
(d) करुर वैश्य बैंक

उत्तरमाला

1. (d)	2. (a)	3. (d)	4. (d)	5. (b)
6. (b)	7. (b)	8. (c)	9. (a)	10. (d)
11. (a)	12. (a)	13. (c)	14. (d)	15. (b)
16. (a)	17. (c)	18. (b)	19. (c)	20. (d)
21. (d)	22. (b)	23. (b)	24. (c)	25. (a)

संस्थान–संगठन

प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्थान - संगठन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड की शुरुआत की गई है।

वास्तुकला परिषद

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 11 अगस्त, 2020 को 'वास्तुकला शिक्षा विनियम, 2020 के न्यूनतम मानक' लॉन्च किए। ये विनियम वास्तुकला परिषद (Council of Architecture) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं।

- **वास्तुकला परिषद** एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार ने **वास्तुकार अधिनियम, 1972** के प्रावधानों के तहत किया है। यह अधिनियम वास्तुकार के पंजीकरण, शिक्षा के मानकों तथा योग्यता की मान्यता और अभ्यास के मानकों का पालन करने की व्यवस्था प्रदान करता है। वास्तुकला परिषद **वास्तुकला पंजिका को प्रबंधित करने** के अलावा पूरे भारत में **पेशे की शिक्षा** और **अभ्यास (व्यवसाय)** को **विनियमित** करने का कार्य करती है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 अगस्त, 2020 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के मुख्यालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया।

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री **मौलाना अबुल कलाम आजाद** द्वारा **1950** में की गई थी। परिषद् का उद्देश्य भारत के **विदेशी सांस्कृतिक संबंधों** से संबंधित **नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना** और उनके कार्यान्वयन में भागीदारी करना; भारत और **अन्य देशों** के बीच **सांस्कृतिक संबंधों** और **पारस्परिक समझ** को बढ़ाना और मजबूत करना; अन्य देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। **डॉ. विनय सहस्रबुद्धे** ICCR के अध्यक्ष हैं।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा 25 से 30 अगस्त, 2020 तक ऑनलाइन कार्यकारी विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- भारत सरकार ने अक्टूबर, 1936 में **कानपुर** में 'इंपीरियल इंस्टिट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी' की स्थापना की। **1957** में संस्थान का नाम बदलकर 'राष्ट्रीय शर्करा संस्थान' कर दिया गया था। संस्थान **उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,** और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। संस्थान के प्रमुख कार्य-**शर्करा रसायन विज्ञान, शर्करा प्रौद्योगिकी, शर्करा इंजीनियरिंग** और संबद्ध क्षेत्रों की सभी शाखाओं में **तकनीकी शिक्षा** और **प्रशिक्षण** प्रदान करना; सामान्य रूप से शर्करा प्रौद्योगिकी, शर्करा और गन्ना रसायन विज्ञान और शर्करा इंजीनियरिंग से संबंधित समस्याओं विशेष रूप से **शर्करा कारखानों** पर तथा **शर्करा उद्योग के उप-उत्पादों के उपयोग** पर **अनुसंधान** करना है।

भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान

26 अगस्त, 2020 को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के 'बीज पोर्टल' का एसबीआई के 'योनो कृषि ऐप' के साथ एकीकरण किया गया।

- भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान को **1967** में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने नई दिल्ली मुख्यालय में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय **बेंगलुरू** में स्थित है। संस्थान का मुख्य कार्य **फलों, सब्जियों, सजावाटी, औषधीय एवं संगधीय पादपों** तथा मशरूम जैसी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय बागवानी फसलों की उत्पादकता और उपयोग को बढ़ाने हेतु कार्यनितियां विकसित करने के लिए **मौलिक एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान** करना तथा बागवानी से संबद्ध **वैज्ञानिक सूचना के संग्रह-स्थल** के रूप में कार्य करना है। वर्ष **1999** और **2011** के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने इसे **सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार** प्रदान किया था।

भारतीय ताराभौतिकी संस्थान

भारतीय ताराभौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics-IIA) ने 12 अगस्त, 2020 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया।

- भारतीय ताराभौतिकी संस्थान देश का एक प्रमुख संस्थान है, जो **खगोल विज्ञान, ताराभौतिकी एवं संबंधित भौतिकी** में **शोधकार्य** को समर्पित है। इसका उद्गम मद्रास (चेन्नई) में 1786 में स्थापित की गई एक निजी वेधशाला से जुड़ा है। **1971** में इसने एक स्वायत्त संस्था भारतीय ताराभौतिकी संस्थान का रूप लिया। संस्थान का मुख्यालय **कोरमंगला, बेंगलुरू** में स्थित है। संस्थान की प्रमुख प्रेक्षण सुविधायें **कोडैकनाल, कावलूर, गौरीबिदनूर एवं हान्ले** में स्थापित हैं। कावलूर स्थित वेणुबप्पू वेधशाला **1960** के दशक से रात्रिकालीन खगोल की मुख्य प्रकाशिक वेधशाला रही है। यहां 2.34 मी. **वेणुबप्पू दूरदर्शी** कार्यशील है। दक्षिण पूर्व लद्दाख के हान्ले नामक स्थान में नई उच्च उत्तुंग (high altitude) भारतीय खगोल वेधशाला है, जहां वर्ष 2001 से 2 मी. व्यास का **'हिमालयन चंद्रा दूरदर्शी'** कार्यशील है। ■■

लोक सभा | राज्य सभा
प्रश्नोत्तर–सार

इस अंक में संसद के बजट सत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का तथ्य सार दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को सरकार की कार्य-योजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य-योजनाओं से अवगत कराना है।

लोक सभा

- **महिलाओं का कौशल विकासः** प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 2.0) **2016-20** कौशल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसमें **चार वर्षों** में **12,000 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ **अल्पावधि प्रशिक्षण**, पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) और विशेष परियोजना के तहत महिलाओं सहित **एक करोड़ लोगों** को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई है। पीएमकेवीवाई 2.0 योजना के तहत 17 जनवरी, 2020 तक, 31.29 लाख महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। देश भर के 15,697 औद्योगिक संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना** (सीटीएस) के तहत महिलाओं सहित उम्मीदवारों को दीर्घावधि प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- **छात्र-शिक्षक अनुपातः** UDISE 2017-18 (अनंतिम) आंकड़ों के अनुसार, **72.80%** सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और **68.29%** सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) के प्रावधानों के मानकों का पालन करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा **प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों** में क्रमशः **30:1** और **35:1** का छात्र -शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निर्धारित किया गया है। इसी तरह, **माध्यमिक स्तर** पर PTR **30:1** निर्धारित है। UDISE 2017-18 (अनंतिम) आंकड़ों के अनुसार, **प्राथमिक विद्यालयों** के लिए राष्ट्रीय स्तर पर PTR **23:1** है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए **25:1** है और माध्यमिक स्तर के लिए **26:1** है, जो निर्धारित मानकों से बेहतर है।
- **वित्तीय साक्षरता पर सर्वेक्षणः** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को छोड़कर) में अखिल भारतीय वित्तीय साक्षरता और समावेश सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के तहत, वित्तीय साक्षरता को **वित्तीय ज्ञान, वित्तीय मनोभाव (Attitude) और वित्तीय व्यवहार** जैसे तीन घटकों में मापा गया, जिनके लिए अधिकतम स्कोर क्रमशः 7, 5 और 9 हैं। **तीन घटकों** में **भारत का औसत स्कोर क्रमशः 3.7, 2.6 और 5.6** है और **वित्तीय साक्षरता** में कुल 21 के स्कोर में से 11.9 स्कोर है।

राज्य सभा

- **कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग की सफलताः पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय** द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इसकी स्वायत्त संस्था- **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियरोलॉजी (IITM) क्लाउड एयरोसोल परस्पर क्रिया और वृष्टिपात वृद्धि परीक्षण** (Cloud Aerosol Interaction and Precipitation Enhancement Eñperiment) कर रही है। इसके एक भाग के रूप में, क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता पर अध्ययन किया जा रहा है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार, लगभग **एक- तिहाई बादलों** का वृष्टिपात (precipitated) हुआ। अध्ययन क्लाउड सीडिंग विज्ञान और उसके बाद के परिणामों पर केंद्रित है।
- **केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने हेतु निर्धारित मानदंडः** प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की **धारा 2, 'कोई संरचना**, राचन या **संस्मारक या कोई स्तूप या दफनगाह, या कोई गुफा, शैल-रूपकृति, उत्कीर्ण लेख** या एकाश्मक (monolith) जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम **एक सौ वर्षों से विद्यमान** है' और जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, के रूप में पुरातत्वीय स्मारकों का मानदंड निर्धारित करती है। 'पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष (ruins or relics) है या जिनको होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान हैं' और राष्ट्रीय महत्व के हैं, को अधिनियम पुरातत्वीय स्थल और अवशेष के रूप में निर्धारित करता है। देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित **3691 स्मारक/स्थल** हैं।
- **वनों का अतिक्रमणः** अतिक्रमण सहित विभिन्न खतरों से वनों की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों की होती है। **राज्यों** और **केंद्र-शासित प्रदेशों** से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग **14.64 लाख हेक्टेयर** वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। राज्य सरकारें और केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन, अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों के साथ-साथ अतिक्रमणों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, **वन सीमाओं के सीमांकन और डिजिटलीकरण**, वन संरक्षण हेतु **अवसंरचना को सुदृढ़ करने** तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों जैसे सीमांत वन समुदायों को शामिल करने जैसे कई अन्य उपाय भी करते हैं। ■■

इन्हें भी जानें

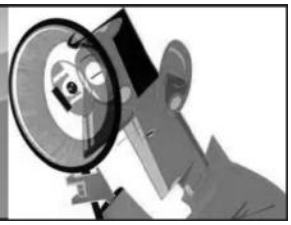

इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के शब्दों से आने वाले संभावित प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है।

- **एयर बबल्सः** केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 'एयर बबल्स' (air bubbles) शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। एयर बबल्स कोविड महामारी के दौरान नियमित उड़ानों के स्थगित होने के कारण अस्थायी वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करने का समझौता है। एयर बबल्स के तहत दो देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता करके एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है, ताकि हवाई यात्रा में कोई दिक्कत ना आए। इस समय कोरोना संकट के चलते तमाम शर्तों के साथ दो देश आपस में एयर बबल्स शुरू कर सकते हैं, जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी होता है। भारत भी कई देशों के साथ इस प्रक्रिया में जुटा है।
- **सिन टैक्सः** सिन गुड्स (Sin Goods) वे वस्तुएं होती हैं, जिन्हें समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। जैसे- शराब और तंबाकू, फास्ट फूड, कॉफी, चीनी, जुआ और पोर्नोग्राफी। इस प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर या टैक्स 'सिन टैक्स' (Sin Tax) कहलाता है। यह टैक्स लोगों को सामाजिक रूप से हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है, लेकिन वे सरकारों के लिए राजस्व का एक स्रोत भी प्रदान करते हैं।
- **साल्मोनेलाः** अगस्त 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्याज चिंता का विषय बन गया है। जिसमें लोगों में कैलिफोर्निया में उगाये गए प्याज के सेवन से 'साल्मोनेला' बैक्टीरिया का संक्रमण हुआ है। साल्मोनेला (salmonella) बैक्टीरिया जानवरों में पाया जाता है। जब यह मानव शरीर में प्रवेश करता है, तो यह साल्मोनेलोसिस (salmonellosis) का कारण बनता है। इसके अलावा लोग दूषित भोजन या दूषित पानी पीने सहित कई स्रोतों से साल्मोनेला से संक्रमित हो सकते हैं। यह संक्रमण आंत पर हमला करता है, और दस्त, पेट दर्द, बुखार, उल्टी, और मल में रक्तस्राव का कारण बन सकता है। ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक दवाओं के बिना साल्मोनेला संक्रमण से चार से सात दिनों के भीतर ठीक हो जाते हैं। पहली बार इस बैक्टीरिया को 1885 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक डॉ. डैनियल ई. साल्मन द्वारा खोजा गया था।
- **इम्यूनिटी पासपोर्टः** दुनिया भर में, देश 'इम्यूनिटी पासपोर्ट' (immunity passports) के उपयोग पर विचार कर रहे हैं। 'इम्यूनिटी पासपोर्ट' को 'जोखिम-मुक्त प्रमाण पत्र' के रूप में भी जाना जाता है। ये इस आधार पर उन लोगों को यात्रा के लिए जारी किया जाएगा, जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं तथा जिनमें एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, ऐसे प्रमाण-पत्रों के उपयोग से निरंतर संक्रमण का जोखिम हो सकता है।
- **स्पेशल फ्रन्टियर फोर्सः** लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी कब्जे को रोकने में 'स्पेशल फ्रन्टियर फोर्स' (एसएफएफ) इकाई जिसे 'विकास बटालियन' के रूप में भी जाना जाता है, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे 1962 के चीन-भारत युद्ध के तुरंत बाद स्थापित किया गया था। भारत में बसे तिब्बती शरणार्थियों (अब इसमें तिब्बतियों और गोरखाओं का मिश्रण है) को इसमें भर्ती किया जाता था। उन्हें शुरू में शत्रु इलाकों में गुप्त ऑपरेशन के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। शुरू में इसे 'इस्टेब्लिशमेंट 22' (Establishment 22) के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे खड़ा करने की जिम्मेदारी 22-माउंटेन रेजिमेंट के मेजर जनरल सुजान सिंह उबन को सौंपी गई थी। यह अब कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है। इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक (Inspector General) करता है, जो मेजर जनरल रैंक का एक सैन्य अधिकारी होता है। SFF इकाइयां सेना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे सेना के संचालन नियंत्रण में कार्य करती हैं। 1971 के युद्ध में चटगांव की पहाड़ियों को 'ऑपरेशन ईगल' के तहत सुरक्षित करने में, 1984 में 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन विजय' में एसएफएफ की अहम भूमिका थी।
- **मुलगांवकर सिद्धांतः** अधिवक्ता प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराये जाने पर, उनके वकील ने 'मुलगांवकर सिद्धांतों' का आह्वान करते हुये अदालत से संयम दिखाने का आग्रह किया। 1978 के 'एस मुलगांवकर बनाम अज्ञात' मामले में अवमानना के विषय पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। इसमें 2-1 बहुमत से, अदालत ने द इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक मुलगांवकर को अवमानना का दोषी नहीं माना था, हालांकि उसी पीठ ने कार्यवाही शुरू की थी। जस्टिस पी कैलासम और कृष्णा अय्यर ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम एच बेग के खिलाफ बहुमत प्राप्त किया था। न्यायमूर्ति अय्यर द्वारा अवमानना क्षेत्राधिकार का पालन करने में सावधानी बरतने को 'मुलगांवकर सिद्धांत' कहा जाता है। उन्होंने मीडिया को शामिल करते हुये मुक्त आलोचना के संवैधानिक मूल्यों और एक निडर न्यायालय प्रक्रिया और न्यायाधीश की आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने के पक्ष में तर्क दिया था। ■■